मेहुल चोकसी का
प्रत्यार्पण हो पाएगा?

भारतीय जनता पार्टी
क्यों मची है खलबली

सोने की हॉलमार्किंगः
व्यापारियों में हाहाकार

23 जून, 2021 40 रुपए

इंडिया टुडे

कोविड-19 टीकाकरण

90 करोड़

टीके का मुश्किल मिशन

मौजूदा दर
27 लाख प्रति दिन

लक्षित दर
84 लाख प्रति दिन

क्या भारत इस साल 31 दिसंबर तक अपने सभी वयस्क नागरिकों को टीका लगाने का लक्ष्य साध लेगा?

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

www.indiatodayhindi.in

VISIT…

सत्यमेव जयते
गुजरात सरकार

गुजरात है देश का सर्वाधिक FDI इक्विटी प्राप्त करने वाला प्रदेश 37% के साथ सर्वोच्च हिस्सेदारी

गुजरात ने ₹ 1,62,830 करोड़ के प्रवाह के साथ 279% Y-O-Y की वृद्धि दर्ज की

गुजरात ने कायम रखा है अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के सबसे पसंदीदा राज्य का दर्जा

Only Books Magazine

कोविड-19 महामारी के बावजूद गुजरात में वित्तीय वर्ष 2020- 21 में ₹ 1,62,830 करोड़ के एफडीआई का लक्ष्य प्राप्त किया है। 279% की वृद्धि के साथ यह समग्र राष्ट्रीय प्रवाह का 37% है। मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी जी के ओजस्वी और सक्रिय नेतृत्व में गुजरात में निवेश की सुविधा हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जैसे उद्योगों के अनुकूल नीति, व्यापार में सरलता और अनुपालनो में कमी। ये सभी कदम गुजरात को औद्योगिक विकास में अग्रणी बनाए रखने में सहायक साबित हुए हैं।

देश के विभिन्न राज्यों में एफडीआई इक्विटी प्रवाह का प्रतिशत

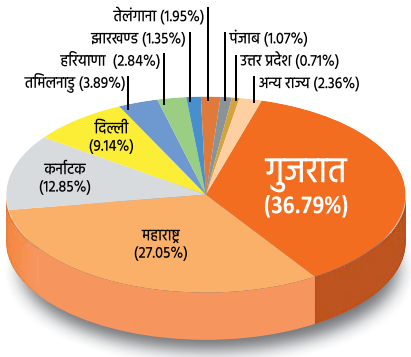

एफडीआई इक्विटी प्रवाह ₹ करोड़ में

गुजरात में निवेश

- वित्तीय वर्ष 2021 में जहां भारत के कुल एफडीआई प्रवाह में 25% की वृद्धि हुई है वहीं गुजरात में यह ₹42,976 करोड़ से बढ़कर ₹1,62,830 करोड़ हो गया है जो कि 279% वृद्धि है।
- कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 37% भागीदारी के साथ, गुजरात सभी राज्यों में से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला प्रदेश है।
- गुजरात का सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में है- 94%
- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में देश के कुल एफडीआई में से 78% हिस्सेदारी गुजरात की है।
- गुजरात में एमएसएमई सुविधा अधिनियम को संशोधित किया गया जिससे सभी नए एमएसएमई 3 वर्ष के लिए राज्य से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने से छूट दी गई है।
- अत्याधुनिक फेसलेस ऑनलाइन डेवलपमेंट प्लान अनुमोदन प्रणाली ODPS 2.0 विकसित करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
- गुजरात द्वारा विकसित सिंगल विंडो प्रणाली निवेश सुविधा पोर्टल पर 7.7 लाख से अधिक आवेदन संसाधित हो चुके हैं।
- 14 विभागों से संबंधित 40 से अधिक विभिन्न अधिनियम की समीक्षा की जा चुकी है।
- 2000 अनुपालनों को घटाया गया।

वर्तमान परिस्थितियों में सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह गुजरात के व्यापार हितेषी राज्य का परिचायक है

- श्री नितिन भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री गुजरात

प्रधान संपादक की कलम से

एक कदम आगे, दो कदम पीछे का मुहावरा देश की लड़खड़ाती टीकाकरण नीति पर फिट बैठता है. पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने टीवी संबोधन में बड़े धूम-धड़ाके से एक कदम आगे बढ़ाया. उन्होंने ऐलान किया कि अब केंद्र 75 फीसद उपलब्ध वैक्सीन खरीदेगा और राज्यों को 18 वर्ष से ऊपर वालों के टीकाकरण के लिए मुफ्त बांट देगा, जबकि बाकी 25 फीसद वैक्सीन दाम पर स्पष्ट दिशानिर्देश के साथ निजी अस्पतालों को मुहैया कराई जाएगी. यह पुरानी नीति से कुछ हद तक पलटना था. 1 मई से राज्यों को वैक्सीन निर्माताओं से सीधे हासिल करने को कहा गया था और टीकाकरण की योग्य जनता 18-44 वर्ष आयु वर्ग की बताई गई थी. इस तरह इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की जिम्मेदारी अपनी मर्जी की कीमत पर राज्यों पर डाल दी गई थी. उस वक्त दूसरी लहर का कहर चरम पर था.

इस बदलाव का फौरी नतीजा यह हुआ कि टीकाकरण मुहिम में अड़चन आ गई और वैक्सीन की किल्लत अचानक बढ़ गई. शायद प्रधानमंत्री के इस मौजूदा रोलबैक की वजह राज्य सरकारों, आम लोगों की ऊंची होती टीका-टिप्पणी और सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा है. हालांकि टीकाकरण नीति में इस उठापटक और पर्याप्त वैक्सीन आपूर्ति तय करने में केंद्र की नाकामी अपनी कीमत ले चुकी है. कोविड से 4 अप्रैल और 5 जून के बीच 1,80,000 लोगों की मौत हुई. यह संख्या पिछले साल मार्च में वायरस संक्रमण शुरू होने के बाद हुई कुल मौतों की आधी है. कोविड के दौर में देरी का मतलब मौत होता है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि कोविड-19 वायरस अब हमेशा मौजूद रहेगा, धीरे-धीरे वह कम खतरनाक जरूर होता जाएगा. हालांकि निकट भविष्य में देश अपने कवच उतारने और मई 2021 की तबाही को दोहराने का जोखिम नहीं उठा सकता, जब दूसरी लहर में देश में हर रोज औसतन 3,900 लोग मारे गए. उससे यह सीख मिली कि वायरस साल भर पहले जैसा ही खतरनाक है. वायरस के उभरते नए स्ट्रेन पर निरंतर निगरानी और राष्ट्रीय संक्रमण दर को डब्ल्यूएचओ के मानक 5 फीसद से कम तो रखना ही है. इसके अलावा, देश में कम से कम 90 फीसद आबादी को टीकाकरण के जरिए इस महामारी से उबारने की जरूरत है. फटाफट व्यापक टीकाकरण का प्रभाव अमेरिका की मिसाल में देखा जा सकता है. वहां 42 फीसद आबादी टीकाकरण के बाद सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूमने को आजाद है. वहां अपवाद बस कुछेक राज्य हैं, जहां कुछ पाबंदियां जारी हैं.

28 अप्रैल, 2021 का आवरण

भारत को बड़ी आबादी के टीकाकरण में अभी लंबी दूरी तय करनी है, जो दूसरी लहर जैसी तबाही वाली किसी और लहर से बचाव का बेहतरीन कवच है. मोदी सरकार ने शुरू में वैक्सीन के घरेलू अनुसंधानकर्ताओं और निर्माताओं को शह देकर बेहतर काम किया था. लेकिन वह अपनी आबादी को सुरक्षित करने के लिए टीका की मात्रा को लेकर भारी गफलत में रही. दूसरी लहर का अंदाजा तो वह वक्त रहते नहीं ही लगा पाई. केंद्र सरकार गर्व से यह दावा करती है कि 8 जून तक 23 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है लेकिन अफसोसनाक हकीकत यह है कि अब तक सिर्फ 3 फीसद लोगों का ही पूरी तरह टीकाकरण हो पाया है.

सरकार ने अपनी वैक्सीन नीति में तीन बड़ी गलतियां कीं. एक, उसने वैक्सीन की जरूरत पूरी करने के लिए घरेलू निर्माताओं पर भरोसा किया लेकिन कंपनियों को बड़ा ऑर्डर देने से हिचक गई, जबकि अमेरिका और यूरोप ने उचित वादा करने वाले निर्माताओं को ऑर्डर दिया. उसके बाद, उसने पहले 45 वर्ष से ऊपर के उम्र वालों के टीकाकरण पर जोर देकर सही किया, लेकिन दूसरी लहर ने बता दिया कि युवा उम्र वाले भी उतना ही खतरे में हैं. युवा लोगों के टीकाकरण की मांग बढ़ी तो केंद्र झुका मगर उसे पता था कि वैक्सीन की भारी किल्लत है. उसके बाद तो टीका लगवाने के लिए हुजूम उमड़ने लगा, किल्लत बड़े पैमाने पर हो गई और सारा टीकाकरण कार्यक्रम ध्वस्त हो गया.

अब देश में 18 वर्ष से ऊपर के अनुमानित 90 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है, लेकिन समूची वयस्क आबादी को 31 दिसंबर तक टीका लगा देने के सरकारी लक्ष्य के मद्देनजर 1.8 अरब टीके हासिल करना मुश्किल है. हाल में रोजाना टीकाकरण कुछ तेज हुआ है. महीने भर पहले औसत 15 लाख से अब औसतन 27 लाख तक पहुंचा है. इस दर से भी लक्ष्य हासिल करने में 21 महीने लगेंगे. इस साल के अंत तक 'हर्ड इम्युनिटी' हासिल करने के लिए फौरन रोजाना कम से कम 84 लाख टीकाकरण की जरूरत है. संयोग से, देश में टीकाकरण की सबसे अधिक दर 20 मई को 48.7 लाख थी.

हमारी इस हफ्ते की आवरण कथा '90 करोड़ टीके का मुश्किल मिशन' में ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर (पब्लिशिंग) राज चेंगप्पा ने उस लक्ष्य को हासिल करने के संभव तरीकों और कई अड़चनों पर गौर किया है. लगता है, केंद्र को सबक मिल गया है और अब वह लक्ष्य हासिल करने की हड़बड़ी में है. फिलहाल स्थिति यह है कि केंद्र के पास जल्दी ही रोजाना टीकाकरण दर 80 लाख हासिल करने की एक योजना है. हालांकि सब कुछ अगस्त से दिसंबर के बीच कोविशील्ड के 75 करोड़, कोवैक्सीन के 55 करोड़, बायोलॉजिकल ई के 30 करोड़ और स्पूतनिक 5 के 15 करोड़ डोज के उत्पादन और आपूर्ति पर झूल रहा है. अगर सब कुछ ठीक चला तो भारत में अगस्त से दिसंबर के बीच 1.8 अरब डोज का उत्पादन होगा.

देश में वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट से भी लोहा लेना है. वह भी एक वजह है कि पहले 100 दिनों में महज 14 करोड़ ही टीके लग सके. 18 वर्ष से ऊपर वालों को टीका लगाने की छूट के बाद टीकाकरण में कुछ तेजी आई और अगले 40 दिनों में 9.7 करोड़ लोगों को टीका लगा. सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम का अनुभव यही है कि भारत टीकाकरण की हिचकिचाहट से पार पा सकता है. एक ओर जहां 2012 में सिर्फ 60 फीसद लोग टीकाकरण को आगे आए थे, वहीं अब यह बढ़कर 90 फीसद हो गया है. हर दरवाजे पर पहुंच, जागरूकता अभियान, सुलभ टीकाकरण केंद्र और किफायती टीकों से लोगों की हिचक तोड़ने में मदद मिली है.

दूसरी लहर अब थमने लगी है तो देश को फौरन वैक्सीन आपूर्ति हासिल करने पर सारा ध्यान लगा देना चाहिए, ताकि तीसरी लहर की रोकथाम की जा सके. हम अनवरत लॉकडाउन में नहीं जी सकते, लेकिन हम समय से पहले भरोसा ओढ़ लेने की कीमत से भी वाकिफ हो चुके हैं. सिर्फ सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी और सुव्यवस्थित तथा कारगर टीकाकरण कार्यक्रम ही हमें वह चीज दिला सकता है जिसकी कामना हम वर्ष के अंत तक करना चाहते हैं: यानी कोविड-19 का वायरस भी सामान्य सर्दी-खांसी जैसा गैर-घातक बन जाए.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

Digibooks Magazine

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो: आशीष मिश्र (लखनऊ), अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
चीफ डिजाइनर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीम
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरु)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन वग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 35; अंक: 30; 17-23 जून, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरू-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

सुर्खियां

अपराध: मिशन चोकसी
पेज 6

अर्थात्: वैक्सीन के उपनिवेश
पेज 17

भीतर

फुरसत

उस्ताद राशिद खान: 'रियाज अलग है, परफॉर्मेंस अलग'
पेज 54

सवाल-जवाब/अर्जुन कपूर: 'सब कुछ करना चाहता हूं मैं'
पेज 58

फोटो इलस्ट्रेशन: बंदीप सिंह

32

आवरण कथा

अब समय से लगी होड़

सरकार को उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक तक वह देश की 90 करोड़ वयस्क आबादी को टीका लगवा देगी. क्या यह मुमकिन हो पाएगा?

Only Books Magazine

भाजपा
22 अंदरूनी खींचतान
पार्टी अपने शासन वाले प्रमुख राज्यों में असंतोष का सामना कर रही है.

कोविड-19
43 बच्चे कितने महफूज?
बच्चों में संक्रमण के जोखिम को नजरअंदाज कर दिया गया है.

कोविड अनाथ
46 सिर से उठ गया साया
युद्ध के अनाथों की तरह अब कोविड अनाथ बच्चे भी हैं.

डेटा प्राइवेसी
48 निजता की लड़ाई
नए नियमों को लेकर सोशल मीडिया मंचों और सरकार के बीच टकराव.

इंडिया टुडे
इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
9311409555 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.
या मेल करें: Moreinfo@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरण: नीलांजन दास

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी वस्तु, सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

जम्मू-कश्मीर:ग्रामीण कश्मीर में डर और मौत का साया
पेज 10

तृणमूल कांग्रेस: अभिषेक युग का सूत्रपात
पेज 12

सुर्खियां

हॉलमार्किंग खरे पर खलबली!
पेज 14

उत्तराखंड: भू-गर्भ में छुपा जल खजाना
पेज 16

एपी

मंदार देवधर

बड़ी मछली
डोमिनिका के रोसेऊ मजिस्ट्रेट अदालत में 4 जून को चोकसी (व्हीलचेयर पर); मुंबई में उसके घर के बाहर बैंकों और जांच एजेंसियों के नोटिस

अपराध

मिशन चोकसी

कैरिबियाई क्षेत्र में इस भारतीय भगोड़े ने अपहरण का सनसनीखेज दावा किया. भारत उसे इंसाफ का सामना करने के लिए वापस ला सकेगा?

संदीप उन्नीथन

भारत के सबसे बड़े बैंक घोटाले में वांछित शख्स चोटिल अवस्था में, काली आंखों और एक अविश्वसनीय कहानी के साथ दूर कैरेबियन द्वीप राष्ट्र कैसे पहुंचा? मेहुल चोकसी 2018 में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को धोखा देने के चलते वांछित होने के बाद भारत से भाग गया था, तब से उसकी कहानी में कुछ आश्चर्यजनक मोड़ आए हैं. बीते कुछ दिनों की घटनाएं काफी सनसनीखेज हैं. 62 वर्षीय चोकसी ने आरोप लगाया कि उसे एंटीगुआ द्वीप पर मिली एक महिला ने हनी ट्रैप में फंसाया, जहां वह भारत से भागने के बाद छिपा हुआ था. उसे कथित तौर पर भारतीय मूल के अज्ञात लोगों ने पीटा, प्रताड़ित किया और एक अन्य द्वीपीय राष्ट्र डोमिनिका नौका से ले गए.

यह हीरा व्यापारी कभी दक्षिण मुंबई के व्यापार की चाहत रखता था और कई अरब डॉलर के वैश्विक हीरा साम्राज्य का स्वामी था. अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है. वह एक साथ तीन देशों के कानून से जूझ रहा है—भारत, जहां सीबीआइ (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उसे वापस लाना चाहते हैं, ताकि उस पर बैंक धोखाधड़ी मामले में मुकदमा चलाया जाए;

Infinix
NOTE 10 Pro
DESIGN AWARD 2021
Infinix
OUTPLAY THE REST
Available on Flipkart
KNOW MORE →

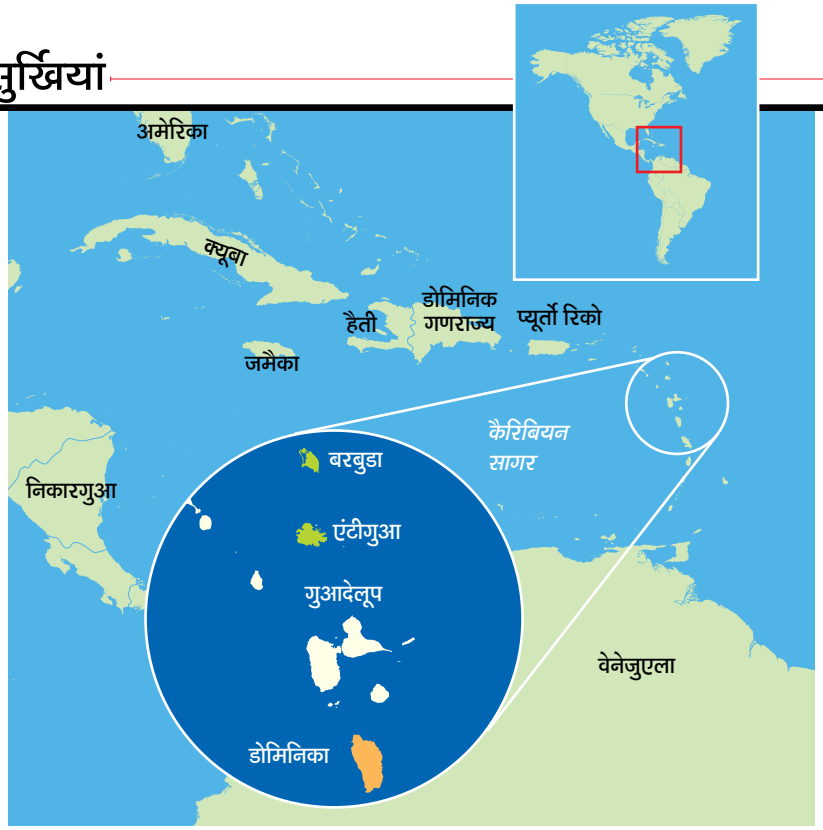

ग्राफिक: तन्मय चक्रवर्ती

रहस्यमयी महिला
चोकसी की 'दोस्त' बारबरा जाराबिक जिस पर उसके परिवार ने चोकसी के कथित अपहरण में शामिल होने का आरोप लगाया है

एंटीगुआ, जिसने हाल ही में उसके खिलाफ एक इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) का पता चलने के बाद उसकी नागरिकता छीन ली; और डोमिनिका, जो उसके अपहरण की कहानी और एंटीगुआ वापस निर्वासन की उसकी याचिका की जांच कर रही है.

बड़ा भगोड़ा कलाकार

भारत में जनवरी 2018 में, पीएनबी अधिकारियों ने पुलिस को बताया कि चोकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने उनसे 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी. यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला था. चोकसी के कथित घोटाले ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया. 20 फरवरी, 2019 को डेलावेयर में अमेरिकी दिवालियापन अदालत को सौंपी गई 132 पन्नों की एक रिपोर्ट में बताया गया कि उसने यह सब कैसे किया. मालाबार हिल पर समुद्र के सामने वाले अपने डुप्लेक्स पेंटहाउस से, मोटा हीरा व्यापारी अंतरराष्ट्रीय हीरा फर्मों का एक वैश्विक वेब चलाता था, जिसने कथित तौर पर प्रमुख बैंकरों को रिश्वत देकर बैंकों को ठग लिया था. इसमें धोखाधड़ी वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स (एलओयू) जुटाकर बैंक ऋण प्राप्त करना और गुप्त रूप से नियंत्रित शेल संस्थाओं के एक वेब के जरिए भारत में आभूषणों को 'आयात' करने का दिखावा करना शामिल था.

चोकसी का जन्म हीरा व्यापार में लगे पालनपुरी जैन व्यवसायी परिवार में हुआ था. दुनिया के कटे और तराशे हुए हीरों के निर्यात में भारत का हिस्सा 70 प्रतिशत से अधिक है. पालनपुरी जैन परिवार भारत के हीरा व्यापार को नियंत्रित करने वाले दो समुदायों में से एक है (दूसरा परिवार काठियावाड़ी पटेल है). यह समुदाय छोटा है, आपस में जुड़ा हुआ है और इसकी उत्पत्ति राजस्थान की सीमा से लगे गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर में हुई है.

जब उसकी कथित धोखाधड़ी का पता चलने वाला था, तो चोकसी 2018 की शुरुआत में अमेरिका चला गया और वहां से एंटीगुआ और बारबुडा के कैरिबियाई द्वीपों में चला गया, जहां उसने 2017 में एक निवेश योजना के जरिए नागरिकता हासिल की थी. कैरेबियन सागर के देशों में लगभग 16 छोटे राष्ट्र शामिल हैं; उनमें से कई विदेशी टैक्स हेवन और व्यापारी जहाजों के लिए सुविधा के रूप में काम करते हैं.

पर्यटन पर निर्भर द्वीपीय राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा पुदुच्चेरी से छोटा है और उसका सकल घरेलू उत्पाद 1.6 अरब डॉलर (लगभग 11,700 करोड़ रुपए) है. यह चोकसी और मोदी की कथित तौर पर पीएनबी के साथ की गई धोखाधड़ी के पैसे से भी कम है.

नागरिकता, जिसने चोकसी को 150 देशों में वीजा-मुक्त यात्रा की अनुमति दी थी, के अलावा उसके मन में यहां की नौकाओं, मैरिनों और चमचमाते समुद्र तट का आकर्षण था. इस साल 23 मई को, चोकसी जॉली हार्बर के अपने घर से गायब हो गया, जो एंटीगुआ के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में एक स्क्रीनसेवर जैसा शहर है, जिसमें कई मरीन और नौकाएं हैं. चोकसी उस शाम अकेले रात के खाने के लिए बाहर गया था और उसे अपने दोस्त बारबरा जाराबिक से मिलना था. उसकी पत्नी प्रीति को आशंका हुई और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उनके वकील का कहना है कि चोकसी ने अपनी कार में अपनी चाबी छोड़ दी, अपना पासपोर्ट या व्यक्तिगत सामान नहीं ले गया और किसी को भी नहीं बताया कि वह कहां जा रहा है. 27 मई को, वह एंटीगुआ के दक्षिण में 180 किमी दूर एक अन्य द्वीपीय राष्ट्र डोमिनिका में पाया गया.

एंटीगुआ की पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में चोकसी परिवार का आरोप है कि लंदन में रहने वाली एक हंगेरियन नागरिक जाराबिक, जो अक्सर द्वीप जाती थी, चोकसी को द्वीप पर अपने किराए के अपार्टमेंट में बुलाती थी. बयान में आरोप लगाया गया है कि वहां उन्हें कई लोगों ने अपहृत कर लिया था और एक नौका पर एक व्हीलचेयर पर ले जाया गया, पीटा गया, प्रताड़ित किया गया और एक अज्ञात भारतीय राजनेता से बात की गई. उसने अपने दो अपहरणकर्ताओं की पहचान गुरमीत सिंह और गुरजीत सिंह भंडाल के रूप में की, जो ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं. 15-17 घंटे तक नौकायन करने के बाद, उसे डोमिनिका लाया गया और एक समुद्र तट पर छोड़

दिया गया, बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

यह सब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फिल्म के एक धोखाधड़ी बी-मूवी संस्करण की तरह लग रहा था, जिसका खुलासा डोमिनिका की राजधानी रोसेउ में डोमिनिका चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल से करीब 5,500 किमी दक्षिण में हुआ, जहां चोकसी को फिलहाल रखा जा रहा है. 1960 में मोसाद के एजेंटों ने अर्जेंटीना में छिपे नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ आइकमैन का अपहरण कर लिया और उसे यात्री विमान से इस्राइल में मुकदमे का सामना करने के लिए ले आए.

29 मई को भारतीय पुलिस अधिकारी चोकसी को लेने के लिए एक चार्टर्ड जेट पर डोमिनिका पहुंचे. एक पखवाड़े बाद घटनाओं के उसके विवरण के महत्वपूर्ण हिस्सों को चुनौती दी जाने लगी है. 8 जून को जाराबिक ने टीवी साक्षात्कारों में बताया कि वह वास्तव में चोकसी से मिली थी, पर 25 मई की सुबह, लंदन जाने से कुछ घंटे पहले.

जाराबिक लंदन के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक, मेफेयर स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी, कुलिनन प्रॉपर्टीज की निदेशक है. कंपनी के दस्तावेजों में उसका पता लंदन के उत्तर-पश्चिमी उपनगर ब्रेंट दर्ज है. वे कहती हैं कि वे पिछले अगस्त में एंटीगुआ की व्यावसायिक यात्रा के दौरान चोकसी से मिली थीं. वे कहती हैं कि चोकसी ने अपना नाम 'राज' बताया था, और उसके बाद के महीनों में, उसके प्रति जुनूनी लग रहा था और कई नंबरों से उसने सैकड़ों टेक्स्ट और व्हाट्सऐप संदेशों की उस पर बौछार कर दी. उसने उसे हीरे की अंगूठियां और कंगन भी उपहार में दिए, लेकिन हीरे नकली निकले. वे कहती हैं कि चोकसी परिवार जो कहानी सामने रख रहा है, वह फर्जी है. जाराबिक ने *इंडिया टुडे टीवी* को 8 जून को दिए साक्षात्कार में पूछा, ''अगर मुझे एजेंट या अपहरणकर्ता बनना होता, तो मेरे पास उसका अपहरण करने के सैकड़ों अवसर थे. मैं जॉली हार्बर में ऐसा क्यों करूंगी?'' वैसे, इसकी संभावना है कि 30 वर्षीया जाराबिक द्वीप पर आने से पहले चोकसी को जानती होंगी. उनकी कंपनी कुलिनन के ग्राहकों में फ्रॉस्ट डायमंड्स भी था, जो चोकसी के भतीजे नीरव मोदी की कंपनी थी. मोदी मार्च 2019 में गिरफ्तारी के बाद से अब लंदन में सलाखों के पीछे है.

चोकसी के नई दिल्ली स्थित वकील विजय अग्रवाल, जाराबिक के दावों पर सवाल उठाते हैं. *इंडिया टुडे* पत्रिका को दिए एक बयान में, उन्होंने जाराबिक की गवाही में कई संयोगों की ओर इशारा किया. अग्रवाल ने कहा कि जिस दिन एंटीगुआ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और जिस दिन चोकसी की जमानत याचिका सूचीबद्ध की गई, उसी दिन वे सामने आईं. उसी दिन ब्रिटेन में स्कॉटलैंड यार्ड में चोकसी परिवार ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें चार विदेशी नागरिकों की भूमिका की जांच के लिए कहा गया. क्या यह संयोग है कि जिन लोगों की जांच की जा रही है वे सभी ब्रिटेन के निवासी हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि चोकसी ने एंटीगुआ (जिसकी भारत के साथ एक संधि है) से प्रत्यर्पण के डर से डोमिनिका (जिसकी कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है) जाने का फैसला लिया? अग्रवाल का कहना है कि अगर चोकसी (अपहरण के बारे में) झूठ बोल रहा होता, तो डोमिनिका में एक होटल में ठहरने की पूर्व व्यवस्था क्यों नहीं करता. उनका दूसरा तर्क था—चोकसी परिवार ने उसके लापता होने के दिन ही शिकायत क्यों दर्ज कराई? वह अपना पासपोर्ट एंटीगुआ में क्यों छोड़ेगा?

इन सवालों का जवाब शायद तब मिलेगा, जब एंटीगुआ और डोमिनिका की पुलिस अपने-अपने देशों की अदालतों के सामने अपने बयान पेश करेगी.

क्या भारत चौकसी को वापस ला सकेगा?

भारतीय अधिकारियों को पूरा भरोसा है कि वे चोकसी को हासिल करके रहेंगे. लेकिन कानूनी प्रक्रिया के कारण उसका निर्वासन अस्थायी रूप से रुका हुआ है. चोकसी पर डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश का आरोप लगा है, जिसके लिए उसे एंटीगुआ भेजा जा सकता है. लेकिन एक अड़चन है. उसका एंटीगुआ को निर्वासन इसलिए भी रोक दिया गया है क्योंकि एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने 6 जून को कहा कि चोकसी भारतीय नागरिक है और उसकी एंटीगुआ की नागरिकता रद्द कर दी गई है क्योंकि उसने एंटीगुआ की नागरिकता के लिए अपना आवेदन दाखिल करते समय इंटरपोल आरसीएन के बारे में झूठ बोला था.

भारत के पक्ष में एक बड़ा तथ्य यह है कि एंटीगुआ अब मानता है कि चोकसी भारतीय नागरिक है और उसे वापस भेजने की जरूरत है. **पर एक वकील संजय बद्री-महाराज का कहना है कि दोनों ही देशों का अमीर अपराधियों के प्रत्यर्पण का रिकॉर्ड खराब रहा है**

चोकसी ने एंटीगुआ के उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी है लेकिन इस मामले की सुनवाई नवंबर 2021 तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इस बीच, भारतीय अधिकारियों ने चोकसी को भारत निर्वासित करने के लिए कहा है क्योंकि वह भारतीय नागरिक है और उसके खिलाफ दिसंबर 2018 से एक आरसीएन लंबित है. इस आरसीएन की वजह से ही चोकसी को डोमिनिका में शुरू में जमानत नहीं मिली थी. भारत के पक्ष में एक बड़ा तथ्य यह है कि एंटीगुआ अब यह मानता है कि चोकसी भारतीय नागरिक है और उसे भारत वापस भेजने की जरूरत है. चोकसी की जमानत पर अगली सुनवाई 11 जून को होगी. अगर उसे जमानत दी जाती है, तो वह डोमिनिका में तब तक रहेगा जब तक कि अदालत यह तय नहीं कर लेती कि उसके साथ आखिर करना क्या है. संभावित विकल्पों में भारत निर्वासन पर विचार भी शामिल है.

वैसे, त्रिनिदाद और टोबैगो स्थित एक वकील संजय बद्री-महाराज उतने आशान्वित नहीं दिखते. वे कहते हैं, ''एंटीगुआ और डोमिनिका दोनों ही देश सफेदपोश अपराधियों को शरण देने के लिए बदनाम हैं. अदालतें कानून का पालन करेंगी और निष्पक्ष रहेंगी, लेकिन अमीर अपराधियों के प्रत्यर्पण का सरकारों का रिकॉर्ड बहुत खराब है.'' वे धोखाधड़ी के लिए वांछित त्रिनिदाद के राजनेता-व्यवसायी जैक वार्नर के मामले की ओर इशारा करते हैं, जिसे अमेरिका छह साल से अधिक समय से प्रत्यर्पित कराने का प्रयास कर रहा है.

अगर भारत चोकसी को वापस लेकर आने और उसे अदातल में खड़ा कर पाने में सफल हो जाता है, तो यह एक बड़ी घटना होगी. पूर्व आइआरएस अधिकारी और फाइनेंशियल फोरेंसिकोलॉजिस्ट अजय अग्निहोत्री कहते हैं, ''ब्रिटेन की बहुप्रचारित न्यायिक प्रणाली (जिसका इस्तेमाल कैरेबियाई देश करते हैं) में इतनी खामियां हैं कि विजय माल्या, नीरव मोदी और चोकसी जैसे जालसाजों के लिए काफी अवसर बन जाते हैं.''

2017 में दक्षिण मुंबई की एक पार्टी में चोकसी ने एक अन्य हीरा व्यापारी को अपनी सफलता और बैंक ऋण के अंतहीन चक्र से बचे रहने के 'राज' का थोड़ा सुराग दिया था. उसने कहा था, ''आपको किराए का भुगतान तब करना होता है जब आप टैक्सी से उतरते हैं... मैं कभी टैक्सी से उतरने ही वाला नहीं.'' भारतीय अधिकारियों को आखिरकार चोकसी के इस मंत्र को परखने का मौका मिल सकता है.■

जम्मू-कश्मीर

ग्रामीण कश्मीर में डर और मौत का साया

मोअज्जम मोहम्मद

जम्मू और कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को अभूतपूर्व संवैधानिक बदलावों को अंजाम देने के बाद केंद्र सरकार पारंपरिक राजनैतिक व्यवस्था को हटाकर उसकी जगह नए निर्वाचित नेता लेकर आई. भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार को लगा कि जब कामकाजी विधानसभा नहीं है, ऐसे में पारंपरिक राजनैतिक पार्टियों और उनके विधायकों को बेअसर करने का सबसे अच्छा तरीका राजकाज की स्थानीय संस्थाओं (पंचायत और नगर समितियां) पर कब्जा करना है. मगर अब दो साल बाद जमीनी लोकतंत्र उग्रवादियों और सरकारी बलों के बीच लड़ाई के निशाने पर आ गया है. चुने हुए नुमांइदों को धमकियां मिल रही हैं, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है और उन्हें अपने पैतृक गांवों से भागना पड़ रहा है.

राकेश पंडिता अक्तूबर 2018 में हुए म्यूनिसिपल चुनाव में दक्षिण कश्मीर में त्राल के निर्विरोध पार्षद चुने गए थे. भाजपा के यह पदाधिकारी स्थानीय निकाय के चेयरमैन थे, लेकिन वे श्रीनगर के अपने पैतृक गांव से 40 किमी दूर एक जगह से काम करते थे, जहां वे अस्थायी ठिकाने पर दो पुलिस वालों की हिफाजत में रहते थे. मधुमक्खी पालकों के परिवार से आने वाले पंडिता 1989 में उग्रवाद उभरने के बाद कश्मीर से भागकर जम्मू चले गए थे, पर उन्होंने अपने मुस्लिम पड़ोसियों से संपर्क बनाए रखा था. 2 जून को वे अपने मोहल्ले के एक दोस्त मुश्ताक अहमद से मिलने आए. वहीं तीन उग्रवादियों ने गोलियां दागकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. हमले में उनके दोस्त की बेटी भी घायल हो गई.

जम्मू में रह रहे राकेश के चाचा जवाहर लाल पंडिता कहते हैं कि उनका भतीजा 31 मई को कश्मीर के लिए निकला था ताकि कर्मचारियों को वक्त पर तनख्वाह देने के लिए कागजों पर दस्तखत कर सके. परिवार अभी राकेश के पिता की मौत का मातम मना ही रहा था, जिनका निधन 16 मई को हुआ था. जवाहर कहते हैं, ''गांव के हमारे पड़ोसी फोन पर उसके काम की तारीफ करते थे. राकेश को खुद पर ज्यादा भरोसा था. मैं कहता था कि थोड़ा दब-छिपकर रहे. उसे मारने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इससे न भारत को मदद मिलेगी और न पाकिस्तान को. वे (आतंकवादी) धमकी दे सकते थे, पर सीधे मार देने से तो परिवार तबाह हो गया.'' 50 वर्षीय पार्षद अपने पीछे पत्नी, 12वीं में पढ़ रहा बेटा, मां और मंदबुद्धि भाई छोड़ गए हैं. वे जम्मू के रूपनगर में रहते हैं जहां घाटी से पलायन के बाद कश्मीरी पंडितों के परिवार बड़ी तादाद में बसे हैं.

2018 में स्थानीय निकायों के चुनाव शुरू होने के बाद कश्मीर में दर्जन भर पार्षद मारे गए हैं. 30 मार्च को उत्तर कश्मीर के सोपोर में भाजपा के दो पार्षदों और एक पुलिस वाले को मार दिया गया. इन हत्याओं ने पुलिस को चुने हुए नुमांइदों की आवाजाही पर पाबंदी लगाकर उन्हें 'सुरक्षित क्षेत्रों' में रखने को मजबूर कर दिया. बीते साल से कोई दर्जन भर सदस्यों को दूर-दराज के जिलों से लाकर श्रीनगर के होटलों में रखा जाता है, क्योंकि सभी को सुरक्षा दे पाना नामुमकिन है. कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने एक एडवायजरी में 'सुरक्षा प्राप्त लोगों' से एसओपी का उल्लंघन नहीं करने का आग्रह किया और कहा कि खतरों का जमीनी आकलन करने के बाद ही आवाजाही की इजाजत दी जाती है.

स्थानीय भाजपा खामियों के लिए अब

एएनआइ

उपराज्यपाल की अगुआई वाले प्रशासन को दोषी ठहरा रही है. पार्टी के महासचिव (संगठन) अशोक कौल कहते हैं कि हमलों का मकसद राजनैतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकना है. वे कहते हैं, ''करीब 200 चुने हुए नेता बडगाम, तंगमार्ग और श्रीनगर के होटलों में कैद होकर रह गए हैं. यह पक्का करना सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षित माहौल में अपना काम कर पाएं. उन्हें चारदीवारी में बंद रखकर और किसी भी राजनैतिक गतिविधि की इजाजत नहीं देकर क्या आप कहना चाहते हैं कि आपने उग्रवाद का सफाया कर दिया है?''

सोपोर में फारूक अहमद राठेर तकलीफ के साथ कहते हैं कि 5 जून को तीन महीने बाद वे घर आए और डेढ़ घंटे से ज्यादा नहीं रह सके. डंगेरपोरा गांव के जेऐंडके अपनी पार्टी के 35 वर्षीय सरपंच कहते हैं, ''पुलिस ने जब कहा कि अब हमें लौटना होगा तो मेरा बेटा और बेटी रोने लगे. होटल के कमरे में बैठकर मैं क्या विकास कर सकता हूं? लोग शिकायतें करते हैं कि हमने इसलिए वोट दिया था कि आप वीआइपी कमरों में बैठे रहें. मगर उन्हें हमारी हालत का अंदाज ही नहीं है.''

उन्हीं की तरह घाटी में दूसरी जगहों के उनके समकक्ष कहते हैं कि वे उन्हें गाड़ी में दफ्तर ले जाते हैं और वापस ''जेल'' (जहां उन्हें ठहराया गया है) में ले आते हैं. बड़गाम की एक बीडीसी (ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल) के चेयरमैन गुलाम एच. खान कहते हैं, ''यह भारत सरकार की नाकामी है. हम मर्जी से कुछ नहीं कर सकते. हमें पुलिस के नियमों का पालन करना होता है.'' खान पहले भाजपा में थे, अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हैं.

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के महीने भर बाद सितंबर 2019 में सरपंचों का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला था. उन्होंने जम्मू और कश्मीर के नए ''नेता'' कहकर उनका अभिनंदन किया था और उनका डर दूर करते हुए सुरक्षा और बीमे का भरोसा दिलाया था. जेऐंडके सरकार ने उग्रवाद की वजह से निर्वाचित सदस्यों की मौत पर उनके नजदीकी परिजन को 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया पर राजनीति की स्थापित मुख्यधारा को बदलने का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ. यह तब भी जाहिर था जब जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के चुनाव में फारूक अब्दुल्ला की अगुआई में सात राजनैतिक पार्टियों का गठबंधन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) पूरे जम्मू-कश्मीर की 280 में से 110 सीटें जीतकर सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर उभरा (भाजपा ने 75 सीटें जीतीं, सभी जम्मू में थीं). गुलाम खान कहते हैं, ''वे (भाजपा) बाहर से लोगों को लाकर यहां (घाटी में) नेताओं की तरह रोपना चाहते थे. मगर नाकाम रहे. पारंपरिक पार्टियों के वोटों में थोड़ी कमी भले आई, पर इससे वे अप्रासंगिक नहीं हो जाएंगी.''

पंचायत सदस्यों की शीर्ष संस्था ऑल जेऐंडके पंचायत कॉन्फ्रेंस, जिसकी कमान शफीक मीर के हाथों में है, कहते हैं कि पंचायत चुनावों का मकसद ही नाकाम हो गया है. उनकी शिकायत है कि जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के सदस्यों को तो सुरक्षा मुहैया करवाई गई पर पंचायत और बीडीसी के कई सदस्य अब भी खतरों से घिरे हैं (जम्मू-कश्मीर में अब स्थानीय निकायों का तीन स्तरीय ढांचा है). पंचायत चुनावों के कुछ वक्त बाद दिसंबर 2018 में मीर 48 सरपंचों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षा मसलों और पंचायतों को ताकतवर बनाने की जरूरत के बारे बताया था. वे कहते हैं, ''मगर सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं आया. अगर चुने हुए सदस्यों को खुद अपने को सुरक्षित और महफूज रखना पड़े तो स्थानीय निकाय लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं. लोगों ने इस उम्मीद से चुनाव लड़ा था कि उन्हें ताकतवर बनाया जाएगा और सुरक्षा दी जाएगी. ऐसा नहीं हुआ.''

केंद्र ने इस वित्त वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए तय किए हैं. इसमें फिलहाल 4,817 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए हैं. मगर तीनों स्तरों के बीच अधिकारों का बंटवारा नहीं होने का असर काम पर पड़ा है. इरफान एस. पंडितपुरी बीते दिसंबर में कुपवाड़ा की 14 सदस्यीय बीडीसी में चुने गए थे, पर कहते हैं कि यह ''बेकार की कवायद'' साबित हुई. वे कहते हैं, ''ईंधन और दफ्तर के खर्चों तक के लिए मुझे अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है. यह फंदा है और यही हालात भ्रष्टाचार की तरफ ले जाएंगे.'' घाटी के कुछ हिस्सों में ऐसी कई शिकायतें हैं भी. पिछले महीने शोपियन के चित्रगाम के सरपंचों और पंचों ने राज्य के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय को रकम में घपले की लिखित शिकायत दी. उन्होंने आरोप लगाया कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस ने उनकी स्वीकृति के बगैर डिजिटल दस्तखतों से रकम निकाल ली. अगर हालात नहीं बदले तो निर्वाचित प्रशासन का आखिरी नामोनिशान भी जल्द ही मिट जाएगा. ■

आतंकी हिंसा

श्रीनगर में दिवंगत पार्षद राकेश पंडिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते भाजपा नेता. पंडिता की 3 जून को आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी

गांवों में आतंक

12

निर्वाचित पदाधिकारी मारे जा चुके हैं साल 2018 के स्थानीय निकाय चुनाव के बाद से अब तक

40,000

अनुमानित संख्या है जम्मू-कश्मीर में सरपंचों और पंचों की; 280 डीडीसी सदस्य, 310 बीडीसी प्रमुख भी हैं

4,817 करोड़ रुपए

आवंटित किए गए हैं जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण विकास के लिए चालू वित्त वर्ष में

लोकप्रिय
अप्रैल 2021 में कोलकाता के पास राजारहाट में टीएमसी की चुनावी रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी

एएनआइ

तृणमूल कांग्रेस

अभिषेक युग का सूत्रपात

रोमिता दत्ता

पांच जून को अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए. लगातार तीसरी बार भारी बहुमत से पश्चिम बंगाल की गद्दी पर आसीन हुईं ममता बनर्जी ने टीएमसी में सुधारों की शुरुआत करने और पार्टी को बंगाल से आगे ले जाने का काम अपने 33 वर्षीय भतीजे को सौंपने में कतई देर नहीं की. पूर्वोत्तर के राज्यों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से पार्टी के विस्तार की योजना 2017 में मुकुल रॉय के जाने के साथ ही ठंडे बस्ते में चली गई थी.

अब इसकी जिम्मेदारी अभिषेक की है. उनका नजरिया भी स्पष्ट है कि पार्टी केवल सांकेतिक उपस्थिति या कुछ विधानसभा या लोकसभा सीटों पर कब्जे के लिए अन्य राज्यों में नहीं, बल्कि चुनाव जीतने के लिए जाएगी. उद्देश्य देश भर में भाजपा को टक्कर देना है.

अभिषेक के बेहद करीबियों में गिने जाने वाले, टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय कहते हैं, ''अभिषेक कम बोलते हैं पर काम का बोलते हैं.'' रे कहते हैं कि उन्होंने अपने पांच दशक लंबे राजनैतिक करियर में इतनी परिपक्वता वाला युवा नेता शायद ही कभी देखा हो. उनकी तरह, टीएमसी में कई अन्य नेता अभिषेक को ममता का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं. हालांकि दीदी ने कभी भी सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है. ममता चाहती हैं कि उनकी पार्टी संगठित रूप से अपना भावी नेता चुने. वे अभिषेक को स्वाभाविक रूप से पार्टी के नेता के रूप में उभरते देखना चाहती हैं.

भाजपा उन्हें 'तृणमूल राजकुमार' कहती है, लेकिन अभिषेक पर नजर रखने वालों का कहना है कि राज्य में भगवा रथ को रोककर उन्होंने पार्टी में सम्मान अर्जित किया और विपक्ष के भ्रष्टाचार तथा जबरन वसूली के गंभीर आरोपों की हवा निकाल दी. ममता विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में ही उनका बचाव करने उतरीं, लेकिन अभिषेक न तो झुके और न ही विपक्षी हमलों से घबराकर मैदान छोड़ा. वे चुपचाप जुटे रहे.

एक नया तृणमूल

रे कहते हैं कि अभिषेक ने पार्टी की अहम संस्थाएं टीएमसी संचालन समिति और विभिन्न कोर समितियों में अपनी छाप छोड़ी है. टीएमसी अध्यक्ष के रूप में जहां ममता की बात किसी मुद्दे पर अंतिम होती है, वहीं अभिषेक ने पार्टी संगठन के पुनर्गठन की जिम्मेदारी संभाली. उन्होंने जिला पर्यवेक्षकों की व्यवस्था खत्म की, जिसे भाई-भतीजावाद और गुटबाजी को प्रोत्साहित करने वाला

पद माना जाता था. इसके बजाए, उन्होंने 21 सदस्यीय राज्य समन्वय समिति और 25 प्रवक्ता की व्यवस्था बनाकर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, जिनके ऊपर सात सदस्यीय संचालन समिति होती है. वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं के मिश्रण वाली समितियों को जिलों में पार्टी के मामलों के लिए जवाबदेह बनाया गया था. अभिषेक के चुने हुए युवा पदाधिकारियों को युवा मतदाताओं को लुभाने का काम सौंपा गया था. उनमें से टीएमसी के प्रवक्ता देबांग्शु भट्टाचार्य देव भी हैं, जिनका गाना 'खेला होबे (खेल होगा)' विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान खूब लोकप्रिय हुआ.

ममता की नई कैबिनेट में भी अभिषेक की छाप दिख रही है. पिछली सरकार में विवादास्पद और खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को बाहर किया गया. इनमें ज्योतिप्रियो मलिक, अरूप विश्वास और मंटूराम पाखीरा शामिल हैं. कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया गया और पहली बार विधायक बनीं संथाली फिल्म स्टार बीरबाहा हांसदा और पूर्व आइपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर जैसे 15 नए चेहरे शामिल किए गए.

पार्टी में 5 जून को टीएमसी में अभिषेक के वफादारों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं. राज्य महासचिव के रूप में कुणाल घोष और टीएमसी ट्रेड यूनियन विंग के राज्य अध्यक्ष के रूप में रीताब्रत भट्टाचार्य की नियुक्ति इसका उदाहरण है. अभिनेत्री से नेता बनीं सायोनी घोष की टीएमसी युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. घोष आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से हार गईं, लेकिन युवाओं की ओर से उन्हें पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका देने के अनुरोधों की बाढ़ आ गई थी.

वंशवादी राजनीति

अभिषेक एक साल से अधिक समय से 'एक नेता-एक पद' व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं. आखिरकार अब यह होने जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा, ''मैं अगले 20 वर्षों तक कोई मंत्री पद नहीं चाहता.'' भाजपा में ''वंशवादी नेताओं (शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों)'' की ओर इशारा करते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी में वंशवादी राजनीति के भाजपा के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया था. भाजपा को वंशवाद की राजनीति के खिलाफ कानून लाने की चुनौती देते हुए उन्होंने कहा था, ''मैं हटने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा. क्या बीसीसीआइ के पदाधिकारी जय शाह (केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे) ऐसा ही कह सकते हैं?''

2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 26 साल की उम्र में डायमंड हार्बर से अभिषेक जीते थे, अभिषेक ममता के भाई अमित और उनकी पत्नी लता के बेटे हैं और दीदी के आठ भतीजे-भतीजियों में सबसे बड़े हैं. पार्टी संचालन और फंड प्रबंधन में उनके बढ़ते दखल ने स्पष्ट किया कि ममता का उत्तराधिकारी कौन होगा.

2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के सांसदों की संख्या 2014 में 34 सीटों (कुल 42 में से) से गिरकर 22- भाजपा से केवल आठ अधिक—हो जाने के बाद अभिषेक नए तेवर में दिखे. विधानसभा चुनावों में सिर्फ दो साल शेष थे और उन्होंने पार्टी के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी ली. इसमें उन्होंने प्रशांत किशोर और उनकी आइ-पैक (इंडियन पॉलिटिकल ऐक्शन कमेटी) को भी शामिल किया. किशोर के फॉर्मूले का वरिष्ठ नेताओं ने कड़ा विरोध किया. लेकिन अभिषेक ने किशोर को लाने के अपने फैसले पर ममता की मुहर लगवा ली. जब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने 17 मई को नारद घोटाले में टीएमसी के चार वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया तब अभिषेक ने राजनैतिक परिपक्वता के और सबूत दिए. ममता कोलकाता में सीबीआइ कार्यालय में धरने पर बैठ गईं, जबकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाहर सड़कों पर हिंसा की. तब पार्टी काडर और समर्थकों को अभिषेक ने संभाला.

टीएमसी की शानदार जीत के बाद, भाजपा में गए बहुत से दलबदलू अपनी मूल पार्टी में लौटने की इच्छा जता चुके हैं. कभी दलबदल से चिढ़ने वाले अभिषेक ने तीखापन कम किया है. उन्होंने हाल में कहा, ''मैं भूलता नहीं, लेकिन माफ कर देता हूं.'' 2 जून को कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती मुकुल रॉय की बीमार पत्नी से मिलने वाले नेताओं में अभिषेक सबसे पहले थे. इसके बाद बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष भी अस्पताल पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रॉय को फोन करके उनकी पत्नी का हालचाल लिया.

अफवाहें हैं कि रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु टीएमसी में लौटना चाहते हैं. अभिषेक ने कहा कि उनके अस्पताल के दौरे का राजनैतिक अर्थ नहीं निकाला जाए, ''बचपन में मैंने उनका (रॉय की पत्नी) दुलार पाया है.'' इस शिष्टाचार से अभिषेक ने साबित किया कि उनके खून में दीदी का सियासी डीएनए है. ■

खास मंडली

प्रशांत किशोर

अभिषेक और 'पीके' को टीएमसी में सत्ता की जोड़ी माना जाता है. मुख्य बैठकों में शामिल होने से लेकर चुनाव में जीत के बाद ममता, अभिषेक और उनकी मां के साथ काली मंदिर जाने से लेकर 5 मई को दीदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने तक, पीके अपरिहार्य हो चुके हैं. अभिषेक के प्रमुख सलाहकारों में किशोर एक हैं. अभिषेक को भी किशोर की तरह काली टी-शर्ट और डेनिम में देखा जाता है.

कुणाल घोष

टीएमसी प्रवक्ता के रूप में घोष ने भाजपा के सघन चुनाव अभियान के खिलाफ पार्टी का बहुत अच्छे से बचाव किया. राज्य महासचिव के पद पर उनकी पदोन्नति अभिषेक के सौजन्य से हुई है. शारदा चिटफंड घोटाले में कथित भूमिका के कारण पार्टी से निलंबन और फिर जेल के बाद घोष गुमनामी में चले गए थे लेकिन अभिषेक ने 2020 में पार्टी में उन्हें फिर से बहाल किया था

सुखेंदु शेखर रे

वरिष्ठ राज्यसभा सदस्य के अभिषेक से मधुर रिश्ते हैं. लंबे समय तक दिवंगत प्रणब मुखर्जी के सहयोगी रहे रे, संसदीय मानदंडों और लोकसभा और राज्यसभा के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ हैं. वे बड़ी खामोशी से अपना काम करते हैं, जो अभिषेक को पसंद है

सुब्रत बख्शी

टीएमसी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव. अभिषेक ने उनकी जगह ली है. बख्शी उनको बचपन से जानते और पसंद करते हैं. अभिषेक राजनैतिक सलाह के लिए बख्शी से मिलते हैं

पार्थ चटर्जी

टीएमसी के दिग्गज और बंगाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्री. माना जाता है कि उन्होंने शुरुआती वर्षों में अभिषेक का मार्गदर्शन किया था

राजवंत रावत

हॉलमार्किंग

खरे पर खलबली!

शुभम शंखधर

देशभर के सर्राफा बाजारों में गहनों की खरीदारी के तौर-तरीके बदलने वाले हैं. मुमकिन है कि आप 15 जून के बाद अपने खास जौहरी की दुकान पर जाएं तो वह आपको अपना भारत मानक ब्यूरो (बीआइएस) का रजिस्ट्रेशन दिखाए, आपको मैग्नीफाइंग ग्लास देकर गहनों पर अंकित चिन्हों को देखने और समझने के लिए कहे और जब बिल बने तो गहने का वजन, शुद्धता और हॉलमार्किंग का शुल्क अलग-अलग लिखकर दे.

वैसे, सोने के गहनों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग की व्यवस्था नई नहीं है लेकिन अब यह पहले की तरह स्वैच्छिक न रहकर अनिवार्य हो गई है. मौजूदा समय में देश में सिर्फ 30 फीसद स्वर्ण आभूषण ही हॉलमार्क वाले हैं यानी गहने-जेवरों की खरीदारी मोटे तौर पर जौहरी के भरोसे चल रही थी. दरअसल, बीआइएस अप्रैल 2000 से ही सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग योजना चला रहा है, लेकिन सोने के गहनों का करीब 70 फीसद कारोबार बिना हॉलमार्क के चलता रहा है.

हॉलमार्किंग कीमती धातु (सोना-चांदी) की शुद्धता को प्रमाणित करता है. नवंबर 2019 में सरकार ने स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों पर 'हॉलमार्किंग' 15 जनवरी, 2021 से अनिवार्य किए जाने की घोषणा की. लेकिन कोविड के कारण जौहरियों की ओर से समयसीमा बढ़ाने की मांग के बाद इसे चार महीने आगे खिसकाकर 1 जून कर दिया गया था. इसके बाद 24 मई को हुई बैठक में इस व्यवस्था को फिर एक पखवाड़े के लिए मुल्तवी कर 15 जून करने का निर्णय लिया गया.

नई व्यवस्था के बाद अब जौहरी सिर्फ हॉलमार्क वाले सोने के गहने और कलाकृतियां ही बेच सकेंगे. यानी सोने के हर गहने या कलाकृति पर अब चार चिन्ह अनिवार्य रूप से गुदे होंगे. पहला बीआइएस का निशान, दूसरा सोने की शुद्धता से जुड़ा ग्रेड (14,18 या 22 कैरेट), तीसरा हॉलमार्क सेंटर का लोगो या चिन्ह और चौथा जौहरी की पहचान या नंबर.

कारोबारी क्यों परेशान?

लेकिन महामारी की चोट खाए बैठे सर्राफा कारोबारियों को हॉलमार्किंग कानून की बारीकियां डरा रही हैं. दिल्ली स्थित बुलियन ऐंड जूलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल कहते हैं, ''हॉलमार्किंग वाले गहने बेचने में किसी भी कारोबारी को कोई परेशानी नहीं. लेकिन इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जिन्हें सरकार को वापस लेना चाहिए.'' वे कुछेक का जिक्र भी करते हैं. मसलन, बिना हॉलमार्क जूलरी मिलने पर उसकी कीमत के दस गुना या पिछले साल की टर्नओवर के दस गुने तक जुर्माने का प्रावधान हटना चाहिए. सिंघल साफ कहते हैं जूलरी हॉलमार्क होने के बाद भी अगर शुद्धता संबंधी कोई शिकायत मिलती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की ओर से अधिकृत हॉलमार्क सेंटर की होनी चाहिए जिसने उस पर मुहर लगाई न कि ज्वैलर की. इसके अलावा, सिंघल के शब्दों में, ''सरकार का मकसद हॉलमार्किंग के पीछे ग्राहकों तक शुद्ध सोना पहुंचाना है,

जांच-परख
चांदनी चौक, दिल्ली में जेवर की एक दुकान में गहनों की खरीदारी. अगले पखवाड़े से गहनों पर हॉलमार्क जरूरी होने जा रहा

ऐसे में हॉलमार्किंग खुदरा बिक्री के स्तर पर अनिवार्य होनी चाहिए.'' गहनों की आपूर्ति शृंखला में मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, होलसेलर कई व्यापारी होते हैं. हर स्तर पर पंजीकरण, हॉलमार्किंग करवाने से मुश्किलें बढ़ेंगी. मान लीजिए कोई रिटेलर दिन में 10 पीस बेचता है, उसके लिए हॉलमार्किंग कराना तो आसान होगा, लेकिन एक थोक व्यापारी जिसके पास 500 पीस के सौदे वाले अगर चार व्यापारी भी आते हैं, उसके लिए हॉलमार्किंग काफी जटिल काम होगा. हर उत्पाद का यूआइडी बनाने की प्रक्रिया में हर पीस का तौल और नाम लिखकर सेंटर को भेजना होगा और तौल या नाम में कोई ऊंच-नीच हुई तो सेंटर से फिर वापस आएगी. सिंघल कहते हैं कि ''हर पीस का नाम और वजन तथा यूआइडी नंबर आदि भरने में खासा समय लगेगा, जिससे गलती की संभावना ज्यादा रहेगी. ऐसे में इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा. इसलिए नया कानून जूलरी इंडस्ट्री को स्वीकार्य नहीं है.''

इंडिया बुलियन ऐंड जूलर्स एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी और नेशनल बोर्ड की निदेशक तान्या रस्तोगी कहती हैं, ''जो कारोबारी पहले से ही केवल हॉलमार्किंग का सामान बेचते हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं होगी, पर जिनके पास पिछले साल का स्टॉक पड़ा है जो हॉलमार्किंग के स्टैंडर्ड का नहीं, उन्हें नुक्सान उठाना पड़ेगा.'' वजह: उन्हें फिर से गलाकर हॉलमार्किंग के स्टैंडर्ड की जूलरी बनानी होगी. गलाने की लागत करीब 10 फीसद बैठती है. कोविड के कारण करीब डेढ़ साल से बाजार सुचारू रूप से नहीं खुल पाए हैं. ऐसे में व्यापारियों के पास पुराना स्टॉक होना स्वाभाविक है.

चुनौतियां ये भी

गहने के निर्यात से जुड़े कारोबारी हॉलमार्किंग के दायरे में आएंगे या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. रत्न और आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) के मुताबिक, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि जो सर्राफा कारोबारी सिर्फ निर्यात लेनदेन करते हैं, वे पूरी तरह से इस आदेश के दायरे से बाहर हैं. जीजेईपीसी के चेयरमैन कोलिन शाह भंडारण से जुड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सभी निर्यातक निर्यात और घरेलू क्षेत्र दोनों के लिए साझा भंडार रखते हैं. ''सोने के आभूषणों को जब तक घरेलू बिक्री के लिए नहीं रखा जाता, उनके लिए हॉलमार्किंग प्रावधानों का पालन अनिवार्य नहीं होना चाहिए.''

जीजेईपीसी की ही स्वर्ण समिति के संयोजक के. श्रीनिवासन कहते हैं, ''भारत में हॉलमार्क वाले उत्पादों की देश के बाहर स्वीकार्यता नहीं है. ऐसे में अगर निर्यातक को पूर्ण या आंशिक रूप से हॉलमार्किंग के लिए कहा जाता है, तो इससे निर्यात कारोबार की लागत बढ़ेगी. नतीजा: रत्न और आभूषणों का निर्यात आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं रह जाएगा.''

बहरहाल, हॉलमार्किंग कानून लागू करने की तारीख करीब आने के बाद भी जौहरियों में पंजीकरण कराने का कोई उत्साह नहीं दिख रहा. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, देशभर में करीब 4 लाख जूलर हैं. इनमें से सिर्फ 35,879 को ही अब तक बीआइएस सर्टिफिकेट हासिल है. कुल 10 फीसद जौहरियों ने भी अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है. जीजेईपीसी के चेयरमैन (गुजरात क्षेत्र) दिनेश नावदिया कहते हैं, ''सरकार ने पर्याप्त समय दिया, एसोसिएशन भी सेमिनार वगैरह करवाकर अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, धीरे धीरे पंजीकरण बढ़ने लगेंगे.'' वे जीएसटी की याद दिलाते हुए कहते हैं कि शुरुआत में जीएसटी को लागू करने में भी कई तरह की दिक्कतें आई थीं लेकिन धीरे-धीरे व्यापारियों ने उसे अपना लिया और काम चल निकला. इसी तरह, उनके मुताबिक, बड़े महत्व का यह कानून जब अनिवार्य हो जाएगा तो जौहरियों के पंजीकरण में तेजी आएगी. वे कहते हैं, ''हर गली नुक्कड़ पर जब जौहरी की दुकानें खुलने लगी हैं तो यह बहुत जरूरी है कि ग्राहकों को शुद्ध माल मिले और उसकी पूरी जिम्मेदारी तथा जवाबदेही तय की जाए.''

4 लाख
कुल जौहरी हैं देशभर में

35,879
जौहरी बीआइएस से सर्टिफाइड

800 टन
सोने की देश में मौजूदा सालाना खपत, 80 फीसद सोने का इस्तेमाल गहनों के लिए

30%
आभूषण ही वर्तमान में हॉलमार्क

940 सेंटर
परख और हॉलमार्किंग के लिए देशभर में

सोर्स: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और बीआइएस

जौहरियों की दिक्कतों और दस गुना तक बेहिसाब जुर्माने से डर के अलावा नए हॉलमार्क नियम के अमल में अड़चन यह भी है कि देश में करीब 500 जिलों में हॉलमार्क सेंटर हैं ही नहीं

हालांकि इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर के प्रमुख सुधीश नांबियाथ को लगता है कि ''पूरे देश में फैले असंगठित कारोबारियों के साथ इस कानून पर अमल बड़ी चुनौती होगी.'' असंगठित कारोबारी आभूषण उद्योग में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं. इसके अलावा 32,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड जौहरियों पर सिर्फ 940 हॉलमार्क सेंटर के बुनियादी ढांचे के साथ इस कानून को लागू करना भी भारी मशक्कत वाला काम होगा. पिछले पांच वर्षों में हॉलमार्किंग सेंटरों में 25 फीसद की बढ़ोतरी हुई है. इस दौरान उनकी संख्या 454 से बढ़कर 945 हो गई, पर अभी 940 परख और हॉलमार्किंग सेंटर ही काम कर रहे हैं. वे कहते हैं, ''नई हॉलमार्किंग व्यवस्था पुरानी से बहुत अलग है. ऐसे में हॉलमार्किंग सेंटरों को ही नई व्यवस्था अपनाने में जौहरियों से ज्यादा परेशानी होने वाली है.'' एक अनुमान के मुताबिक, देश में करीब 500 ऐसे जिले हैं, जहां हॉलमार्किंग सेंटर हैं ही नहीं.

सरकार ने उचित तालमेल की पुख्ता व्यवस्था और कानून लागू करने संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया है. बीआइएस के महानिदेशक प्रमोद तिवारी इस समिति के संयोजक होंगे. इसके अलावा, उपभोक्ता मामले विभाग में अपर सचिव निधि खरे और जूलर्स एसोसिएशन और हॉलमार्किंग निकायों वगैरह के प्रतिनिधि समिति में शामिल होंगे. तो उम्मीद कीजिए कि अब सोना खरा मिलेगा. ■

उत्तराखंड

भू-गर्भ में छुपा जल खजाना

अखिलेश पांडे

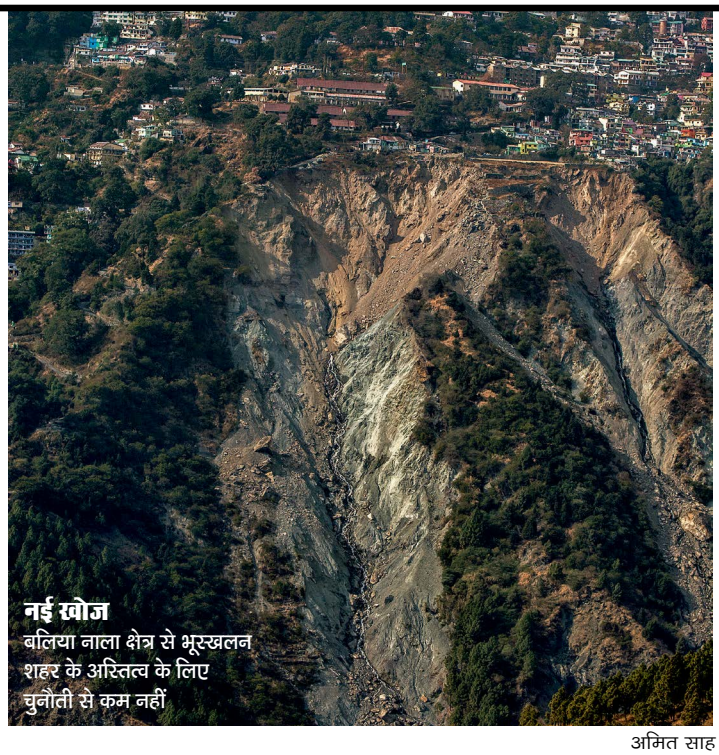

नई खोज
बलिया नाला क्षेत्र से भूस्खलन शहर के अस्तित्व के लिए चुनौती से कम नहीं

अमित साह

पर्यटकों की मुख्य आकर्षण रही झील नगरी नैनीताल की नैनी झील के मुहाने से लगभग 400 मीटर दूर जमीन के नीचे करीब 200 मीटर लंबी और पांच मीटर तक गहरी झील होने का पता लगा, जिसे अधिकारी इस नगरी की रक्षा के लिए दैवीय वरदान से कम नहीं मान रहे हैं. आइआइटी रुड़की के भू-भौतिकी विभाग के प्रोफेसर आनंद जोशी और प्रोफेसर संदीप सिंह की उत्तराखंड सिंचाई विभाग को सौंपी गई रिपोर्ट इसका खुलासा हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, बलिया नाला क्षेत्र में पानी रिसाव का करण बने जलस्रोतों के समीपवर्ती 70 मीटर इलाके के भूमिगत भू-भौतिकी सर्वे में यह झील दिखी है. मजे की बात यह भी है कि बलिया नाला इलाके में यह भूमिगत झील नैनीझील से नहीं जुड़ी है.

नैनी झील के रख-रखाव से जुड़े सिंचाई विभाग के इंजीनियर हरीश चंद्र सिंह के अनुसार इसका सीधा मतलब यह है कि इस भूमिगत झील का पानी निकाला जाए तो नैनी झील पर कोई असर नहीं पड़ेगा. भूमिगत झील के मिलने से प्रशासन और नैनीताल की बलिया नाले वाली तलहटी के भूस्खलन से परेशान निर्माण एजेंसियों को भी राहत महसूस हुई है. सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि पानी का रिसाव नैनी झील से नहीं, बल्कि भूमिगत झील से हो रहा है.

बलिया नाला क्षेत्र में 2014 और 2018 में हुए भूस्खलन से पूरे क्षेत्र को भारी नुक्सान पहुंचा था. कई घरों को खाली करवाना पड़ा था. शहीद मेजर राजेश अधिकारी इंटर कॉलेज भी भूस्खलन की चपेट में आया था. 100 साल पुराने इस स्कूल को शिफ्ट करने की नौबत आई तो सिंचाई विभाग ने रुड़की स्थित नेशनल हाइड्रोलॉजी संस्थान से इस क्षेत्र के तमाम जलस्रोतों का आइसोटोपिक परीक्षण करने का जिम्मा सौंपा, ताकि पता चले कि पानी का रिसाव नैनी झील से हो रहा है या कोई और स्रोत है. पता चला रिसाव नैनी झील से नहीं हो रहा है.

उसकी रिपोर्ट के बाद हाइकोर्ट के आदेश से समस्याग्रस्त बलिया नाला क्षेत्र के सर्वे के लिए आइआइटी रुड़की, देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट, जीएसआइ समेत कई एजेंसियों की कमेटी बनाई गई. आइआइटी रुड़की की सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि पानी का रिसाव नैनीझील से नहीं बल्कि भूमिगत झील से हो रहा है. आइआइटी रुड़की की सर्वे रिपोर्ट ने साफ किया कि जीजीआइसी से सिपाही धारा तक लगभग 200 मीटर की लंबाई में पानी का भूमिगत स्रोत है, जो झील की तरह है, जिससे बलिया नाला में प्रतिदिन लगभग 80 लाख लीटर पानी निकल रहा है, जो नैनीताल शहर के कुल पेयजल आवश्यकता के बराबर है.

इस खुलासे के बाद नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने पानी लिफ्टिंग के लिए गठित कमेटी के सदस्यों को पानी की उपलब्धता जांचने के लिए चिन्हित क्षेत्र में दो से तीन स्थानों पर बोरिंग करने के निर्देश दिए हैं. गर्ब्याल कहते हैं, ''इस मामले में भूगर्भ वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा. हम भूमिगत पानी निकालने में सफल रहे तो नगर में पेयजल की आपूर्ति के लिए नैनीताल झील पर आश्रित नहीं रहना होगा और उसके गिरते जलस्तर को बचाया जा सकेगा. इससे बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन रोकने में भी मदद मिलेगी.'' बलिया नाले में 1980 में भूस्खलन के बाद उसके ट्रीटमेंट और सर्वे का काम शुरू हुआ. लेकिन बलिया नाले में प्रवाहित स्रोतों के पानी के प्रवाह के चलते ट्रीटमेंट में सफलता नहीं मिल रही थी. अब यह साफ हो गया है कि जल प्रवाह भूमिगत झील के चलते है तो उसके ट्रीटमेंट की राह भी आसान दिखने लगी है.

जिलाधिकारी ने सिंचाई और नलकूप, जल निगम वगैरह विभागों की आठ सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो इस क्षेत्र में ट्यूबवेल स्थापित करेगी. गर्ब्याल ने बताया कि इस भूमिगत पानी को अपलिफ्ट कर नैनीताल तक पहुंचाया जाएगा. अगर यह प्रयास सफल हुआ तो प्रति वर्ष ग्रीष्मकाल में नैनी झील के कम होते जलस्तर से उसके सौंदर्य को लगने वाले ग्रहण से बचाया जा सकेगा और शहरवासियों को पेयजल किल्लत और अमूमन प्रदूषित पेयजल से लगने वाली बीमारियों से भी बचाया जा सकेगा.

खुशखबरी यह भी है कि भूमिगत झील के चलते प्रवाहित हो रहे बलिया नाला क्षेत्र के जल को नेशनल हाइड्रोलॉजिकल सर्वे संस्थान गुणवत्ता में नैनी झील से अधिक बढ़िया और प्रदूषण मुक्त पानी पा चुका है. देवभूमि को यकीनन यह दैवी वरदान है. इन स्रोतों के उचित दोहन से न केवल नैनीताल की प्यास बुझेगी बल्कि भूस्खलन का बचाव कार्य भी संभव हो जाएगा. ■

अर्थात्

वैक्सीन के उपनिवेश

अंशुमान तिवारी

बाजार और कूटनीति को मिलाना हो तो चीन शायद अपने युद्ध गुरु सुन त्जु के अलावा किसी नहीं सुनता. त्जु कहते थे कि सारी लड़ाइयां छिपकर लड़ी जाती हैं. वुहान से निकले कोविड वायरस पर दुनिया चीन को क्या सजा सुनाएगी, इसका फैसला अभी होना है लेकिन वैक्सीन राष्ट्रवाद पर चिल्ल पों के बीच चीन ने खामोशी से अपने वैक्सीन उपनिवेशवाद को पूरी दुनिया में फैला दिया है.

वैक्सीन कूटनीति की बिसात पर अब चीन के मोहरे दौड़ रहे हैं. भारतीय वैक्सीन 'डिप्लोमेसी' के ढोल तो अप्रैल में ही फूट गए थे. टीकों का निर्यात रोक दिया गया और मई के अंत से वैक्सीन के आयात की तैयारी शुरू हो गई. कोविड से अमेरिका भी इतना हैरान था कि वह गरीब दुनिया को वैक्सीन पहुंचाने की जिम्मेदारी और कूटनीति के प्रति देरी से सक्रिय हुआ. इस बीच चीन ने दुनिया के 60 से अधिक देशों में अपनी वैक्सीन पहुंचा दी. यही नहीं, जून के पहले सप्ताह तक चीन में भी प्रति 100 में से 50 लोगों को वैक्सीन मिल गई थी.

मई का महीना वैक्सीन की कूटनीति और बाजार के लिए बेहद उथल-पुथल भरा था. भारत की एकमात्र कोवैक्सीन जब मंजूरी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का दरवाजा खटखटा रही थी तब जून के पहले सप्ताह में डब्ल्यूएचओ ने चीन की दूसरी वैक्सीन साइनोवैक (साइनोफार्म पहले से मंजूर) के इमर्जेंसी इस्तेमाल मंजूरी दे दी.

वैक्सीन बाजार के लिए चीन ने बड़ी तैयारी की थी. 2020 में शोध की शुरुआत के बाद से देश के नियामक ने 6 वैक्सीन (कोई विदेशी भागीदारी नहीं) उपयोग के लिए मंजूर की जबकि 49 वैक्सीन पर काम चल रहा है (वैक्सीन ग्लोबल डेटाबेस और *नेचर*). यानी अमेरिका (66 पर परीक्षण—ट्रैक वैक्सीन ओआरजी) के बाद अब चीन दूसरा सबसे बड़ा वैक्सीन आविष्कारक है, जर्मनी अपनी दिग्गज कंपनियों (बायोएनटेक और क्योरवैक) के बावजूद तीसरे नंबर पर है. यूके और पीछे है.

वुहान से वायरस के प्रसार के जिम्मेदार चीन ने अपनी वैक्सीन पर दुनिया को राजी कैसे किया, यह बड़ा रहस्य है. चीन की पांच प्रमुख वैक्सीन (उपयोग के लिए स्वीकृत) के तीसरे चरण के ट्रायल मेक्सिको, अर्जेंटीना, चिली, पेरु, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, रूस जैसे करीब एक दर्जन देशों में हुए यानी दुनिया की सभी नस्लों और भूगोलों में वैक्सीन जांची गई. इस साल 25 अप्रैल तक 41.5 करोड़ खुराकों के साथ चीन दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक (27 करोड़ अमेरिका, 22 करोड़ ईयू, 19.6 करोड़ भारत) बन गया था.

चीन ने बड़ी खामोशी से अपने वैक्सीन उपनिवेशवाद को पूरी दुनिया में फैला दिया है

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और बहरीन ने चीन की वैक्सीन को बीते दिसंबर में ही मंजूर कर दिया था, अलबत्ता कूटनीति की बिसात पर चीन ने निर्णायक चाल इस साल मार्च में चली. विश्वव्यापी परीक्षण और भरपूर उत्पादन क्षमता के साथ चीन को यह पता था कि कोविड की मारा-मारी के बीच कोई ग्लोबल कंपनी तीसरी दुनिया के मुल्कों को वैक्सीन नहीं देने वाली.

अप्रैल में भारत में वैक्सीन की कमी और निर्यात पर रोक के बाद वैक्सीन समूह (कोवैक्स) की आपूर्ति सीमित हो गई. फाइजर से पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी. जॉनसन और मॉडर्ना इस कार्यक्रम में देरी से शामिल हुए. इस कार्यक्रम के तहत लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के कम आय वाले देशों को 2021 के अंत तक दो अरब खुराकें दी जानी थीं. इन देशों का अब चीन ही सहारा था.

विश्वास करना मुश्किल है कि जिस चीन को कोविड की महामारी पहला जिम्मेदार माना जा रहा है, उसकी वैक्सीन पूर्वी यूरोप के पांच, एशिया के 10, लैटिन अमेरिका के 10, पश्चिम एशिया के तीन और अफ्रीका के 12 देशों तक पहुंच गई है. 69 देशों को वैक्सीन दान में दी गई है, 60 देशों में चीनी वैक्सीन प्रयोग के लिए मंजूर हैं और 43 देशों को निर्यात हो रही है. संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को भी चीन की वैक्सीन मिली है.

ग्लोबल फार्मा उद्योग इस पैंतरे से लड़खड़ा गया है. बाजार की गरज है कि गलाकाट होड़ वाले फार्मा उद्योग में मर्क, जॉनसन के लिए, लंदन की जीएसके, स्विस नोवार्टिस के लिए और फ्रांस की सनोफी जर्मन बायोएनटेक के लिए वैक्सीन बना रही है, ताकि अमीर बाजारों को सुरक्षति करने के बाद तीसरी दुनिया के बाजारों में पहुंचा जा सके. लेकिन अब वहां चीन पहुंच गया है.

कोविड से पहले तक वैक्सीन बनाने वाली शीर्ष दस कंपनियों में चीन की एक कंपनी थी. अब अमेरिका और यूके से उत्पादन के केवल एक से तीन फीसद निर्यात के मुकाबले चीन कोविड वैक्सीन उत्पादन का आधा हिस्सा निर्यात कर रहा है. इधर, कोविड से पहले तक दुनिया की 60 प्रतिशत वैक्सीन आपूर्ति करने वाला भारत अपने ही लिए वैक्सीन के लिए दुनिया में भटक रहा है.

वैक्सीन उद्योग के तंबू में तो नया ऊंट घुस ही गया है, कूटनीति भी दिलचस्प दुविधा में है कि वुहान से निकली तबाही पर चीन से हिसाब मांगा जाए या उसके वैक्सीन उपनिवेशवाद को गले लगा लिया जाए.

ज्ञान और रणनीति का चरम, संघर्ष की संभावना ही खत्म कर देता है—सुन त्जु

@anshuman1tiwari

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

मुख्यमंत्री खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा राज्य में जन स्वास्थ्य और कल्याण सर्वोपरि

देश के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक, हरियाणा विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में निरंतर विकास और उन्नति के चलते देश के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरक पथ प्रदर्शक के रूप में उभर रहा है।

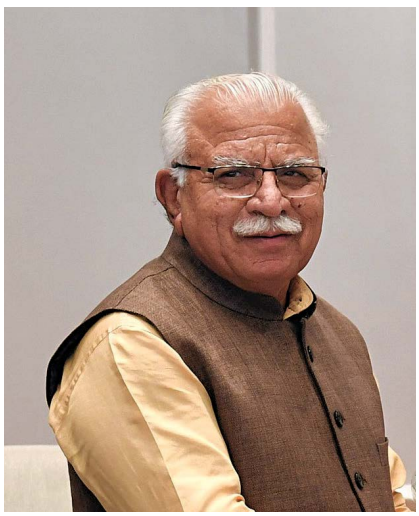

Manohar Lal Khattar
Chief minister of Haryana

कोविड महामारी के इस विकट स्वास्थ्य संकट से जूझते विश्व के सभी नेता आज विकास और प्रगति की अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हैं। इस विषद परिदृश्य के बावजूद हरियाणा राज्य आज भी अपनी उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के साथ वर्तमान परिस्थियों का सामना करने के साथ साथ अपनी बुनियादी स्वास्थ्य संरचनाओं में निरंतर और व्यवस्थित रूप से बढोतरी भी कर रहा है।

"हरियाणा ने हमेशा अपने निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण पर अत्यधिक ध्यान दिया है। राज्य निवासियों के लिए दीर्घकालीन स्वास्थ्य और समृद्धि सुनिश्चित करने के प्रति हम सदैव कार्यरत रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को सुदृढ करने से लेकर

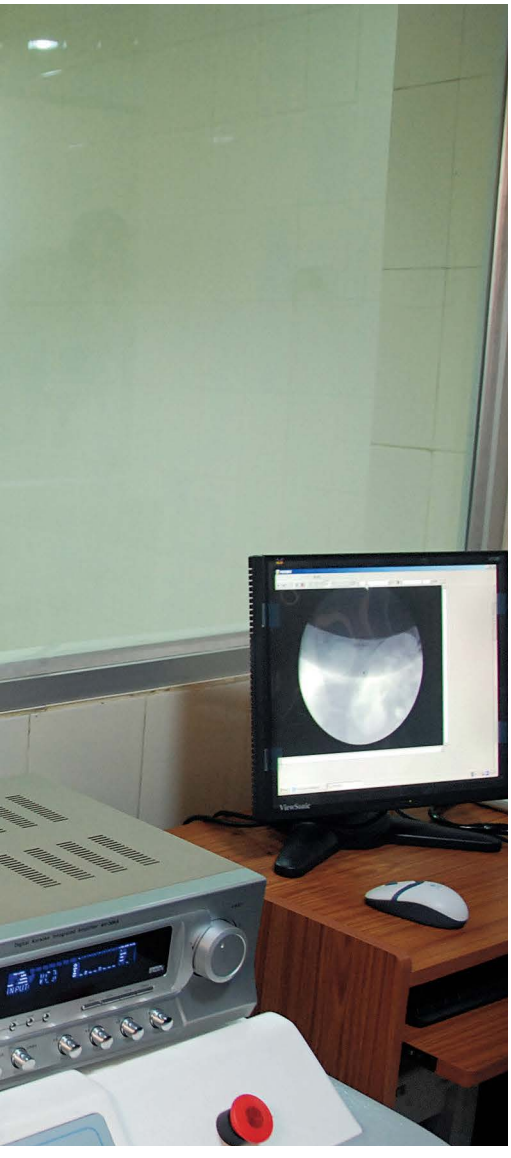

चिकित्सा संबंधी आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति तक हमने अपने नागरिकों के लिए सर्वोत्तम सुविधायें सुनिश्चित करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है" मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए कई कदम उठाए हैं।

महामारी का प्रभावी प्रबंधन

हाल ही में महामारी का प्रभावी ढंग से सामना कर पाने और उससे संबंधित आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा संरचना का विस्तार कर पाने में सक्षम हरियाणा को अग्रणी राज्यों में पाया गया।

इसी दौरान राज्य सरकार ने हरियाणा सहायक एप्लिकेशन की आधारशिला रखी, जो इन अप्रत्याशित और कठिन परिस्थितियों में राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक ही स्थान पर एक ही बार में सहायता उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य करती है। यह एप्लिकेशन हरियाणा कोविड–19 डैशबोर्ड के द्वारा प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध करा कर नागरिकों को वर्तमान कोरोनावायरस के प्रकोप से लड़ने में मदद करती है। उनके स्थान के आस पास संक्रमण के पुष्टि किए गए मामलों की जानकारी से लेकर निकटतम कोविड नामित अस्पतालों और सरकार द्वारा अनुमोदित आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के पते तक की सभी जानकारी उपयोगकर्ता को इस एप्लिकेशन के सुलभ हो जाती है।

हरियाणा में सभी कोविड–19 रोगियों को मुफ्त इलाज और दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रोगियों को किसी भी प्रकार के वित्तीय शोषण से बचाने के लिए सरकार ने हरियाणा के निजी अस्पतालों में भी कोविड के इलाज के व्यय के लिए एक सीमा निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों

में, दो डायलिसिस मशीनें कोविड–19 रोगियों के लिए आरक्षित की गई हैं और 408 एम्बुलेंस विषेश रूप से कोविड रोगियों के लिए सुलभ कराई गई हैं।

"यह हमारा दृढ़ विश्वास है कि कोविड के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए परीक्षण, अलगाव और उपचार का कठोर पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने संक्रमण परीक्षण का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 27 नई परीक्षण प्रयोगशालाओं की शुरुआत की है। इनमें 19 सरकारी और 8 निजी परीक्षण प्रयोगशालाएँ शामिल हैं," मुख्यमंत्री खट्टर ने सूचित किया। उन्होंने यह भी बताया कि इस आपदा से निपटने के लि, 12 मेडिकल मोबाइल इकाइयाँ भी क्रियान्वित की गई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि "इस संकट की घड़ी में अग्रिम पंक्ति के चिकित्सा कर्मियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों को मान्यता देने के लिए हमने उन सभी कर्मियों के लिए एक निर्धारित अनुग्रह राशि प्रदान करने का निर्णय भी लिया है।"

कोविड–19 के आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाले फ्रंटलाइन चिकित्सा कर्मियों, आई. सी. यू. लैब में काम करने वाले कर्मियों और निजी प्रेक्टिस वालें डॉक्टरों के लिए 50 लाख रुपये, नर्सों के लिए 30 लाख रुपये, चिकित्सा संबंधी सेवाओं में अनिरिक्त कर्मियों के लिए 20 लाख रुपये, और अन्य चिकित्सा सहायी सेवाओं में कार्यरत कर्मियों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और पैरा मेडिकल कर्मियों के वेतन को दोगुना करने का भी निर्णय लिया है।

एक दूरदर्शी – दृष्टिकोण

हरियाणा में एक कोविड रोगी की केवल आर. टी. पी. सी. आर. रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही इलाज नहीं रुक जाता है। सरकार का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक रोगी के शारीरिक और मानसिक आरोग्य के लिए बीमारी के बाद की देखभाल भी समान रूप से अनिवार्य है। इसलिए, राज्य सरकार ने रोहतक में एक पोस्ट कोविड उपचार एवं अनुसंधान केन्द्र की भी स्थापना की है। इस केन्द्र का उद्देश्य कोविड की बीमारी के बाद के उपचारों और सावधानियों के बारे में उपयुक्त जानकारी और सहायता प्रदान करना है, जिन्हें प्रत्येक रोगी को ध्यान में रखना चाहिए।

सभी के लिए बेहतरी सुनिश्चित करने की विचारधारा के साथ सामंजस्य बिठाते हुए सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकूला और करनाल सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्लाज्मा बैंक स्थापित किए हैं, जहां ठीक हो चुके मरीज अपना प्लाज्मा दान कर सकते हैं। अब तक 5019 मरीजों द्वारा दान किए गए प्लाज्मा के द्वारा हरियाणा में लगभग 3262 मरीजों की जान बचाने में सफलता मिली है।

इतना ही नहीं, सरकार अपने नागरिकों के लिए समयोचित टीकाकरण सुनिश्चित करने के दूरदर्शी दृष्टिकोण के प्रति भी सजग और सक्रिय है।

मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया "हम हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में पात्र नागरिकों का निशुल्क टीकाकरण कर रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत अब तक हमने राज्य में 18,68,130 से अधिक निवासियों का टीकाकरण पूरा कर लिया है। वर्तमान में,

हरियाणा में 386 सरकारी अस्पतालों और आयुष्मान भारत केंद्रों पर टीकाकरण सेवायें उपलब्ध हैं।"

निरंतर अद्यतन, एक सामयिक अनिवार्यता

जबकि इस वैश्विक आपदा को देश में स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थितियां प्रज्वलित करने के लिए अनुकूल सुर्खियों के रूप में भी देखा जा रहा है, हरियाणा सरकार का मानना है कि इस परिदृश्य में किसी भी अन्य बीमारी के सुचारू उपचार की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए, सरकार राज्य में स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के अन्य पहलुओं पर अविभाजित ध्यान बनाये हुए है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत राज्य की स्वास्थ्य सोसायटी की 8वीं शासकीय निकाय बैठक में यह पता चला कि एनीमिया मुक्त भारत (ए.एम.बी.) सूची में हरियाणा का प्रदर्शन देश के 29 राज्यों में से 46–7 सूचकांक के साथ सबसे अच्छा रहा है। हरियाणा राज्य वर्ष 2019–20 में ही एनीमिया के विरुद्ध 93 प्रतिशत टीकाकरण कर पाने में सफल रहा था।

ऐसे ही एक अन्य दूरदर्शी प्रयास के चलते राज्य सरकार सभी पीड़ितों को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की दवाएं निशुल्क उपलब्ध करवा रही है।

गर्भवती माताओं और शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही पंचकूला, पानीपत और नलहर में तीन नल महिला और शिशु अस्पतालों का उद्घाटन किया जाएगा।

तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल प्रतिमानों के साथ चलते हुए, सरकार ने मुफ्त टेली–परामर्श के लिए 'ई–संजीवनी ओ.पी.डी.' आवेदन प्रस्तुत किया है। इस एप्लिकेशन के माध्यम से विभिन्न रोगों से पीड़ित 'ई–संजीवनी' ऐप पर अपना पंजीकरण करवा कर निशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न जिला नागरिक अस्पतालों और तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने भी मरीजों के इलाज के लिए टेली कंसल्टिग सेवायें प्रारंभ की हैं।

डेंगू रोगियों के लिए हरियाणा ने पूरे राज्य में एक मुफ्त सिंगल डोनर प्लेटलेट्स (एस.डी.पी.) सुविधा की शुरूआत की है। ऐसी पहल करने वाला हरियाणा उत्तर भारत में पहला राज्य है। हरियाणा में डेंगू की जांच भी सरकारी प्रयोगशालाओं में निःशुल्क की जा रही है।

हरियाणा में स्वास्थ्य सेवा कार्यों में तेजी लाने के लिए, 956 डॉक्टर और 206 नए आयुश चिकित्सा प्रतिनिधि राज्य के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शामिल हुए हैं। अंबाला कैंट, रेवाड़ी और पानीपत के अस्पतालों में मरीजों की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।

सरकार ने गुरुग्राम में अपनी तरह के पहले शीतला माता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला भी रखी है। राज्य गांव मूनक (करनाल), गांव खंबी (पलवल), गांव नारायणा (करनाल) और गांव कोयल (जींद) में सबसे प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए भी तैयार है।

"स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र हमारे प्रशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बना रहा है। हम वास्तव में देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को महत्व देते हैं और उनके कल्याण के लिए अपने प्रयासों को बिना शर्त समर्पित करने का प्रयास करते हैं," सीएम खट्टर ने पुष्टि की।

हरियाणा अपने निवासियों के लिए प्रभावी और कुशल स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वन में एक अग्रणी प्रदेश रहा है और राज्य के स्वास्थ्य और कल्याण के सकारात्मक आंकड़े इन्हीं सफल प्रयासों की पुष्टि करते हैं।

सबसे बड़ी पार्टी के

राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के विस्तार की बदस्तूर जारी मुहिम के बीच पार्टी अपने शासन वाले कुछ प्रमुख राज्यों में अंदरूनी असंतोष का सामना कर रही है, इनमें वे प्रदेश भी शामिल हैं जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने वाले हैं

अनिलेश एस. महाजन

मनीष अग्निहोत्री

भीतर मायूसी

बीती 8 मई को, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबा मंथन किया. उन्हें तय करना था कि असम में मौजूदा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल या उनके प्रतिद्वंद्वी हिमंत बिस्वा सरमा में से किसके नेतृत्व में सरकार बने. सरमा की राजनीतिक कुशाग्रता, असम की राजनीति पर उनकी पकड़ और पूर्वोत्तर में भाजपा के विस्तार में उनके योगदान को देखते हुए उनका पलड़ा निस्संदेह भारी था, लेकिन सोनोवाल भी राज्य में बहुत लोकप्रिय थे.

दुविधा इस बात की थी कि विधानसभा चुनाव में फिर से जीत हासिल करके सत्ता बरकरार रखने के बावजूद, नेतृत्व में किसी बदलाव को कैसे सही ठहराया जाए. केंद्रीय नेतृत्व ने कड़वी गोली निगलने का निर्णय किया और सरमा को कमान सौंपने का फैसला हुआ; सोनोवाल को कथित तौर पर जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में 'समायोजित' किया जाएगा. भाजपा ने दोनों में से किसी को भी चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं किया था, फिर भी माना जा रहा था कि मौजूदा मुख्यमंत्री को फिर मौका मिलेगा. इससे दो महीने पहले, विधायकों के विद्रोह के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह लो-प्रोफाइल तीरथ सिंह रावत को कमान सौंप दी थी. नवंबर 2020 में पार्टी ने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी को केंद्र में बुला लिया जबकि उन्होंने नीतीश कुमार के जद (यू) के साथ गठबंधन में लड़े गए विधानसभा चुनावों में पार्टी का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था. ये कुछ उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि अगर राज्य, केंद्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल में नहीं रहते तो पार्टी राज्यों में बदलाव से जरा भी नहीं हिचकिचाती.

इस बीच, पार्टी ऐसे नेताओं को तैयार कर रही है जो केंद्र में मोदी-शाह की जोड़ी के प्रति वफादार हैं और अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं. अगर राज्यों के नेतृत्व का वर्गीकरण किया जाए तो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तीन श्रेणियों में रखे जा सकते हैं: राज्यों के क्षत्रप जैसे बी.एस. येदियुरप्पा (कर्नाटक) और शिवराज सिंह चौहान (मध्य प्रदेश); पार्टी के सत्ता में आने के बाद हुई आकस्मिक नियुक्तियां जैसे एम.एल. खट्टर (हरियाणा), योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश) और जयराम ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) और सरमा जैसे युवा तुर्क जो अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं.

शिकवे-शिकायत
भाजपा महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों से बतायीत की

पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, दिग्गजों के उत्तराधिकारी तलाशने की योजना तैयार करना है. इस पर देरी और गैर-स्पष्टता कर्नाटक और मध्य प्रदेश में पहले से ही चुनौतियां पैदा कर रही है. जिन राज्यों में पार्टी मोदी लहर पर सवार होकर सत्ता में आई, वहां शीर्ष पद के लिए नए दावेदार उभरे हैं. भाजपा ने 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद झारखंड और हरियाणा में नेतृत्व नहीं बदला और उसकी कीमत चुकाई. जहां झारखंड में रघुबर दास के नेतृत्व वाली पार्टी का सफाया हो गया, वहीं दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली जननायक जनता पार्टी के साथ चुनाव के बाद हुए गठबंधन से जैसे-तैसे खट्टर की सरकार बनी.

2018 से ही राज्य के चुनाव (छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश) में मोदी की वोट-खींचने की शक्तियों में लगातार कमी देखी गई है और यह भाजपा के लिए बड़ी चिंता है. एक तूफानी चुनाव अभियान के बावजूद भाजपा बंगाल फतह नहीं कर पाई और उस विचार की फिर से पुष्टि हुई कि राज्यों में जनादेश तभी प्राप्त हो सकता है अगर वहां विश्वसनीय क्षेत्रीय क्षत्रप हों; अगले साल पांच विधानसभा चुनावों में इसकी फिर से परीक्षा होगी.

इस बीच, जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में है, वहां अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है. राजस्थान में नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को किनारे लगाकर आरएसएस के पसंदीदा गजेंद्र सिंह शेखावत को आगे बढ़ाने की कोशिश की. लेकिन 'ऑपरेशन सचिन पायलट' में गलत चाल और राजस्थान में राजे की मजबूत पकड़ के कारण, केंद्रीय नेतृत्व को पांव पीछे खींचने पड़े. छत्तीसगढ़ में यह थोड़ा आसान दिखता है क्योंकि तीन बार के सीएम रमन सिंह राज्य के परिदृश्य से गायब हो रहे हैं और सांसद सरोज पांडे अपने पंख फैला रही हैं.

भाजपा काडर जल्द ही फिर से कमर कसकर चुनावी समर में कूद पड़ेगा क्योंकि फरवरी 2022 में पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनाव होने हैं. पंजाब को छोड़कर, बाकी राज्यों में भाजपा सत्ता में है और भारतीय राजनीति का आधार बने रहने के लिए

इन राज्यों में पार्टी की पुनर्वापसी जरूरी होगी. बंगाल के परिणाम, कोविड की दूसरी लहर और इसके प्रबंधन को लेकर लोगों की नाराजगी के साथ स्थानीय मुद्दों का असर काडर के मनोबल पर दिखेगा.

जिन भाजपा शासित राज्यों में स्थानीय क्षत्रप नहीं हैं, वहां पार्टी के लिए सकारात्मक बात यह है कि वहां उसे बहुत से नए नेताओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिला और कुछ मामलों में तो प्रदेश के प्रचलित जातीय समीकरणों को बदल भी दिया गया है. एक प्रमुख उदाहरण हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर हैं जो पंजाबी खत्री समुदाय से हैं जिनकी संख्या राज्य की आबादी के 2 प्रतिशत से भी कम है. दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह कहते हैं, ''कई विकल्प खुले रखना, किसी राजनीतिक दल के लिए हमेशा अच्छा होता है. इससे नेतृत्व को चुनावी अंकगणित साधने के लिए आवश्यक गुणा-भाग करने में सहूलत हो जाती है. उन्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न गुट, एक-दूसरे के खिलाफ काम न करें.''

इस बीच, विद्रोहों को दबाने के लिए मुख्यमंत्रियों (उत्तराखंड की तरह) को बदलने की हालिया रणनीति ने कम से कम चार अन्य भाजपा शासित राज्यों—कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में—एक नई राजनीतिक परेशानी को जन्म दिया है.

मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच सबसे बड़ी नाराजगी इस बात की है कि पाला बदलकर आए नेताओं को पलकों पर बिठा लिया गया और उन्हें मलाईदार मंत्रालय दिए गए हैं जबकि पार्टी के पुराने नेता हाथ मलते रह गए. अन्य दलों से आने वाले दलबदलुओं को भाजपा लगातार पार्टी में शामिल कर रही है, जो येन-केन-प्रकारेण सत्ता पर काबिज होने के उसके मिशन का हिस्सा है. यह पार्टी और संघ के दीर्घकालिक राष्ट्रीय एजेंडे को तो पूरा करता है लेकिन इससे पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं के बीच बहुत नाराजगी भी पैदा होती है. चुनावी लिहाज से भी यह दोधारी तलवार है. 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में दलबदलुओं ने भाजपा के लिए अच्छा काम किया, लेकिन 2021 में बंगाल में यह आत्मघाती हो गया. बंगाल में टिकट पाने वाले 148 दलबदलुओं में से केवल छह ही जीत सके.

इस बीच, पांच राज्य के चुनावों में कुछ ही महीने शेष हैं, पार्टी कोविड के बाद जमीन पर बदलते राजनीतिक परिदृश्यों का विश्लेषण कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है. जोरदार चर्चा है कि केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जातिगत समीकरणों को मजबूत करने और पार्टी के आधार को व्यापक बनाने के लिए सरकार और संगठन में अधिक नेताओं को समायोजित करें. गोरखपुर के पूर्व सांसद और गोरखनाथ मठ के प्रमुख भगवाधारी योगी ने खुद को पार्टी के हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में स्थापित किया है. उन्हें राज्य इकाई, विधायकों के एक बड़े वर्ग और उनके कई प्रमुख मंत्रियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन पार्टी सूत्रों ने पुष्टि की कि मोदी इस बात का मजबूती से समर्थन करते हैं कि अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व योगी ही करें. पार्टी को जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या पीएम ने चुनावी रूप से महत्वपूर्ण राज्य में सही आदमी का समर्थन किया है. ■

उत्तर प्रदेश

चुनाव से पहले 'चेहरा' दुरुस्त करने की चुनौती

आशीष मिश्र

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अप्रैल महीने के बाद से लखनऊ में विधान भवन के सामने मौजूद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश मुख्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ था. सन्नाटा तब टूटा जब पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष 31 मई की सुबह 10 बजे मुख्यालय पहुंचे. दिन भर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद अगले दिन 1 जून को संतोष ने प्रदेश भाजपा कार्यालय के पहले तल पर मौजूद गेस्ट रूम संख्या एक में डेरा डाल दिया. यहां उन्होंने एक-एक कर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से बंद कमरे में मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और संगठन व सरकार के कामकाज के बारे जानकारी ली. उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार में दोनों उपमुख्यमंत्रियों केशव मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ कुल 14 मंत्रियों से बात कर सरकार की कार्यप्रणाली पर राय ली.

संतोष ने जिन मंत्रियों से अकेले में बातचीत की उनमें से ज्यादातर वे थे जिन्होंने पिछले चार वर्षों

मिलिंद शेल्टे

नुक्सान की भरपाई
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

के दौरान समय-समय पर प्रदेश सरकार के कामकाज पर असंतोष जाहिर किया था. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय के कामकाज के प्रति भाजपा के केंद्रीय पदाधिकारियों से नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. प्रदेश में पिछले कई वर्षों से मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अच्छे संबंध न होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं. हालांकि मौर्य अटकलों को सिरे से खारिज कर कहते हैं, ''अगले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा एक बार फिर 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी.''

2017 में प्रदेश भाजपा की सरकार बनने के बाद से योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा को प्रदेश सरकार का प्रवक्ता बनाया गया था. पिछले कई मौकों पर भ्रष्टाचार में लिप्त और सुस्त अधिकारियों के कामकाज पर श्रीकांत शर्मा की नाराजगी जाहिर होती रही है. यही वजह है कि श्रीकांत शर्मा ने प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम करने से खुद को अलग कर रखा है. 2017 में गोरखपुर में एन्सेफ्लाइटिस की रोकथाम करने में स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सिद्धार्थनाथ सिंह को अक्तूबर, 2019 में स्वास्थ्य विभाग से हटाकर अपेक्षाकृत महत्वहीन एमएसएमई (मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग) विभाग का कैबनेट मंत्री बनाया था. इस परिवर्तन से सिद्धार्थनाथ सिंह खुश नहीं थे. परिवहन मंत्री अशोक कटारिया भी महकमे में अफसरों की मनमर्जी और सरकार में सुनवाई नहीं होने की शिकायत प्रदेश भाजपा के नेताओं से करते रहे हैं. श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी प्रदेश सरकार में मनमुताबिक विभाग न मिलने और अधिकारियों की ओर से कार्यकर्ताओं की समस्याओं को तवज्जो न देने के खिलाफ अपनी नाराजगी वरिष्ठ नेताओं से जाहिर कर चुके हैं. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं, ''मंत्रियों और नेताओं में कुछ मतभेद हो सकते हैं लेकिन विवाद जैसी स्थिति नहीं है. सभी मंत्री व नेता 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2017 के चुनाव से भी बड़ी जीत दिलाने का संकल्प ले चुके हैं.'' (देखें इंटरव्यू)

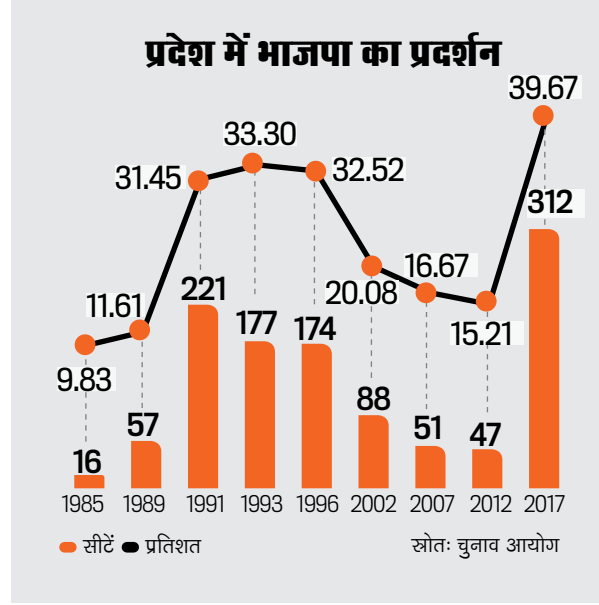

तीन दिन पार्टी पदाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों से फीडबैक लेने के बाद संतोष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले. मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उन्होंने 1 जून की रात ट्वीट करके कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार के कामकाज की प्रशंसा की. लखनऊ के तीन दिवसीय दौरे की समाप्ति पर 2 जून को संतोष ने दोबारा ट्वीट करके कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए योगी सरकार के टीकाकरण अभियान की सराहना की और बच्चों की बेहतर देखभाल होने की उम्मीद जताई. इस तरह भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने संकेत दिया कि शीर्ष नेतृत्व का योगी आदित्यनाथ में विश्वास बरकरार है. संतोष ने भाजपा के प्रदेश नेताओं और प्रदेश के मंत्रियों के बीच नियमित समन्वय बैठकें करने का निर्देश भी दिया है.

कानपुर में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में राजनीतिशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और भाजपा की राजनीति पर करीबी से नजर रखने वाले आशुतोष सिन्हा बताते हैं, ''कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश में कई चुनौतियां एक साथ भाजपा के सामने आ गई हैं. पंचायत चुनाव में अनुकूल नतीजे नहीं आने के बाद गांव कोरोना संक्रमण से भी पीड़ित हुए. प्रदेश में कोरोना से हुए नुक्सान के 'डैमेज कंट्रोल' की चुनौती ने भाजपा को प्रदेश में संगठन या सरकार में कोई बड़ा परिवर्तन करने से रोक दिया है. प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में सात महीने का समय रह गया है. ऐसे में भाजपा के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश संगठन की कमियां दूर कर कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है.''

संतोष ने 5 जून को अपनी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को सौंप दी. पता चला है कि संतोष प्रदेश की जातियों खासकर ओबीसी, दलित और ब्राह्मण में पकड़ मजबूत करने के लिए संपर्क कार्यक्रम शुरू करने, पार्टी में रिक्त पड़े पदों को भरने, कार्यकताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय करने, 15 जुलाई से पहले होने वाले जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को बेहद मजबूती के साथ लड़ने जैसे सुझावों से जुड़ी रिपोर्ट नड्डा को सौंपी है. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में 39 प्रतिशत से अधिक वोट पाकर 312 सीटें जीतने वाली भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस प्रदर्शन को 2022 के विधानसभा चुनाव में दोहराने की है. अगले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश के 75 जिलों होने वाले जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव के जरिए शक्ति दिखाने की तैयारी में है. यह चुनाव 15 जुलाई से पहले प्रस्तावित हैं. नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य अपने जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे. चुनाव से पहले पार्टी में मतभेद और गुटबाजी से बचने के लिए भाजपा अपने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों का नाम आपसी

मनीष अग्निहोत्री

बातचीत | **स्वतंत्र देव सिंह**

“जिन्हें भाजपा की कार्यप्रणाली का ज्ञान नहीं वे ही अटकलें लगाते रहते हैं”

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और भाजपा संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 6 जून की सुबह लखनऊ में गौतमपल्ली स्थित अपने आवास पर इंडिया टुडे के असिस्टेंट एडिटर आशीष मिश्र से बातचीत की. कुछ अंशः

● **उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के सामने क्या चुनौतियां हैं?**
कोरोना जैसी महामारी पहले कभी नहीं हुई. अब स्वास्थ्य जनता की प्राथमिकता बन गया है. जितना हो सकता है केंद्र और राज्य की सरकार पूरी प्रतिष्ठा लगाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं.

● **कोरोना की दूसरी लहर में सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े हुए हैं?**
पहले भी जब देश पर कोई संकट आता था तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी विपक्ष की भूमिका निभाते थे. संकट के समय वे हमेशा सत्ता पक्ष के साथ खड़े रहते थे. कोरोना काल में पहली बार यह देखने को मिला कि सभी विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने का काम किया. सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भूमिका सबसे ज्यादा खराब रही.

● **भाजपा के प्रदेश संगठन में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं?**
भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है. कार्यकर्ता के निर्माण और उन्हें सक्रिय रखने के लिए रैली, प्रशिक्षण, बैठक और सम्मेलन नियमित होते रहते हैं. जिन्हें भाजपा की कार्यप्रणाली का ज्ञान नहीं वे ही अटकलें लगाते रहते हैं.

● **पंचायत चुनाव में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन की क्या वजह मानते हैं?**
पंचायत चुनाव में भाजपा का यह पहला अनुभव था जब सभी जगह पर प्रत्याशी खड़ा किया. मेरा मानना है कि जब चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं हो रहा हो तो प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाहिए था. हम लोगों से गलती हुई. अगर चुनाव चिन्ह होता तो परिणाम अलग आते. फिर भी, भाजपा ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है. जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव भाजपा बड़ी संख्या में जीतेगी.

● **दलित और पिछड़ी जाति के बीच भाजपा का जनाधार कम हो रहा है?**
पार्टी के पास पासी, जाटव, कठेरिया, कोरी, वाल्मीकि, खटीक, धोबी समेत अनुसूचित जाति के सभी वर्गों में नेतृत्व है. ओबीसी में भी कुर्मी, मौर्य, पाल, सैनी, बिंद, निषाद, मल्लाह, प्रजापति सभी जातियों में भाजपा के पास नेतृत्व है. भाजपा सभी जातियों की बात सुनती है और सभी को मौका देती है.

● **अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की लड़ाई किस दल से मानते हैं?**
ईमानदारी, अपराध मुक्त, कानून का राज, विकास ऐसे कई सारे बिंदुओं पर योगी आदित्यनाथ की सरकार के कामकाज के आगे अखिलेश यादव की पिछली सरकार कहीं नहीं ठहरती है. कोरोना काल में जहां योगी जी गांव-गांव गए वहीं अखिलेश ने खुद को बंगले में कैद कर रखा. ऐसे में जनता अखिलेश को क्यों पसंद करेगी.

● **प्रदेश भाजपा के प्रकोष्ठ और मोर्चा का गठन नहीं हो पाया है?**
प्रक्रिया चल रही है. दो हफ्ते के भीतर इनका गठन हो जाएगा.

● **भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार के कामकाज के खिलाफ पत्र लिखे हैं?**
जिस पार्टी के पास तीन सौ से अधिक विधायक हों. साठ से अधिक सांसद हों, हजारों जनप्रतिनिधि हों, उनमें दो-तीन नेताओं ने अगर सुझाव के लिए पत्र लिखे हों तो उसे किसी प्रकार का विवाद नहीं मानना चाहिए.

● **बीते कुछ दिनों में भाजपा नेताओं के अपराधियों से गठजोड़ की बातें भी सामने आई हैं?**
अपराधियों को संरक्षण देने वाला चाहे वह प्रदेश सरकार में मंत्री हो या संगठन में पदाधिकारी, सब पर सख्त कार्रवाई हो रही है.

● **2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कितनी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है?**
जितनी सीटें भाजपा के पास हैं, उससे अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. हम 51 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करेंगे.

● **मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है?**
अभी कोई चर्चा नहीं हुई है. कोरोना महामारी में सरकार का ध्यान केवल लोगों की सुरक्षा पर है. अगले तीन महीने तक पार्टी जनता के बीच जाकर उनकी सेवा पर ध्यान लगाएगी.

● **प्रदेश भाजपा और सरकार में कई पावर सेंटर बनने के आरोप लग रहे हैं?**
प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में काम कर रही है. संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर रहा है.

● **भाजपा और बसपा के बीच तालमेल की अटकलें लगाई जा रही हैं?**
यह सब खबरें निराधार हैं. बहन जी (मायावती) स्वयं सपा से ज्यादा ताकतवर हैं. ■

सहमति से तय करेगी. प्रदेश भाजपा के पंचायत चुनाव प्रभारी विजय बहादुर पाठक बताते हैं, ''हर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष के दो से तीन संभावित दावेदारों का एक पैनल तैयार होगा. दावेदारों के पास उपलब्ध सदस्यों के समर्थन का आकलन करने के बाद ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जाएगा.'' जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में भाजपा पिछड़ी जाति को तवज्जो देगी. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जिलों का दौरा कर जिला पंचायत अध्यक्ष के जिताऊ उम्मीदवार खोज रहे हैं. 6 जून को बरेली में प्रदेश अध्यक्ष ने पिछड़ी जाति के कई संभावित उम्मीदवारों के बारे में स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से फीडबैक लिया.

प्रदेश भाजपा में अनुषांगिक संगठनों का नए सिरे से गठन न होने से भी कार्यकर्ताओं में असंतोष है. प्रदेश भाजपा संगठन में पिछड़ा मोर्चा, अनुसूचित जाति-जनजाति मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा समेत कुल सात मोर्चा हैं. सभी मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति के साथ जिला पर भी कार्यसमिति है. इसके अलावा भाजपा के 45 प्रकोष्ठ हैं जिनमें प्रदेश और जिला स्तर पर समन्वयक की तैनाती होती है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने 22 अगस्त, 2020 को नई प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा की थी. पिछले नौ महीने से मोर्चा और प्रकोष्ठ का गठन लंबित है. इससे प्रदेश भाजपा नेताओं में आपसी तालमेल की कमी का संकेत मिलता है. मोर्चा और प्रकोष्ठ के गठन में देरी का मुद्दा बी. एल. संतोष की बैठक में भी उठा था. प्रदेश अल्संख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद लंबे समय से खाली है. कई निगमों और बोर्डों में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हैं. इससे कार्यकर्ताओं में दुविधा है. राष्ट्रीय संगठन महामंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद भाजपा संगठन सभी राजनीतिक नियुक्तियां जून के अंत तक पूरा करने में जुट गया है. फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा दौरा कर चुनावी तैयारियों का बिगुल बजाएंगे. ■

मध्य प्रदेश

गोपनीय बैठकें

भोपाल और दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच हाल ही में बंद दरवाजे की बैठकों की श्रृंखला ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को हवा दी है, जिसे अंततः इन बैठकों में शामिल नेताओं से बयान दिलवाकर रोकना पड़ा. 31 मई को, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ बंद कमरे में बैठक की; इसके तुरंत बाद, मिश्रा से पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और फिर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की भी मुलाकात हुई. लगभग उसी दौरान, विजयवर्गीय और शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल के साथ अलग-अलग मुलाकात की. ये सारी बैठकें उस समय हुईं जब भाजपा के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव (संगठन) शिव प्रकाश भोपाल में राज्य के नेताओं से मिल रहे थे और इनमें से कई बैठकों में वे नेता शामिल थे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी नहीं माने जाते. इससे खुसफुसाहट होने लगी कि क्या पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चौहान को बदलना चाहता है. हालांकि इन बैठकों का आधिकारिक एजेंडा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा थी, भाजपा के सूत्रों का कहना है कि जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें राज्य के स्वामित्व वाले

पंकज तिवारी

सत्ता का केंद्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (नारंगी रंग के कपड़ों में) के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा (चौहान के बाएं)

उपक्रमों के लिए अध्यक्षों और पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति जैसे नेतृत्व से जुड़े सवाल भी थे. नाम न जाहिर करने की शर्त पर भाजपा के एक शीर्ष नेता कहते हैं, ''कैलाश जी अपनी जमीन की थाह ले रहे हैं. बैठकें राज्य में नेतृत्व से नाखुश लोगों के लिए एक संदेश थी कि एक संभावित वैकल्पिक खेमा भी मजबूत हो रहा है.''

कांग्रेस का कहना है कि ये बैठकें इस बात का सबूत हैं कि भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व सीएम को हटाना चाहता है. कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा कहते हैं, ''भाजपा कहती है कि बैठकें बंगाल के नतीजों का आकलन करने के लिए हुई थीं, लेकिन आकलन तो केवल मुख्यमंत्री चौहान के प्रदर्शन का किया जा रहा था.'' भाजपा ने इन बैठकों को नियमित बैठकें बताया है. प्रदेश प्रवक्ता राहुल कोठारी कहते हैं, ''लॉकडाउन के दौरान हमने कई नेताओं और मीडिया में कई दोस्तों को खो दिया. नेता अब शोकसभा कर रहे हैं. और जहां तक शिव प्रकाश जी का सवाल है, मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है जिसका मतलब है कि वे अक्सर भोपाल आते रहेंगे.'' पार्टी ने डैमेज कंट्रोल भी किया और नेताओं से ऐसी बैठकों का प्रचार न करने को कहा. 7 जून को मीडिया को दिए एक बयान में मिश्रा ने कहा, ''शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे.'' विजयवर्गीय ने भी कहा है कि इन अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है. यह पूछे जाने पर कि सीएम के वैकल्पिक चेहरे के रूप में उनका नाम क्यों चल रहा है तो उनका उत्तर था, ''मैं अभी कहीं और लगा हुआ हूं.'' —**राहुल नरोन्हा**

उत्तराखंड

समाधान ही समस्या

एएनआइ

चुनौतीपूर्ण दायित्व
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

जब11 मार्च को, लाखों श्रद्धालु महाकुंभ मेले के पहले स्नान के लिए हरिद्वार में उमड़ने लगे थे, राज्य एक बड़े राजनीतिक मंथन की प्रतीक्षा में था. अपने सहयोगियों और स्थानीय विधायकों के बीच बहुत ज्यादा अलोकप्रिय हो गए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 9 मार्च को इस्तीफा दे दिया और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी जगह सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया. भाजपा के मोदी-शाह युग में पहली बार ऐसा हुआ था कि पार्टी ने एक मुख्यमंत्री को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले बदल दिया और वह भी तब जब कि राज्य में विधानसभा चुनावों में एक साल से भी कम का समय शेष है.

हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि त्रिवेंद्र की जगह ले रहे तीरथ क्षेत्रीय क्षत्रपों का विश्वास जीतने में सक्षम होंगे, लेकिन उनके सार्वजनिक बयानों और फैसलों ने जल्द ही भाजपा आलाकमान को परेशान कर दिया. इस बात के लिए विरोध कि पूरे देश में कोविड संक्रमण के बड़े पैमाने पर प्रसार का खतरा हो सकता है, मुख्यमंत्री बिना किसी प्रतिबंध के महाकुंभ मेला आयोजित कराने को लेकर अड़े रहे. साथ ही लोग प्रधानमंत्री मोदी को भगवान कृष्ण और भगवान राम के अवतार के रूप में देखते हैं, जैसे बयानों के कारण तीरथ पर लगाम लगाने के लिए पार्टी आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा.

राज्य में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी, भाजपा की राष्ट्रीय टीम के सदस्य अनिल बलूनी और राज्य के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत जैसे सत्ता के कई केंद्र होने के कारण उत्तराखंड की राजनीति और अधिक जटिल हो जाती है. उन्हें चुनौती देने वाले कई नेताओं का मानना है कि अगर तीरथ सिंह इसी प्रकार गलतियां करते चले गए तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को या तो चुनाव से पहले उन्हें बदलना पड़ सकता है या फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा किए बिना चुनाव में उतरना पड़ सकता है जैसा कि 2017 में हुआ था.

2017 में चार पूर्व मुख्यमंत्रियों- पोखरियाल, कोश्यारी, बी.सी. खंडूरी और कांग्रेस से आए विजय बहुगुणा सहित कई संभावित दावेदार होने के बावजूद भाजपा बिना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए चुनाव लड़ी थी.

यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत अपील और भाजपा की विकास योजनाओं के बूते चलाया गया था. बाद में भाजपा ने लो-प्रोफाइल त्रिवेंद्र सिंह को चुना था. पूर्व सीएम के खिलाफ दो साल से असंतोष चल रहा था, विधायक कथित तौर पर अपनी राय को नजरअंदाज किए जाने से मुख्यमंत्री से नाखुश थे. अब, उनकी जगह लाए गए तीरथ सिंह भी विवादास्पद विकल्प साबित हो रहे हैं और आगामी चुनाव भाजपा के लिए कड़ी परीक्षा साबित होंगे.

—अनिलेश. एस. महाजन

गुजरात

असहज दौर

शैलेन्द्र राव

राह में रोड़े गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी

चक्र वात ताउते से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अहमदाबाद पहुंचने पर 19 मई को प्रधानमंत्री ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी. आर. पाटिल के साथ अकेले में बैठक की.

परंपरा से हटकर रूपाणी को इस बैठक से अलग रखा गया. एक सूत्र का कहना है कि इसने एक मजबूत राजनीतिक संदेश देने का काम किया—कि पाटिल का मोदी से सीधा संबंध है और यह कि प्रधानमंत्री ने उनका समर्थन किया.

मोदी का समर्थन ऐसे समय में आया है जब पाटिल और रूपाणी के बीच अनबन की खबरें आ रही थीं. मुख्यमंत्री के समर्थकों का कहना है कि जून 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बने पाटिल ने पार्टी संगठन को संभाल लिया है और रूपाणी की अनदेखी करते रहे हैं. हाल ही का एक उदाहरण है, जब पाटिल ने 10 अप्रैल को राज्य भाजपा की ओर से कोविड रोगियों को रेम्डेसिविर की 5,000 शीशियां वितरित कीं. ''कृपया सी.आर. पाटिल से संपर्क करें,'' रूपाणी ने 13 अप्रैल को कथित तौर पर कहा, जब पत्रकारों ने दवा की कमी से निपटने के

लिए उनकी सरकार की योजना के बारे में पूछा.

रूपाणी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नजदीकी माना जाता है और उनके समर्थक कथित तौर पर पाटिल से उन्हें और शाह के करीबी अन्य नेताओं की अनदेखी के चलते नाराज हैं. वे शाह के एक और वफादार प्रदीप सिंह जडेजा के पतन को उजागर करते हैं, ''पहले अहमदाबाद में पार्टी की कोई भी नियुक्ति जडेजा की सहमति के बिना नहीं होती थी. अब पाटिल के दाहिने हाथ प्रदीप वाघेला अंतिम फैसला लेते हैं.'' एक रूपानी समर्थक कहते हैं. इसी तरह दरकिनार किए गए अन्य नेताओं में सुरेंद्र पटेल और शंकर चौधरी भी शामिल हैं.

एक सूत्र इन घटनाक्रमों को रूपाणी और पाटिल के बीच 'शीत युद्ध' का परिणाम बताते हैं जो एक बेहद सफल राज्य के अध्यक्ष के रूप में उभरे हैं—उनके नेतृत्व में पार्टी ने फरवरी में स्थानीय निकाय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की. हालांकि राज्य में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता यमल व्यास ने पाटिल और रूपाणी के बीच अनबन की खबरों को खारिज कर दिया. वे कहते हैं, ''पार्टी और सरकार मिलकर काम करती है. यह धारणा कि इन दोनों के बीच मतभेद है, सोशल मीडिया की उपज है.''

—किरण डी. तारे

हिमाचल प्रदेश

दो ठाकुरों की खींचतान

पिछले साल नवंबर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय परियोजना में जारी देरी पर सार्वजनिक विवाद हुआ था. हालांकि दोनों कुछ समय से आमने-सामने हैं, लेकिन वे अब तक सार्वजनिक टकराव से बचते रहे हैं. जाहिर है दोनों के बीच शांति बहाल करने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा.

अनुराग दो बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं. 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने धूमल को मुख्यमंत्री पद के अपने उम्मीदवार के रूप में पेश किया था, लेकिन वे अपने पारिवारिक गढ़ हमीरपुर के सुजानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गए. अनुराग अब राज्य की राजनीति में पिता की विरासत का दावा कर रहे हैं. उन्होंने भाजपा को जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के साथ गठबंधन करने और हरियाणा में सत्ता बनाए रखने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हालांकि, वे समझते हैं कि उनके लिए भाजपा और आरएसएस को हिमाचल के मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जयराम ठाकुर को संघ का समर्थन प्राप्त है.

हालांकि अनुराग 56 वर्षीय मुख्यमंत्री के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं. कई मौकों पर, राज्यसभा और भाजपा की राज्य इकाई के लिए जयराम ठाकुर के उम्मीदवारों की अनदेखी की गई. हालांकि, पिछले एक साल में जयराम ने कुछ पकड़ बनाई है. पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के खेमे के अधिकांश भाजपा नेताओं ने उनके समूह में पाला बदल लिया है और यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा सहित भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी उन पर विश्वास दिखाया है.

पिछले साल जयराम के वफादार सुरेश कुमार कश्यप ने राजीव बिंदल की जगह पार्टी के राज्य प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था. कश्यप राज्य के दलित समुदाय के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने की ठाकुर की योजना का हिस्सा हैं, जिन्होंने परंपरागत रूप से कांग्रेस को वोट दिया है. उभरती ठाकुर-दलित धुरी ने हाल के ग्रामीण निकाय चुनावों में भाजपा को 80 प्रतिशत सीटों पर कब्जा करने में मदद की और चार शहरी निकायों में से दो पर जीत हासिल की.

—अनिलेश एस. महाजन

संदीप सहदेव

ठाकुर की चुनौती
हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

कर्नाटक

अघोषित युद्ध

बीते 6 जून को विधान सौध में पूर्व मुख्यमंत्री देवराज उर्स की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा (बीएसवाइ) ने एक राजनीतिक धमाका करते हुए कहा कि वे अपने पद पर तब तक बने रहेंगे, जब तक कि भाजपा आलाकमान को उन पर भरोसा है. उन्होंने कहा, ''जिस दिन वे मुझे पद छोड़ने के लिए कहेंगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा और राज्य के कल्याण के लिए काम करने में खुद को लगा दूंगा. बाकी केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है.''

उनके इस भावनात्मक धमाके ने सभी को चौंका दिया क्योंकि वे वही व्यक्ति हैं जो (2011 में) भाजपा से बाहर चले गए थे, जब पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने से इनकार कर दिया (उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था). वे नरेंद्र मोदी के आग्रह पर आम चुनाव से पहले 2014 में पार्टी में लौटे थे.

उनके बयान के बाद, पार्टी में उनके सामान्य विरोधी भी यह दावा करते हुए उनके पक्ष में खड़े हो गए कि अभी नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता नहीं है. लेकिन बीएसवाइ आराम से नहीं बैठ सकते. उनके और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी.एल. संतोष के बीच एक अघोषित युद्ध चल रहा है. कर्नाटक इकाई में संतोष के वफादारों का दबदबा है, जिसमें राज्य के प्रमुख नलिन कुमार कतील, उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी और ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा शामिल हैं, ये सभी बीएसवाइ खेमे को लगातार परेशान कर रहे हैं.

बीएसवाइ को कई लोगों की आलोचनाओं को झेलना पड़ता है, क्योंकि वे अपने मंत्रिमंडल में कई दिग्गज भाजपा नेताओं

को समायोजित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उन्हें जनता दल (एस)-कांग्रेस के 17 दलबदलुओं में से 10 को मंत्रिमंडल में 'समायोजित' करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें सरकार बनाने में मदद की. इनमें से ज्यादातर भाजपा नेता संतोष का साथ दे रहे हैं.

भाजपा के मंत्री और विधायक नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर नियमित रूप से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ऊपर से ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है. कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी, येदियुरप्पा के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं, लेकिन चुनौती देने वालों का मानना है कि आलाकमान को जल्द ही उत्तराधिकार की योजना बनानी होगी. बीएसवाई पहले से ही 78 वर्ष के हो चुके हैं और मोदी-शाह की जोड़ी का एक अलिखित नियम है कि 75 वर्ष की उम्र में पार्टी के लोगों को सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त कर दिया जाए. उनके पुत्र बी.एस. विजयेंद्र पार्टी उपाध्यक्ष हैं और वे मुख्यमंत्री के विरोधियों के निशाने पर भी हैं. बहुत से लोग उनकी कथित आचार संहिता के प्रशंसक नहीं हैं, जिनमें बैठकों में केवल मंत्रियों को शामिल होने की अनुमति है. जाहिर है, विजयेंद्र ऐसे आरोपों का खंडन करते हैं.

इस बीच, संतोष बीएसवाइ के प्रभावशाली लिंगायत समुदाय पर भाजपा की निर्भरता को कम करने के लिए राज्य में जातिगत समीकरणों पर फिर से काम कर रहे हैं. पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के प्रभुत्व वाले ईश्वरप्पा का कुरुबा समुदाय का समर्थन हासिल करना उनका लक्ष्य है.

—अनिलेश एस. महाजन

पीएमओ

माहिर राजनेता
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा

राजस्थान

ज्यादा जोगी...

राजस्थान भाजपा इकाई मोटे तौर पर चार धड़ों में बंटी है, जिनकी अगुआई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करते हैं.

2018 विधानसभा चुनाव में अपनी हार के बाद से राजे शांत बैठ गईं, हालांकि पूनिया गुट के साथ उनकी सीधी भिड़ंत जारी है. भाजपा के 72 विधायकों में से कम से कम आधे और 25 सांसदों में से कम से कम 8 राजे के धड़े में हैं. हालांकि, वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें शायद ही कोई जिम्मेदारी दी जाती है या अशोक गहलोत की अगुआई वाली सत्ताधारी कांग्रेस को घेरने की किसी रणनीति का हिस्सा बनाया जाता है. पूनिया, जो सर्वदा उपलब्ध प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिखते हैं, भाजपा-आरएसएस की उस रणनीति का हिस्सा हैं जो लंबे समय से काम कर रहे सदस्यों

हिमांशु व्यास/गेट्टी इमेजेज

दांवपेच
गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे

को पुरस्कृत करने वाली है चाहे उनका चुनावी रिकॉर्ड कितना भी बुरा क्यों न रहा हो. बहरहाल, वे पहली बार विधायक बने और अतीत में तीन बार चुनाव लड़कर धराशायी हो चुके हैं. उनके अध्यक्ष बनने के बाद से राज्य विधानसभा के लिए पांच उपचुनाव हो चुके हैं पर वह सूबे में पार्टी का प्रदर्शन सुधारने के लिहाज से नाकाम रहे हैं.

आरएसएस के दिग्गज वफादार, कटारिया की उम्र 75 साल के पार हो गई है. पूनिया गुट को उम्मीद है कि वे जल्दी ही रिटायर हो जाएंगे—शायद उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा—और इससे इस धड़े के राजेंद्र राठौड़ सरीखे लोगों की पदोन्नति हो सकती है, जो इस वक्त विपक्ष के उपनेता हैं. बहरहाल, इस वक्त तक भाजपा आलाकमान इस मसले पर फूंक-फूंककर कदम रख रहा है और यह तय कर रहा है कि सारे पत्ते एक साथ न खोल दिए जाएं.

शेखावत के गहलोत सरकार की कुर्सी छीनने की नाकाम कोशिश के बावजूद नेतृत्व का हाथ उनके साथ है. इस कोशिश में सचिन पायलट और उनके धड़े को कांग्रेस के अलग करवाया गया था, लेकिन कथित तौर पर भाजपा को लगता है कि इस नाकामी ने भी प्रदेश कांग्रेस को बहुत बड़े पैमाने पर नुक्सान पहुंचाया है. शेखावत के साथ विधायकों का समर्थन नहीं है और अपनी लोकसभा सीट जोधपुर से आगे उनकी मौजूदगी भी नहीं है.

बहरहाल, सूत्रों का कहना है कि उनमें राज्य के नेताओं के लिहाज से संभावनाएं अधिक दिख रही हैं और इसी वजह से संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और अधिक तजुर्बेकार अर्जुन मेघवाल पर उन्हें तवज्जो दी गई और उनकी पदोन्नति कैबिनेट दर्जे तक की गई.

—रोहित परिहार

एएनआइ

विवाद में उलझे
केरल भाजपा के अध्यक्ष के. सुरेंद्रन (बीच में)

केरल

नाकामी और कलंक

केरल में भाजपा के लिए सब कुछ ढलान पर जाता दिख रहा है, एक ऐसा सूबा जहां पार्टी के पास एक विधायक था लेकिन वह हालिया विधानसभा चुनाव में घटकर शून्य पर पहुंच गई है. इतना ही कलंक कम न था, इसे और गहरा कर दिया है चुनाव बाद के स्कैंडल ने. इसमें स्थानीय पार्टी नेताओं पर पार्टी के चुनाव अभियान के फंड की डकैती, हवाला के जरिए फंड हासिल करने और चुनावी घूस जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मेट्रोमैन ई. श्रीधरन, पूर्व डीजीपी जैकब थॉमस और पूर्व नौकरशाह सी.वी. आनंद बोस (यह तीनों भाजपा के टिकट पर इस बार चुनाव में उतरे थे) के एक पैनल को 3 अप्रैल को कोडाकारा में प्रचार फंड की लूट मामले की जांच करने को कहा है. राज्य पुलिस ने अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और हाइवे पर डकैती के करीबन 3.5 करोड़ रुपए में से 1.12 करोड़ रुपए जब्त किए हैं. आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले पांच पार्टी नेता कथित रूप से उस गैंग के साथ संपर्क में थे जिसने इस पैसे की डकैती की थी.

6 जून को कोच्चि में हुई प्रदेश भाजपा कोर कमिटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन और विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधर को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. अपना नाम न छापने की शर्त पर एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने *इंडिया टुडे* से कहा कि उनमें से बेहद कम लोगों को केरल में चुनाव प्रचार अभियान में खर्च की गई कुल रकम की भनक है. वे कहते हैं, ''प्रस्ताव 400 करोड़ रुपए का था और कर्नाटक के पार्टी नेताओं ने भरोसा दिया था कि फंड मुहैया कराया जाएगा. हमें नहीं पता कि कितना दिया गया और किसने कितना हासिल किया.''

अब सुरेंद्रन पर तलवारें तन गई हैं क्योंकि उनके फोन की एक बातचीत लीक हो गई है जिसमें वे कथित तौर पर आदिवासी नेता सी.के. जानू को साथ लाने और वायनाड की बतेरी सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर उन्हें खड़ा करने के लिए 10 लाख रुपए की डील तय करते सुनाई दे रहे हैं. अन्य आरोपों में बसपा के नेता सुंदरा भी शामिल हैं जो कहते हैं कि मांजेश्वरम सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के एवज में उन्हें 2.5 लाख रुपए मिले थे. सुरेंद्रन ने अपना परचा वहीं से दाखिल किया था.

—जीमॉन जैकब

चुनौती भरपूर मंजिल दूर

कोविड-19 की दूसरी लहर से चित हुई सरकार अब **अपनी टीकाकरण की रणनीति को नया जामा पहना रही है.** उसे उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक तक वह देश की 90 करोड़ वयस्क आबादी को टीका लगवा देगी. आखिर कितना यथार्थपरक है उसका यह लक्ष्य? क्या यह मुमकिन हो पाएगा?

राज चेंगप्पा और पी.बी. जयकुमार

जब खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जून को शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे, महामारी के संकट से घिरा देश अहम चौराहे पर खड़ा था. अच्छी बात यह थी कि दूसरी लहर साफ तौर पर उतार पर थी और कोविड-19 के संक्रमण के नए मामले रोज 4,00,000 के शिखर से उतरकर 1 जून को 1,00,000 से नीचे आ गए थे, हालांकि तब भी वे पहली लहर के शिखर से ज्यादा ही थे. इसका मतलब था कि खतरा अभी बरकरार था और खुलने की प्रक्रिया धीरे-धीरे ही चलनी थी. खराब बात यह थी कि बहुत सावधानी से तैयार किया गया कोविड टीकाकरण अभियान आत्मघाती अराजकता में फंस जाने के खतरे से घिरा था.

केंद्र सरकार ने 21 अप्रैल को टीके की जिस उदार व्यवस्था का ऐलान किया था और जिसमें राज्यों को 18-44 साल के लोगों को टीके लगाने के लिए खुद वैक्सीन खरीदने और कीमत तय करने की छूट दी थी, वह नाकाम हो रही थी. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे 'विवेकहीन और मनमाना' करार देते हुए केंद्र से इसे वापस लेने के लिए कहा था. केंद्र और राज्यों के बीच दोषारोपण का खेल तीखा होने के साथ खुराकों की कमी की वजह से टीके लगाने में अप्रैल के

आशीष वैष्णव/गेट्टी इमेजेज

ज्यादा की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जून को राष्ट्र के नाम अपने संदेश के दौरान (ऊपर); मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अप्रैल में वैक्सीन खत्म होने से निराश लोग

सुरक्षित होने को अभी करना है लंबा सफर

मुकाबले मई में खासी कमी आई. केंद्र डींगें हांकता रहा कि टीके लगाने की कुल तादाद के मामले में भारत सबसे अव्वल तीन देशों में है और केवल चीन तथा अमेरिका ही उससे आगे हैं. मगर हकीकत यह थी कि टीका अभियान के 136 दिन बाद भी 1 जून को महज 4.1 करोड़ या देश की आबादी के 3 फीसद से भी कम लोगों को टीके की दोनों खुराकें लगी थीं.

दूसरी लहर को खराब ढंग से संभालने के लिए भी मोदी सरकार को आलोचना झेलनी पड़ी. राज्य सरकारों को भी बख्शा नहीं गया, खासकर जब बड़े शहरों और ग्रामीण इलाकों में कोविड के गंभीर मरीजों के इलाज की बेहद जरूरी सुविधाएं ध्वस्त हो गईं. मेडिकल ऑक्सीजन की जानलेवा कमी ने आग में घी का काम किया और मौतों की तादाद को पहली लहर के मुकाबले दोगुने ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया. श्मशानों के बाहर मृतकों की अंत्येष्टि के लिए लगी लंबी कतारों ने लोगों के गुस्से और आक्रोश में इजाफा ही किया. जाहिर था कि महामारी से निबटने की केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की क्षमता में उनका भरोसा नहीं बचा था. बदतर यह कि दूसरी से शायद ज्यादा विनाशकारी तीसरी लहर का खतरा साफ दिखाई दे रहा था, वह भी तब जब हिंदुस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद टीके नहीं लगने के कारण असुरक्षित थी.

मोदी ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन शुरू किया, दीवार पर लिखी इबारत साफ थी. इससे पहले कि हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर चले जाएं, टीके लगाने की रणनीति में अधबीच सुधार की जरूरत थी. कई राज्यों ने यह मांग जरूर की थी कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाकर उसमें कम आयु वाले समूहों को भी शामिल किया जाए और टीकों की खरीद को विकेंद्रीकृत करके उन्हें निर्माता से सीधे खरीदने की इजाजत दी जाए, मगर पहले के महीनों में टीके खरीदने के अपने अनुभव को देखते हुए केंद्र ने यह मांग मानकर गलती की थी. लिहाजा मोदी ने जरूरत का फायदा उठाया और ऐलान किया कि अब केंद्र ही टीकों की पूरी खरीद करेगा (जो वह पहले कर रहा था) और इसके अलावा 18-44 आयु समूह के लिए भी मुफ्त टीके मुहैया करेगा, उसी तरह जैसे वह 45 साल और उससे ऊपर के आयु समूहों के लिए कर रहा था. धर्मग्रंथों से उद्धृत करते हुए मोदी ने कहा, ''विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं.''

मिशन इंपॉसिबल?

भारत के टीका अभियान में अभी बहुत कुछ जीतना बाकी है. केंद्र ने 31 दिसंबर तक देश की 94 करोड़ वयस्क आबादी को टीके लगाने के लक्ष्य का ऐलान किया है. मतलब कि जून से दिसंबर तक 90 करोड़ लोगों को यानी रोज 84 लाख लोगों को टीके लगाने होंगे, जो मौजूदा रफ्तार से तिगुने हैं. इस रफ्तार से अमेरिका की पूरी 30 करोड़ आबादी को टीके लगाने में 71 दिन लगेंगे. अमेरिका ने अपना टीका कार्यक्रम 14 दिसंबर को शुरू किया और रोज दस लाख से कुछ कम लोगों को टीके लगाने की रफ्तार से 8 जून तक 14.3 करोड़ लोगों या 42.4 फीसद आबादी को टीके लगाए थे.

दिसंबर तक 90 करोड़ वयस्क भारतीयों को टीके लगाना वाकई पहाड़ गिराने जैसा काम है. केंद्र सरकार को न केवल 2

एक लहर उम्मीद की

(जून–दिसंबर 2021 के बीच टीके की अनुमानित उपलब्धता, करोड़ खुराक में)

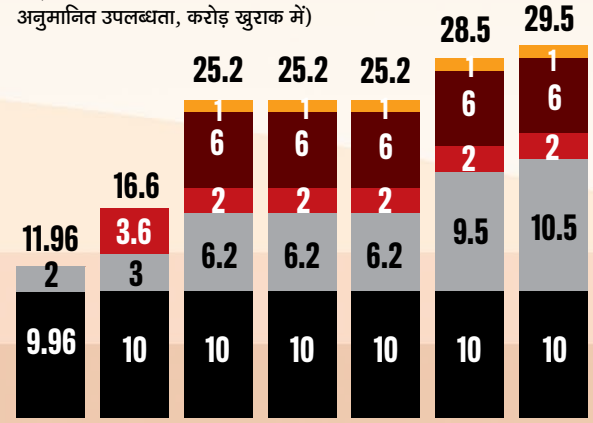

लंबा है फासला

पूरी तरह से टीकाकृत आबादी का प्रतिशत

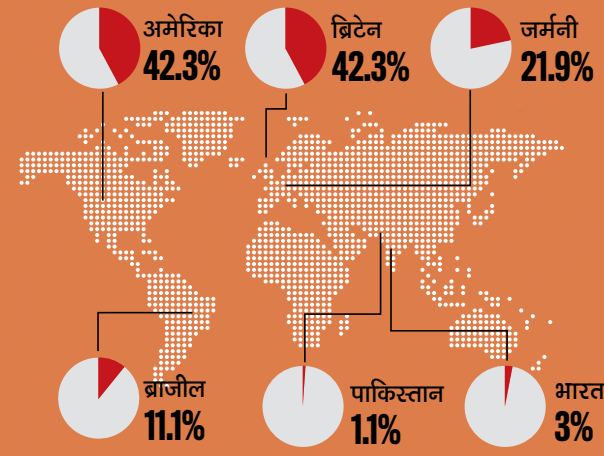

रोज लगने वाले टीके

हालांकि टीकों की उपलब्धता और टीकाकरण दोनों धीरे-धीरे गति पकड़ रहे हैं लेकिन इनकी रफ्तार फिर भी धीमी है. इससे भारत के तीसरी लहर में फंसने का खतरा बरकरार

टीकाकरण की रफ्तार तीन गुना करने की जरूरत

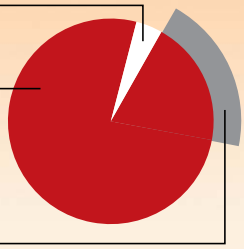

पूरी तरह से टीकाकृत
4.1 करोड़

इतनी आबादी को अभी टीके लगने हैं
90 करोड़

पहली खुराक मिल चुकी
18.1 करोड़

अभी इतनी खुराक दी जानी बाकी
161.9 करोड़

रोज लग रहे टीके, 8 जून तक के हिसाब से
27 लाख

27 लाख खुराक रोजाना के हिसाब से तो भारत की 18 वर्ष से ऊपर की 90 करोड़ से ज्यादा की आबादी को टीका लगने में 599 दिन लग जाएंगे

इस लक्ष्य को 31 दिसंबर 2021 तक हासिल करने के लिए भारत में रोजाना 84 लाख टीके लगने चाहिए

70%
भारत की आबादी को 31 दिसंबर 2021 तक टीका लगना है

उम्र के हिसाब से टीकाकरण

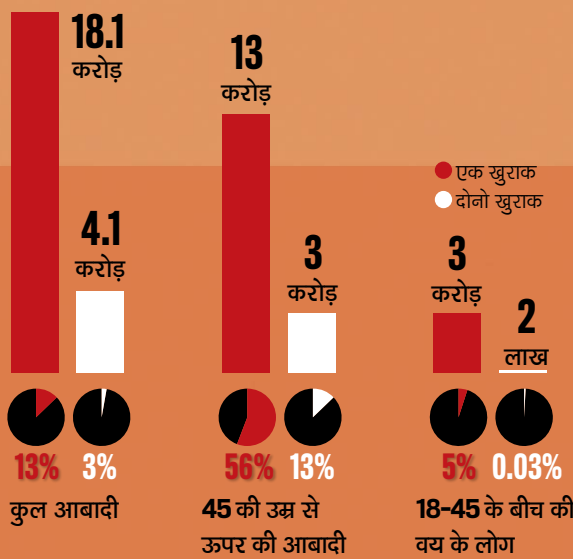

टीकों की खरीद

सौदा पक्का

कोविशील्ड
75 करोड़
कोवैक्सीन
55 करोड़
बायोलोजिकल-ई
30 करोड़
स्पुतनिक
15 करोड़

खरीदे जाने हैं

जाइडस कैडिला
5 करोड़
नोवावैक्स
20 करोड़
बीबी नैसल
10 करोड़
जेनोवा
6 करोड़
फाइजर
अनुपलब्ध
मॉडर्ना
अनुपलब्ध
जेएंडजे
अनुपलब्ध

स्रोतः भारत सरकार के आंकड़े (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य)
ब्लूमबर्ग वर्ल्ड वैक्सीन ट्रैकर. (आंकड़े 8 जून तक के)

इलस्ट्रेशनः
नीलांजन दास

ग्राफिकः
तन्मय चक्रवर्ती

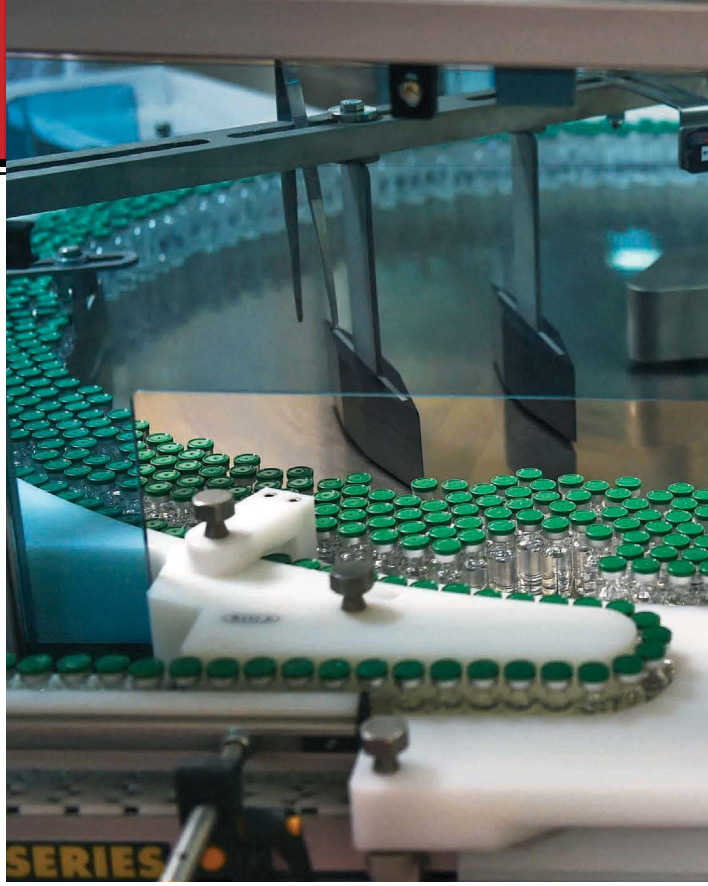

पुनीत परांजपे/एएफपी

अरब के करीब टीके खरीदने होंगे बल्कि लक्ष्य पूरा करने की खातिर इतनी बड़ी आबादी को टीके लगाने के लिए उसे देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को चाक-चौबंद करना होगा. सरकार के एक बड़े अफसर कहते हैं, ''यह टी-20 मैच की तरह है जिसमें अगर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम हर ओवर में जरूरी रन नहीं बनाती है, तो जरूरी रनों की दर बढ़ती जाती है.'' इसलिए अगर किसी भी महीने टीके लगाने का अभियान किसी भी वजह से सुस्त पड़ता है, जैसा कि मई में हुआ, तो रोज टीके लगाने की जरूरी तादाद बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच सकती है. ऐसे में क्या भारत का टीका अभियान नामुमकिन लक्ष्य है?

देश में टीकों की खरीद और वितरण की देखरेख कर रहे शीर्ष निकाय नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 (एनईजीवीएसी) के अध्यक्ष डॉ विनोद के. पॉल को यह लक्ष्य हासिल करने का पूरा भरोसा है. वे कहते हैं, ''यह मिशन मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं. दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने के लिए जरूरी टीकों की जितनी खुराकें चाहिए, वे हम हासिल कर पाए हैं और टीके लगाने की रोजाना क्षमता को तिगुना बढ़ाने के लिए साजो-सामान जुटा रहे हैं, जिनमें ग्रामीण इलाके भी शामिल हैं.'' डॉ. पॉल का भरोसा और जोश बेवजह नहीं है. भारत मई में जितनी नाजुक हालत में था और टीकों की जैसी जबरदस्त कमी थी, उसके मुकाबले एनईजीवीएसी बीते दो महीनों में कड़ी मेहनत करके टीकों की उपलब्धता को ऐसे मुकाम पर ले आया है जहां देश कुछ तसल्ली महसूस कर सकता है. जून-जुलाई के लिए टीकों की 28 करोड़ खुराकें खरीदी जा चुकी हैं.

सरकार ने अपनी इस आलोचना पर ध्यान दिया लगता है कि वह 16 जनवरी को टीका अभियान शुरू करने से पहले पर्याप्त टीकों का ऑर्डर देने में नाकाम रही, जैसा कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप ने किया था. बाद में टीकों की कमी हुई तो उसके लिए यही भूल जिम्मेदार थी. मोदी के ऐलान के एक दिन बाद सरकार ने अहम कदम उठाते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआइआइ) को कोविशील्ड की 25 करोड़ खुराक और भारत बायोटेक लिमिटेड (बीबीएल) को कोवैक्सिन की 19 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया और दोनों को 30 फीसद अग्रिम भुगतान कर दिया. एक अधिकारी ने कहा, ''इससे इस नुक्ताचीनी का समाधान हो जाना चाहिए कि केंद्र अग्रिम ऑर्डर नहीं देकर कंजूसी और घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को हतोत्साहित कर रहा था.'' ये खुराकें अगस्त से मिलनी शुरू हो जानी चाहिए. उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस साल के अंत तक कोविशील्ड की 25 करोड़ और कोवैक्सिन की 20 करोड़ अतिरिक्त खुराकों के ऑर्डर भी देगी.

इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्बिवैक्स की 30 करोड़ खुराकें खरीदने के लिए परिपाटी से हटकर 1,500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया. हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई इस वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है और अमेरिका स्थित बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ने इसका विकास किया है. भारत के केंद्रीय औषधि मानक संगठन या सीडीएससीओ ने अप्रैल के मध्य में बायोलॉजिकल ई को विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) के अधीन तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दी. इससे पहले पिछले चरणों के परीक्षण कामयाबी के साथ हो चुके थे. तीसरे चरण के ये परीक्षण भारत भर में 15 स्थलों पर 18 से 80 साल के बीच के 1,268 स्वस्थ लोगों पर किए जाने हैं. बाद में कहीं ज्यादा व्यापक तीसरे चरण के वैश्विक परीक्षणों की योजना है.

इस बीच उम्मीद की जा रही है कि सरकार रूस की स्पुतनिक 5 की करीब 15 करोड़ खुराकें खरीदेगी. भारत में रूसी वैक्सीन की पहली 25 करोड़ खुराकों के विपणन और वितरण के पूरे अधिकार डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज के पास हैं. इस वैक्सीन की मिल्कियत रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के पास है और उसने साल में 85 करोड़ से ज्यादा खुराकें बनाने के लिए भारत के ग्लैंड फार्मा (25.2 करोड़ खुराक), स्ट्राइड्स आर्कोलैब्स स्टेलिस (20 करोड़ खुराक), विरचोव बायोटेक (20 करोड़ खुराक), पैनीशिया बायोटेक और हेटेरो ड्रग्ज (हरेक 10 करोड़ खुराक) के साथ मैन्युफैक्चरिंग के समझौते किए हैं.

"टीके लेकर हमें लोगों के पास पहुंचना होगा, अगर जरूरत महसूस हुई तो उनके दरवाजे तक भी जाना होगा, जिससे टीका लगवाने के लिए उन्हें मारामारी न करनी पड़े"

भ्रमर मुखर्जी
प्रोफेसर, एपिडेमियोलॉजी,
यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन

पूरी रफ्तार पर पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड की एसेंबली लाइन

"बेशक यह मुश्किल लक्ष्य है लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं. दिसंबर के अंत तक लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने टीकों का इंतजाम कर लिया है और अब टीकाकरण की रोजाना की रफ्तार तीन गुना करने के उपाय कर रहे हैं"

डॉ. वी.के. पॉल
चेयरमैन, एनईजीवीएसी

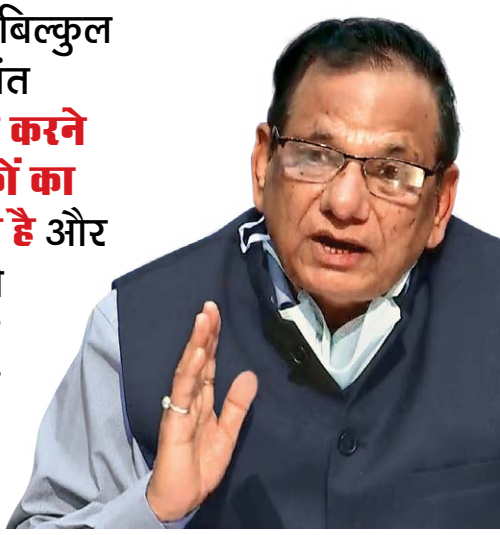

हाल में एसआइआइ को भी भारत में स्पुतनिक बनाने की इजाजत मिली है.

इन सारे सौदों के साथ केंद्र सरकार ने अगले सात महीनों में 1.62 अरब खुराकों की सप्लाइ का भरोसा हासिल कर लिया है, जो देश की पूरी वयस्क आबादी को टीके लगाने के लिए काफी है.

नई वैक्सीनों की आहट

इस बीच मोदी सरकार ने कुछ नई वैक्सीन की खरीद पर भी काम शुरू कर दिया है, ताकि तयशुदा खरीद में कोई देरी या कमी हो तो उसकी भरपाई की जा सके. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के टीके लगाने के मंसूबों में एक बड़ी गड़बड़ी यह रही कि देश में विकसित पहले स्वदेशी कोविड टीके 'कोवैक्सिन' का उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं किया या बढ़ाया नहीं जा सका. भारत बायोटेक के विकसित और निर्मित कोवैक्सिन के 16 जनवरी से अब तक केवल 2.07 करोड़ या महीने में औसतन 54 लाख इंजेक्शन ही दिए जा सके हैं. हालांकि कंपनी का दावा है कि उसने मार्च से अब तक 6 करोड़ टीके बनाए हैं. इस गफलत की वजह से भारत बायोटेक को सफाई देनी पड़ी कि उसकी वैक्सीन के लिए उत्पादन की शुरुआत से टीके लगाने के लिए वितरण तक चार महीनों का वक्त चाहिए. मतलब कि इस साल मार्च में कोवैक्सिन की जिस खेप का उत्पादन शुरू हुआ था, वह इस महीने आपूर्ति के लिए तैयार हो पाएगी. कंपनी अतिरिक्त मांग पूरी करने को हैदराबाद और बेंगलूरू में उत्पादन सुविधाएं बढ़ा रही है.

चूंकि कोवैक्सिन भारत सरकार के सहयोग से सह-विकसित की गई है, इसलिए केंद्र ने उत्पादन बढ़ाने के लिए इसे बनाने का काम सार्वजनिक क्षेत्र की तीन कंपनियों—इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स लि. (आइआइएल), हैफकाइन इंस्टीट्यूट और भारत इम्युनोलॉजिकल्स ऐंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लि. (बीआइबीसीओएल)—को सौंपा है. मगर इसके नतीजे तत्काल नहीं मिलेंगे. महाराष्ट्र सरकार की मिल्कियत वाली हैफकाइन इंस्टीट्यूट साल में कोवैक्सिन की 22.8 करोड़ खुराकें बनाना चाहती है. राज्य सरकार का कहना है, उसे कोवैक्सिन बनाने के लिए बेहद जरूरी बीएसएल-3 जैवसुरक्षा प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आठ महीने का वक्त चाहिए. उम्मीद है कि आइआइएल और बीआइबीसीओएल दोनों मिलकर हर माह 1-1.5 करोड़ खुराकें बनाएंगी, जिसकी शुरुआत अगस्त या सितंबर से होगी.

अच्छी खबर यह है कि भारत में बनाई जा रही कई नई वैक्सीन ने बहुत अच्छी संभावनाएं दिखाई हैं और वे भारत की टीके की खोज में जरूरी सहारा दे सकती हैं. सबसे उत्साहजनक घटनाओं में से एक अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला की मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन है. यह तीन खुराकों वाली डीएनए वैक्सीन है और इसके अंतिम चरण के परीक्षणों का डेटा और उसके साथ अगस्त में लॉन्च करने की योजना जल्द ही औषधि नियामक को सौंप दी जाएगी. जायडस की योजना महीने में 1 करोड़ खुराकों के साथ शुरू करके बाद के महीनों में अपनी क्षमता दोगुनी बढ़ाने की है. भारत सरकार का गणित यह है कि दिसंबर से पहले उसे इसकी 5 करोड़ खुराकें मिलेंगी. ग्रुप के चेयरमैन पंकज पटेल कहते हैं, ''चूंकि यह डीएनए वैक्सीन है, इसलिए इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाना आसान है और यह वायरस के म्यूटेशन का बड़ी हद तक प्रतिकार कर सकती है.'' 12 से 17 साल के बीच के किशोरों पर भी इसके परीक्षण हो रहे हैं. इसकी एक अनूठी खूबी है—इसे सुई से लगाने की जरूरत नहीं; यह खास तरकीब से त्वचा के नीचे इंजेक्ट की जाती है.

अगली वैक्सीन एसआइआइ और अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी नोवावैक्स की प्रोटीन आधारित कोवोवैक्स है. इसके तीसरे चरण के परीक्षण जल्द शुरू होने हैं और इसे सितंबर में लॉन्च करने की योजना है. यूरोप में इसके तीसरे चरण के परीक्षण हो चुके हैं. एसआइआइ के मालिक और सीईओ अदर पूनावाला कहते हैं, ''कोविड वायरस के

एक नजर टीकों पर

अब बाजार में कई किस्म के टीके हैं और कई अभी विकसित किए जा रहे हैं

कोविशील्ड

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआइआइ) ने इसे विकसित किया, उत्पादन भी कर रहा

प्रकार: वायरल वेक्टर वैक्सीन

प्रभाव: 70 फीसद, भारत में दो खुराकों के बीच मौजूदा फासले के साथ

वैश्विक उपयोग: 102 देशों में उपयोग के लिए स्वीकृत

भारत में कब तक आने की उम्मीद: पहले से ही इस्तेमाल हो रहा

कोवैक्सिन

भारत बायोटेक और आइसीएमआर ने विकसित किया और बना रहे. उत्पादन का काम तीन पीएसयू– इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स, हैफकाइन इंस्टीट्यूट और भारत इम्यूनोलॉजिकल्स–को सौंपने की योजना है

प्रकार: होल-वायरियन इनएक्टीवेटेड वीरो सेल वैक्सीन

प्रभाव: बीमारी को रोकने में कुल अंतरिम प्रभाव 78 फीसद; मृत्यु रोकने में 100 फीसद

वैश्विक उपयोग: नौ देशों में इस्तेमाल के लिए स्वीकृत

भारत में कब तक आने की उम्मीद: पहले से उपयोग में लिया जा रहा

कोर्बिवैक्स

हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई इसका उत्पादन कर रहा. अमेरिका स्थित बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के नेशनल स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ने विकसित किया

प्रकार: रीकॉम्बिनैंट प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन

प्रभाव: भारत भर के 15 शहरों में 18 से 80 वर्ष की उम्र के बीच करीब 1,268 स्वस्थ लोगों पर तीसरे चरण के परीक्षण जारी

वैश्विक उपयोग: अभी उपलब्ध नहीं

भारत में कब तक आने की उम्मीद: सितंबर 2021 तक. केंद्र सरकार ने 30 करोड़ खुराक का ऑर्डर पहले ही दे दिया है

स्पुतनिक 5

रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से विकसित, भारत में ग्लैंड फार्मा (25.2 करोड़ खुराक), स्ट्राइड्स आर्कोलैब्स स्टेलिस (20 करोड़ खुराक), विरचोव बायोटेक (20 करोड़ खुराक), पैनैशिया बायोटेक और हेटेरो ड्रग्ज (10 करोड़ खुराक प्रत्येक) ने इसका उत्पादन किया है. भारत में विपणन और वितरण के अधिकार डॉ. रेड्डीज लैब ने ले रखे हैं

प्रकार: एडीनोवायरल आधारित दो हिस्सों वाली वैक्सीन

प्रभाव: बीमारी को रोकने में 91 फीसद तक कारगर

वैश्विक उपयोग: 68 देशों में इस्तेमाल के लिए स्वीकृत

भारत में कब तक आने की उम्मीद: प्रायोगिक पैमाने पर मई 2021 के मध्य में शुरू

जायकोव डी

जायडस कैडिला ने विकसित और उत्पादन भी कर रहा

प्रकार: तीन खुराक वाली प्लास्मिड डीएनए वैक्सीन

प्रभाव: अंतिम चरण के परीक्षणों के परिणाम शीघ्र ही प्रस्तुत होने हैं

वैश्विक उपयोग: उपलब्ध नहीं

भारत में कब तक आने की उम्मीद केंद्र दिसंबर 2021 तक 5 करोड़ खुराक की उम्मीद कर रहा है

कोवोवैक्स

एसआइआइ और अमेरिकी फर्म नोवावैक्स ने विकसित किया और उत्पादन भी कर रहीं

प्रकार: प्रोटीन आधारित वैक्सीन

प्रभाव: 89 फीसद, यूरोप में तीसरे चरण के परीक्षणों के आधार पर

वैश्विक उपयोग: उपलब्ध नहीं

भारत में कब तक आने की उम्मीद: 2021 के अंत में

बीबी नैजल

भारत बायोटेक से विकसित और निर्मित

प्रकार: इंट्रानैजल वैक्सीन

प्रभाव: पहले चरण के परीक्षण चल रहे हैं

वैश्विक उपयोग: उपलब्ध नहीं

भारत में कब तक आने की उम्मीद: परीक्षण सफल रहे तो दिसंबर 2021 तक

अफ्रीकी और ब्रिटिश रूपों के खिलाफ इसके परीक्षण हुए हैं और इसका कुल असर 89 फीसद है.'' फर्म की योजना भारत में साल में करीब 75 करोड़ खुराक बनाने की है और 'जोखिम के साथ' परीक्षण उत्पादन शुरू हो चुका है. उत्पादन के पहले साल में भारत इस वैक्सीन की 20 करोड़ खुराकें पाने की उम्मीद कर रहा है.

भारत सरकार के पैसों से चलने वाला एक और वैक्सीन प्रोजेक्ट पुणे स्थित एमक्योर फार्मास्युटिकल्स की सहयोगी बायोटेक कंपनी जेनोवा बायोफार्मास्युटिकल्स का प्रोजेक्ट है. यह भारत की पहली एमआरएनए कोविड-19 वैक्सीन (फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन से मिलती-जुलती) पर काम कर रहा है. इसके पहले चरण के परीक्षण चल रहे हैं, जो दो महीने में पूरे होंगे. दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण में और दो महीने लगेंगे. उम्मीद है कि वैक्सीन इसी साल लॉन्च होगी. सरकार को उम्मीद है कि जेनोवा इस साल उसे 6 करोड़ खुराकें उपलब्ध करवाएगी. इसकी कामयाबी के आधार पर सरकार ने वैक्सीन के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है.

इतनी ही उत्साहजनक बीबीएल की इंट्रानैजल या नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन बीबीवी154 है. इसके पहले दौर के नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं. यह गेम-चेंजर होगी, क्योंकि यह संक्रमण की जगह पर प्रतिरोधक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है और वायरस के संक्रमण और फैलाव दोनों को रोक सकती है. बीबीएल के चेयरमैन डॉ. कृष्णा ऐल्ला कहते हैं, ''मैं आसानी से एक अरब खुराकें बना सकता हूं क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन आसान है.'' सरकार का मंसूबा इस साल इस नैजल वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकें खरीदने का है.

बड़ी फार्मा कंपनियों से बातचीत

केंद्र शीर्ष विदेशी फार्मास्युटिकल कंपनियों से भी बात कर रहा है. इनमें फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन ऐंड जॉनसन भी हैं, जो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप में कोविड वैक्सीन कामयाबी के साथ लॉन्च कर चुकी हैं. उम्मीद है कि वैक्सीन के आयात में तेजी आएगी, खासकर अब जब भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआइ) ने पिछले हफ्ते कोविड-19 वैक्सीन के आयात के नियमों में और ढील दे दी है. औषधि नियामक ने मंजूरी के बाद अनिवार्य ब्रिजिंग या सीमित नैदानिक परीक्षणों और आयातित वैक्सीनों की हरेक खेप की हिमाचल प्रदेश में कसौली स्थित भारत की केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) से जांच करवाने से छूट दी है. नई दवाइयों और टीकों के लिए पहले के नियम कहते थे कि जो दवाई और टीके देश से बाहर तीसरे चरण के अध्ययन पूरे कर चुके हैं, उन्हें भारत की आबादी पर 'ब्रिजिंग' या सीमित नैदानिक परीक्षण करने होंगे ताकि यह जाना जा सके कि भारतीय मूल के लोगों पर वह टीका कितना कारगर है.

देश में कोविड-19 वैक्सीन की भारी कमी को देखते हुए इस अनिवार्यता को विदेशी वैक्सीनों को भारत लाने में बड़ी बाधा और देरी की वजह के तौर पर देखा जा रहा था. डीसीजीआइ ने 15 अप्रैल को एनईजीवीएसी की सिफारिश के मुताबिक इन नियमों में कुछ हद तक ढील दी थी. उसने उन कोविड-19 वैक्सीनों को इजाजत दे दी, जिन्हें अमेरिकी एफडीए, ईएमए (यूरोप), ब्रिटेन की एमएचआरए, जापान की पीएमडीए या डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन उपयोग सूची (ईयूएल) में दर्ज दूसरी नियामक एजेंसियां सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दे चुकी हैं.

सूत्रों के मुताबिक, सिप्ला और वॉकहार्ड सरीखी कंपनियां मॉडर्ना और फाइजर जैसी अपनी समकक्ष कंपनियों से उनकी वैक्सीन भारत में आयात और मैन्युफैक्चर करने के लिए बात कर रही हैं. जेऐंडजे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के गठजोड़ क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप के तहत

एमआरएनए-1273

मॉडर्ना ने विकसित किया और उत्पादन कर रही

प्रकार: एमआरएनए वैक्सीन

प्रभाव: 92 फीसद

वैश्विक उपयोग: 49 देशों में इस्तेमाल के लिए स्वीकृत

भारत में कब तक आने की उम्मीद: कंपनी के साथ केंद्र की बातचीत चल रही है

बीएनटी162बी2

फाइजर और बायोएनटेक ने विकसित किया, उत्पादन भी वहीं

प्रकार: एमआरएनए वैक्सीन

प्रभाव: 95 फीसद, पहली खुराक के 28 दिन बाद प्रभाव शुरू

वैश्विक उपयोग: 85 देशों में उपयोग के लिए स्वीकृत

भारत में कब तक आने की उम्मीद: कंपनी के साथ केंद्र की बातचीत चल रही है

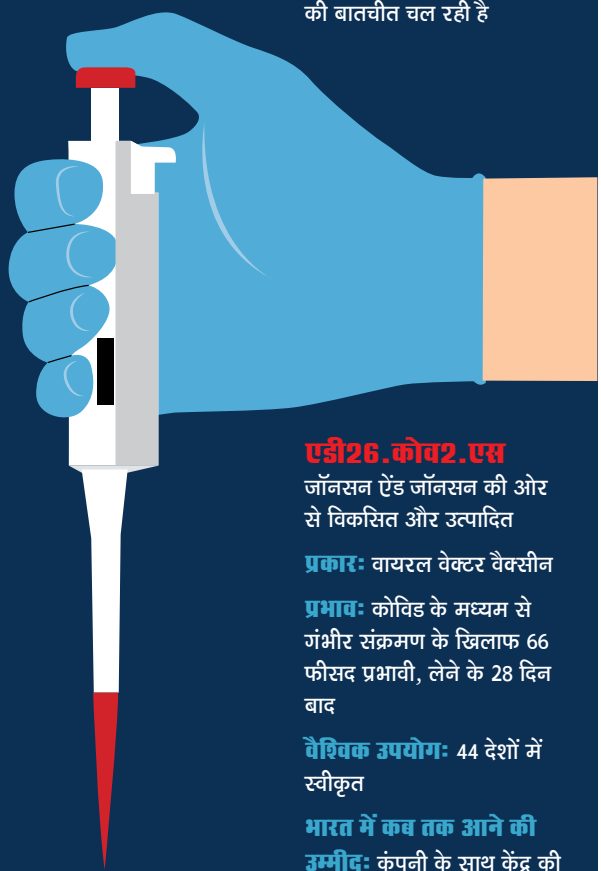

एडी26.कोव2.एस

जॉनसन ऐंड जॉनसन की ओर से विकसित और उत्पादित

प्रकार: वायरल वेक्टर वैक्सीन

प्रभाव: कोविड के मध्यम से गंभीर संक्रमण के खिलाफ 66 फीसद प्रभावी, लेने के 28 दिन बाद

वैश्विक उपयोग: 44 देशों में स्वीकृत

भारत में कब तक आने की उम्मीद: कंपनी के साथ केंद्र की बातचीत चल रही है

ग्राफिक: तन्मय चक्रवर्ती

सुमित सारस्वत/गेट्टी इमेजेज

ठेठ गांवों तक राजस्थान में ब्यावर के मालपुरा गांव में मई में टीकाकरण अभियान का एक दृश्य

"निजी क्षेत्र के पास 25 फीसद टीकों की खरीद का अधिकार बरकरार रहने से उद्योग जगत को टीकाकरण अभियान में भूमिका निभाने और अपने श्रमिकों तक भी उन्हें पहुंचाने में मदद मिलेगी"

टी.वी. नरेंद्रन
सीईओ और एमडी, टाटा स्टील,
अध्यक्ष, सीआइआइ

अपनी सिंगल-शॉट वैक्सीन की एक अरब से ज्यादा खुराकें भारत में बनाने की योजना बना रही है, जिनका इस्तेमाल 2022 के अंत तक एशियाई देशों में किया जाएगा. बायोलॉजिकल ई जेऐंडजे वैक्सीन की सालाना करीब 60 करोड़ खुराकें ठेके पर बनाने पर विचार कर रही थी, पर उसने अब तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की योजनाओं का खुलासा नहीं किया है.

केंद्र मानता है कि इन तमाम उपायों के साथ वैक्सीन के मोर्चे पर उसे कामयाबी मिलेगी. प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ पी.के. मिश्र कहते हैं, ''130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाना चुनौती भरा काम है, न केवल पैमाने और रफ्तार के लिहाज से, बल्कि बहुत सारी सप्लाइ चेन और स्थानीय बाध्याताओं के बीच दक्षता के साथ अंतिम छोर तक पहुंच पक्की करने के लिहाज से भी. हमें स्वीकार करना होगा कि कोविड के टीके आपातकालीन उपयोग के अधिकार के तहत लगाए जा रहे हैं और यह पूरा काम पोलियो सरीखे नियमित टीकाकरण कार्यक्रमों के मुकाबले कहीं ज्यादा पेचीदा है. हम उत्पादन बढ़ाने और विविधता लाने और दूसरी जगहों पर स्वीकृत नई वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए कई रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं. हमें पूरा विश्वास है कि हम इस साल के आखिर तक सभी वयस्कों को टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे और ऐसा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे.''

टीका लगवाने की हिचक दूर करना

टीके की आपूर्ति की अड़चनों को दूर कर दिया गया है, असली समस्या 31 दिसंबर की समय सीमा को पूरा करने की होगी क्योंकि इसके लिए टीकाकरण अभी के 27 लाख रोज से बढ़ाकर 80 लाख रोज तक ले जाना होगा. निस्संदेह, यह बहुत बड़ी चुनौती है, जो लोगों में टीके लगवाने को लेकर झिझक को देखते हुए कहीं बड़ी हो जाती है. मोदी ने भाषण में कहा कि 2012 तक, बच्चों के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआइपी)

में लगभग 60 प्रतिशत आबादी ही कवर होती थी. प्रधानमंत्री ने खासतौर पर इस बात का उल्लेख किया कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद, कवरेज को 90 प्रतिशत तक बढ़ाया गया. अब, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पक्का करना है कि कम से कम 90 प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण हो. यह संभावित तीसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रतिरक्षा (हर्ड इम्यूनिटी) शक्ति प्रदान करेगा. यह पीड़ितों में बीमारी की गंभीरता को भी कम करेगा और इस तरह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर बोझ को घटाएगा. एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं, ''हर्ड इम्युनिटी विकसित करने के दो तरीके हैं. खराब तरीका यह है कि आबादी को बीमारी हो जाए और उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण हो जाए. श्रेष्ठ तरीका यह है कि एक व्यवस्थित और व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से आबादी में प्रतिरक्षा शक्ति निर्मित की जाए.''

एनईजीवीएसी के डॉ. पॉल का मानना है कि चुनाव करवाने और यूआइपी के अनुभव को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक को निष्पादित करने के लिए सबसे बेहतर स्थिति में है. वे कहते हैं, ''राज्य सरकारों ने बहुत भरोसे के साथ कहा है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगी.'' टीकाकरण के मौजूदा दौर में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश पहले ही दिखा चुका है कि यह रोज 18 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर सकता है और मांग को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने भी ऐसी ही क्षमताएं दिखाई हैं. टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशाल ग्रामीण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सशक्त करना होगा. इसमें लगभग 700 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के अलावा 10 लाख आशा कार्यकर्ता और 3,00,000 एएनएम शामिल हैं. जैसा कि मिशिगन विश्वविद्यालय में महामारी विज्ञान की प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी कहती हैं, ''जरूरत पड़ने पर हमें सीधे लोगों के घरों तक जाकर टीके लगाने चाहिए ताकि उन्हें टीके पाने के लिए धक्कामुक्की और संघर्ष न करना पड़े.'' पॉल इससे सहमत हैं और कहते हैं कि टीके को लेकर लोगों की झिझक दूर करने के लिए जनांदोलन की जरूरत है. इसमें देशभक्ति के वैसे ही जज्बे की जरूरत होगी जो युद्ध के दौरान देखने को मिलता है.

राज्यों के लिए टीकों की खरीद और वितरण में पारदर्शिता भी उतनी ही अहम है. केंद्र ने आबादी और आयु समूहों के आधार पर राज्यों से टीकों के वितरण के लिए एक फॉर्मूला बनाया है. इसमें टीके का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है. मुखर्जी का कहना है कि टीकाकरण के लिए अनुरोध दर्ज करने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म को और अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए ताकि जो लोग तकनीक के इस्तेमाल में सहज नहीं हैं वे इससे वंचित न रह जाएं. निजी क्षेत्र अब इस काम के लिए आगे बढ़ रहा है. हालांकि सरकार ने मई में निजी वैक्सीन बाजार खोल दिया, लेकिन मुख्य रूप से वैक्सीन की कमी और छोटे तथा मध्यम श्रेणी के अस्पतालों की निर्माताओं के साथ सीधे बातचीत करने में अक्षमता के कारण यह गति नहीं पकड़ पाया है. इससे टीकाकरण में शामिल निजी अस्पतालों की संख्या 7,000 से घटकर लगभग 2,000 रह गई है. कुल मिलाकर, टीकाकरण में निजी क्षेत्र का हिस्सा 23 प्रतिशत रहा और यह महत्वपूर्ण है कि निजी क्षेत्र उस गति को बरकरार रखे. उद्योग जगत को भी इसके लिए कदम आगे बढ़ाने चाहिए. टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक और भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन कहते हैं, ''टीके की खरीद का 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र के लिए बनाए रखने से उद्योग टीकाकरण अभियान में योगदान कर सकेंगे और अपने श्रमिकों को लक्षित कर सकेंगे''

"टीकाकरण अपने आकार, गति और अंतिम छोर तक पहुंच को पुख्ता करने के लिहाज से बेहद महत्वाकांक्षी अभियान है. हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि 2021 के अंत तक हम सभी वयस्कों का टीकाकरण करवा पाने में कामयाम होंगे"

डॉ. पी.के. मिश्र
प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव

तीसरी लहर को दूसरी लहर जैसा विनाशकारी होने से बचाने में टीकाकरण अभियान अहम साबित होगा. सो इसे गति देने और यह पक्का करने की जरूरत है कि अगली लहर के दस्तक देने से पहले अधिक से अधिक लोगों को टीके लग जाएं. मुखर्जी कहती हैं, ''दूसरी लहर के थम जाने से हमें राष्ट्रीय स्तर पर बहुत खुश और संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए. बल्कि हमें कोविड-उपयुक्त व्यवहार का सख्ती से पालन करने के अलावा टीके जैसे निवारक उपायों की दिशा में कड़ी मेहनत करनी होगी.'' यह चेतावनी दिल्ली में क्रमिक अनलॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद फिर से उमड़ी भारी भीड़ के बाद आई है. एक अधिकारी कहते हैं, वायरस समाप्त नहीं हुआ है. यह अभी भी अतिसंवेदनशील लोगों की तलाश में है और एक और उछाल का कारण बन सकता है. दूसरी लहर ने यह भी दिखाया कि अगर शुरुआत में केवल कुछ राज्य ही प्रभावित होते हैं, तो भी यह आसानी से देश के बाकी हिस्सों में फैल जाता है. इसलिए, हमें न केवल पूर्व चेतावनी प्रणाली की दरकार है, बल्कि राज्यों को भी क्रमिक लॉकडाउन उपायों को अपनाने की जरूरत है. जांच और संक्रमित मिले लोगों की ट्रैकिंग तथा उन्हें अलग करना भी उतना ही अहम है. विशेष रूप से ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पक्की करने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है. वायरस के विभिन्न वेरिएंट एक चुनौती बने रहेंगे और वे टीकाकरण कार्यक्रमों को कमजोर करने और नए सिरे से संक्रमण के मामलों में उछाल लाने की क्षमता रखते हैं. सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम वायरस को नियंत्रण में रखने और तीसरी लहर के हम पर हावी होने से पहले तैयारियां करने में कितने सक्षम हो पाते हैं. टीकाकरण ही हमारा एकमात्र प्रभावी कवच है. अगर आत्मसंतुष्ट होने के कारण हम विफल रहते हैं तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. ■

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

यूपी की धान खरीद व्यवस्था में कई छेद
लालफीताशाही के शिकंजे में कारोबार
सरना: पुराने धर्म पर नई बहस
इंडिया टुडे
कोविड-19 वैक्सीन
कितनी सुरक्षित? कितनी कारगर?
बाजार में आने के लिए तैयार नई वैक्सीन से जुड़े सारे अहम सवालों के जवाब

राम मंदिर को माना गया मोदी की प्रमुख उपलब्धि
अनुच्छेद 370 हटाने को मिला जोरदार समर्थन
बेरोजगारी मानी गई सबसे बड़ी समस्या
इंडिया टुडे
देश का मिजाज सर्वेक्षण
मोदी और हिंदुत्व का बोलबाला
देशव्यापी छमाही सर्वेक्षण से जाहिर है कि नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर बरकरार हैं और संघ परिवार के एजेंडे को मिली जबरदस्त बढ़त

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 25% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	3 वर्ष	156	~~6240~~	4680	25%
☐	2 वर्ष	104	~~4160~~	3330	20%
☐	1 वर्ष	52	~~2080~~	1770	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.....है और इसे दिनांक..... को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में ..... (बैंक का नाम).....रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम..... पता.....

..... शहर..... राज्य..... पिन.....

मोबाइल..... ईमेल.....

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें 18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें www.indiatoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

मेघना शास्त्री/गेट्टी इमेजेज

खैर-खबर ↑
बेंगलूरू के एक स्वास्थ्य केंद्र में एक किशोर के ब्लडप्रेशर की जांच करता डॉक्टर

कितने महफूज हैं बच्चे

कोविड केयर और टीकाकरण के मामले में वयस्कों को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन बच्चों में संक्रमण के जोखिम को शायद नजरअंदाज कर दिया गया है

सोनाली आचार्जी

यही कोई 13 बरस की सनाया कुकरेजा (बदला हुआ नाम) को आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाने के लिए मनाने में माता-पिता को बहुत मुश्किलें पेश आईं. उनकी मां हैदराबाद से फोन पर बताती हैं, ''हमें कहा गया कि बच्चों को कोविड नहीं होगा, इसलिए हमने टेस्ट या दवाइयों पर जोर नहीं दिया.'' छह दिन बाद बुखार तो आखिरकार उतर गया और दूसरे लक्षण भी गायब हो गए. पर दो हफ्ते बाद सनाया को छाती में तेज दर्द हुआ. परिजन उन्हें हैदराबाद के अपोलो अस्पताल ले गए. पता चला कि उन्हें बच्चों में होने वाला एमआइएस-सी या मल्टी-सिस्टम इन्फ्लेमैटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन था, जिसमें कोविड से उबरने के 2-6 हफ्ते बाद बच्चों के बेहद अहम अंगों में सूजन आ जाती है और वक्त पर इलाज न करें तो जानलेवा हो सकती है.

हालांकि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो पक्का बता सके कि पहली के मुकाबले दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा संक्रमित हुए, मगर

यासिर इकबाल

राज्यों के आंकड़े तस्दीक करते हैं कि संक्रमण नौनिहालों में फैल चुका है. कर्नाटक में मार्च 2020 और सितंबर 2020 के बीच पहली लहर के शिखर पर होने के दौरान 10 साल से छोटे बच्चों में संक्रमण के 19,378 मामले आए. तब से इस साल 20 मई तक राज्य में इस आयु समूह के 49,257 मामले आए हैं. महाराष्ट्र में 23 मई को कुल 55.6 लाख मामलों में से 1,71,335 या 3.1 फीसद मामले 10 से कम उम्र के बच्चों में थे. दिल्ली में 18 साल से छोटे बच्चों में संक्रमण बढ़ते देख मैक्स सरीखे कुछ अस्पतालों ने बच्चों के अलग वार्ड और आइसीयू बनाए. उत्तराखंड में 1-15 मई के बीच नौ साल तक की उम्र के 1,579 बच्चे संक्रमित हुए. इनमें नवजात से दो साल के शिशु भी शामिल थे.

दिल्ली के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएफएचआइ) के महामारी विशेषज्ञ गिरिधर बाबू कहते हैं, ''वायरस नाजुक और बेहद संवेदनशील लोगों को खोज ही लेगा. ज्यादातर बड़े लोग संक्रमित हो चुके हैं या उन्हें टीके लग चुके हैं, इसलिए वायरस उन लोगों को संक्रमित करता रहेगा जो सुरक्षित नहीं हैं. संक्रमण जारी है, इसलिए यह बच्चों सहित कम आयु समूह के ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाता रह सकता है.''

डॉक्टर तस्दीक करते हैं कि बच्चों में कोविड के मामले बड़ी तादाद में दिख रहे हैं लेकिन वे पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये पहले वाले या नए स्ट्रेन की वजह से हैं. मुलुंड मुंबई के फोर्टिस अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनैटल इंटेंसिव केयर विशेषज्ञ डॉ. जेसल सेठ कहती हैं, ''इतने ज्यादा मामले जरूरी नहीं कि अकेले कोविड स्ट्रेन की वजह से हों. वे बच्चों के कोविड के माकूल व्यवहार न करने से भी हो सकते हैं. जनवरी और फरवरी 2021 में खूब सामाजिक मेलजोल हुआ. कुछ स्कूल भी खुल गए.''

क्या कोविड बच्चों में ज्यादा गंभीर है?

डॉक्टरों को अब भी पक्का पता नहीं कि बच्चों में कोविड के गंभीर लक्षण विकसित हो सकते हैं या नहीं. अब तक की जानकारी से पता चलता है कि बहुतायत संक्रमित बच्चे बगैर लक्षणों वाले या हल्के लक्षणों वाले थे. पटपड़गंज दिल्ली के मैक्स सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग के प्रमुख डॉ. श्याम कुकरेजा कहते हैं, ''बच्चों को बड़ों जितना ही कोविड संक्रमण हो सकता है. पर जरूरी नहीं कि गंभीर रूप में ही हो. बहुत कम संभावना है कि मौजूदा लहर मुख्य रूप से या पूरी तरह बच्चों को ही प्रभावित करेगी. बुखार, गले में खराश, खांसी सरीखे सामान्य लक्षण हो सकते हैं.'' देश के 32,000 से ज्यादा बालरोग विशेषज्ञों की नुमाइंदगी करने वाली आइएपी (इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स) ने भी तस्दीक की है कि कम से कम 90 फीसद कोविड पॉजिटिव बच्चों में लक्षण बहुत हल्के या बिल्कुल नहीं होंगे. हां, विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि अगर कोविड बेलगाम बढ़ता है तो 5-10 फीसद के अस्पतालों में दाखिल होने से भी व्यवस्था पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है.

कोलकाता की बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. मधुरा चटर्जी छोटे बच्चों के इलाज की चुनौतियां बताती हैं: ''रेडिएशन के खतरे की वजह से आप बढ़ते बच्चों का सीटी स्कैन तब तक नहीं कर सकते जब तक बिल्कुल जरूरी न हो. अस्पताल में दाखिल होने भर से बच्चे के मन में कुछ सदमा लगता ही है. हमारे यहां देश में वयस्क आइसीयू के मुकाबले पीडियाट्रिक और नियोनैटल आइसीयू भी बहुत कम हैं.'' मसलन, उत्तर प्रदेश में गंभीर रूप से बीमार बच्चों के इलाज के लिए 78 नवजात देखभाल इकाइयां (हरेक में 12 बिस्तर) हैं. दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में पीडियाट्रिक विभाग की प्रमुख डॉ. उर्मिला झांब कहती हैं कि उन्होंने इस साल गंभीर लक्षणों वाले 40 बच्चे भर्ती किए, जिनमें 15 शिशु थे. ''हमारे यहां इस साल केवल वही बच्चे थे जिन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के सहारे की जरूरत थी.'' पिछले साल अस्पताल ने 400 बच्चों का इलाज किया था, पर इनमें कोविड पॉजिटिव बच्चे भी शामिल थे.

बच्चों में कोविड क्यों चिंता का विषय है

कुकरेजा कहते हैं, ''बच्चों में लक्षण प्राय: नहीं दिखने से संक्रमण का पता लगाना अपने आप में चुनौती है.'' और समय पर उनकी जांच न कराई गई तो यह घर के दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए भी जोखिमपूर्ण हो सकता है क्योंकि बच्चों से संक्रममण बहुत तेजी से फैलता है. नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉल के अनुसार, भले ही पिछली लहर में बच्चों में कोविड के मामले कम देखे गए थे, जनवरी और दिसंबर में हुए सीरोपॉजिटिविटी सर्वे से पता चला है कि 10 से 18 वर्ष के बच्चों (21.4 प्रतिशत) में भी कोविड संक्रमण की दर लगभग वही थी जो 18 से ऊपर (25.3 प्रतिशत) के लोगों में थी. यानी, बड़ी संख्या में बच्चे संक्रमित थे पर उनमें लक्षण स्पष्ट नहीं दिखे.

जांच में संक्रमित पाए जाने पर सभी बाल रोग विशेषज्ञ जोर देते हैं कि माता-पिता उन्हें वे दवाएं न दें जो वयस्कों के लिए हैं (देखें बॉक्स: बच्चे को कोविड होने पर क्या करें). एक वरिष्ठ बाल चिकित्सक और दिल्ली के अपोलो अस्पताल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉ. अनुपम सिब्बल कहते हैं, ''किसी बच्चे में कोविड के लक्षण हैं, तो जांच के बाद डॉक्टर के परामर्श से ही इलाज शुरू करें, अपनी मर्जी से नहीं. हल्के संक्रमण के लिए अभिभावकों को पहले से बताया जाना चाहिए कि उन्हें कब डॉक्टर से परामर्श करना है और बच्चे की स्थिति पर किस प्रकार कड़ी नजर रखनी है.''

संक्रमण से उबरने के बाद की जटिलताएं भी एक खतरा बनी रहती हैं. अगर बच्चों को समय पर अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता है तो एमआइएस-सी के साथ-साथ फंगस और बैक्टीरिया के कारण होने वाले अन्य संक्रमण भी बच्चों के लिए घातक हो सकते हैं. डॉ. कुकरेजा के मुताबिक, संक्रमणों की शीघ्र पहचान, कोविड के बाद की जटिलताओं के इलाज का एकमात्र तरीका है. कोविड विशेषज्ञों, बाल चिकित्सा देखभाल इकाइयों वगैरह की सीमित संख्या को देखते हुए यह मुश्किल हो सकता है.

नवजातों में कोविड

अब तक, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों में कोविड के कारण मौत के मामले बहुत कम सुनने को मिले हैं लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि

बच्चे को कोविड होने पर क्या करें

- आपके बच्चे को अगर लगातार चार दिन से ज्यादा बुखार रहता है तो किसी डॉक्टर से तुरंत सलाह लें
- अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य पहले से ही ढीला-ढाला चल रहा है तो फिर कोविड का कोई भी लक्षण दिखाई देते ही किसी डॉक्टर से संपर्क स्थापित करें
- वयस्कों के लिए निर्धारित दवाएं देकर आप खुद ही बच्चे का इलाज शुरू करने की भूल कभी न करें
- खांसी और बुखार के हल्के लक्षणों वाले बच्चों का इलाज जरूर घर पर ही किया जा सकता है
- बच्चों में गंभीर रूप से कोविड के मामले कम ही देखने में आए हैं. फिर भी अगर किसी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत पेश आए, होंठ नीले लग रहे हों या फिर उसे पानी और सूप आदि निगलने में कठिनाई हो रही हो तो किसी अस्पताल को फोन करें
- बच्चे का हौसला बनाए रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि बीमारी की स्थिति में मानसिक तनाव बढ़ने से असर और ज्यादा होगा
- बीमारी से उबरने के दौरान बच्चे को आराम, पर्याप्त मात्रा में पानी और लिक्विड तथा अच्छी खुराक की जरूरत होती है
- गंभीर कोविड की स्थिति में फॉलोअप के रूप में भी डॉक्टर से सलाह जारी रहनी चाहिए जिससे कि कोई गंभीर जटिलता न पैदा हो जाए
- कुछ बच्चे कोविड से रिकवरी के बाद एमआइएस–सी का शिकार हो सकते हैं. इसके लक्षणों में शामिल हैं: बुखार, पेट दर्द, उल्टी, गर्दन में दर्द, शरीर पर चकत्ते, आंखें और होठों का लाल होना और हाथ-पैरों में सूजन. ऐसे लक्षण नजर आने पर डॉक्टर को फोन करें

इनसे इनकार नहीं किया जा सकता. 16 अप्रैल को सूरत के डायमंड अस्पताल में 15 दिन के एक शिशु की कोविड से मौत हो गई. कोलकाता में, 34 वर्षीया रूपा मोइत्रा ने राजारहाट स्वास्थ्य केंद्र में एक बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था. घर ले जाने के दो हफ्ते बाद उसे तेज बुखार हुआ. कोई भी अस्पताल कोविड जांच करने को तैयार नहीं था और जब तक वे उसे अस्पताल ले जाते, बच्चे की मृत्यु हो गई. डॉ. चटर्जी कहते हैं, ''महानगरों और छोटे शहरों में मध्यम या उच्च वर्ग के परिवारों के जो बच्चे कोविड संक्रमित पाए जाते हैं, उनका पोषण स्तर बेहतर होता है और चिकित्सा सुविधाओं तक आसान पहुंच होती है. पर अब कमजोर समूह के बच्चे कोविड के ज्यादा शिकार हो रहे हैं.''

हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि एक मां के अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को वायरस संक्रमित करने का जोखिम बहुत कम, मात्र 0.05 प्रतिशत होता है; वास्तविक जोखिम जन्म के बाद ही सामने आता है. अनुचित देखभाल, खासकर जब मां भी कोविड संक्रमित हो, के कारण पहले से ही देश भर में बहुत से नवजात जन्म के बाद संक्रमित हो चुके हैं. डॉ. सेठ कहती हैं, ''अगर मां गर्भावस्था के आखिरी 2-3 महीनों में कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो बच्चे के संक्रमित होने का खतरा उन माताओं के मुकाबले अधिक होता है जो डिलिवरी के महज कुछ दिनों या कुछ हफ्ते पहले संक्रमित हुई हैं.''

भारत तो पहले से ही दुनिया के उन देशों में से एक है जहां नवजातों की सबसे अधिक मौतें होती हैं. 2011 के बाद से देश भर में 800 विशेष नवजात देखभाल इकाइयों (एसएनसीयू) के शुरू होने से स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन ये अभी भी कोविड-पॉजिटिव नवजात शिशुओं की देखरेख के लिए आवश्यक पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं हैं. सेव द चिल्ड्रन, इंडिया में स्वास्थ्य उप-निदेशक डॉ. राजेश खन्ना कहते हैं, ''एसएनसीयू पहले से ही भरे हुए हैं और बिस्तरों की बहुत अधिक मांग है.'' इन एसएनसीयू के अलावा प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो नवजात देखभाल इकाइयां हैं उनमें नियमित रूप से होने वाले बच्चों के जन्म के मामलों को भी संभालने के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं हैं फिर कोविड को संभालने की बात करना बेमानी है.

नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए चिकित्साकर्मियों की कमी चिंता का एक और विषय है. बाल चिकित्सा (पीड्रियाटिक) कोविड आइसीयू में महीने में 25 दिन बिताने के बाद, डॉ. सेठ कहती हैं, ''डॉक्टरों का मनोबल पहले से ही बहुत गिरा हुआ है. कोविड और सीमित संसाधनों के कारण चिंता का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है. माता-पिता अक्सर उत्तेजित होते हैं और हमें उनका तनाव और अपना तनाव कम करने के लिए प्रयास करते हुए रोगी का जीवन बचाने के प्रयास जारी रखने होते हैं.''

तीसरी लहर बच्चों के लिए अधिक गंभीर?

विशेषज्ञों के अनुसार, हमें अभी तक नहीं पता कि भविष्य के कोविड स्ट्रेन बच्चों को अधिक गंभीरता से प्रभावित करेंगे या नहीं. डॉ. सिब्बल कहते हैं ''अभी तक हमारे सामने एक चीज स्पष्ट है कि कुल संख्या के लिहाज से देखें तो दूसरी लहर में पहले से अधिक बच्चे संक्रमित हुए हैं. मसलन, बच्चों में भी इस साल अलग-अलग लक्षण देखे गए हैं, जैसे गैस्ट्रिक समस्याएं. पहले सिर्फ खांसी और हल्का बुखार ही होता था.'' सिंगापुर, जहां पहली बार भारत में दिखे कोविड के स्ट्रेन बी.1.617 के 333 मामले पाए गए हैं, का कहना है कि यह वैरिएंट बच्चों में ज्यादा तेजी से फैलता दिखता है.

18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए अगर तीसरी लहर आती है तो वे सबसे ज्यादा जोखिम में होंगे. फिलहाल भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर परीक्षण किया जा रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि यह इस साल के अंत तक 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी टीकारण के दायरे में लाने में एक संभावित अग्रदूत हो सकती है. इस बीच, संक्रमण के तुरंत बाद दिए गए फ्लू शॉट्स और ऐंटीबॉडी कॉकटेल बच्चों और उनके परिवारों, दोनों को वायरस से बचाने में मदद कर सकते हैं.

डॉ. सेठ कहती हैं, ''तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले हमारे पास तैयारियों का कुछ समय शेष है. हमें बच्चों और नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए और नवजात और बाल चिकित्सा संसाधनों का तेजी से निर्माण करना चाहिए ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटने को तैयार हो सकें.'' देश किसी भी देरी का जोखिम नहीं उठा सकता. —साथ में **अखिलेश पांडे**

सिर से उठ गया मां-बाप का साया

राहुल नरोन्हा

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बगरतावा गांव के दीपक सोलंकी जांच के बाद 8 अप्रैल को कोरोनावायरस संक्रमित पाए गए. दो दिन पहले सोलंकी और उनकी पत्नी अनीता में बुखार और फ्लू जैसे अन्य लक्षण उभरे थे लेकिन उनका मानना था कि कोविड तो शहरों में होता है इसलिए उन्हें बस फ्लू ही हुआ होगा. हालांकि जिला चिकित्सा प्रतिनिधि, 45 वर्षीय दीपक के आग्रह पर उन्होंने आरटी-पीसीआर टेस्ट कराया तो संक्रमित निकले. दीपक को उसी दिन एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और दो दिन बाद अनीता को भी भर्ती कराना पड़ा. 18 और 15 वर्ष की उनकी दो बेटियां और 12 साल का बेटा उनके भतीजे श्रीकांत सोलंकी की देखभाल में घर में ही थे. तीनों बच्चे भी संक्रमित निकले थे.

हफ्तेभर में सोलंकी की स्थिति बिगड़ती चली गई और 20 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई. पिता की मृत्यु पर कलपते बच्चों की आंखों से आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि 1 मई को उन्हें अपनी मां के निधन की खबर मिली. कुछ ही हफ्तों में उनकी दुनिया उजड़ गई थी. सबसे बड़ी बेटी जो कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा है, उसी के कंधों पर स्कूल जाने वाले अपने भाई-बहनों की देखभाल का बोझ आ गया था. उन्होंने ऐसी स्थिति की कभी कल्पना नहीं की थी. सोलंकी अपने पीछे न तो खेती-बाड़ी छोड़ गए हैं न कोई अन्य संपत्ति. बच्चे फिलहाल श्रीकांत सोलंकी की देखरेख में रह रहे हैं, जो बगरतावा में एक छोटी-सी दुकान चलाते हैं और दो बच्चों के पिता हैं.

होशंगाबाद के जिला मजिस्ट्रेट धनंजय भदौरिया कहते हैं, ''जैसे ही कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों की खबर सुनने को मिली, हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को सक्रिय कर दिया और उनके बारे में जानकारी एकत्र की. सोलंकी के बच्चों को नव-घोषित मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत पंजीकृत किया गया है.''

वायरस के क्रूर हमले ने युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है और देशभर में मरने वालों की संख्या 3.5 लाख पार कर चुकी है. युद्ध के अनाथों की तरह अब कोविड अनाथ बच्चे भी हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के अनुसार, 1 अप्रैल से 5 जून के बीच 3,621 बच्चे अनाथ हुए; 26,176 बच्चों ने माता-पिता में से किसी एक को खोया; और 274 के लिए कोई आसरा न रहा. एनसीपीसीआर ने स्पष्ट किया कि माता-पिता की मृत्यु कोविड के कारण ही नहीं हुई थी.

दूसरी लहर के बाद केंद्र और विभिन्न राज्यों का ध्यान इस संकट पर गया है. वे सक्रिय हो गए हैं और सरकार और स्वैच्छिक दोनों क्षेत्रों से मदद मिल रही है. मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड से अनाथ बच्चों के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के अलावा 5,000 रुपए की पेंशन की घोषणा की है. उन्हें मुफ्त राशन मिलेगा और अगर उनके पास ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जिसके साथ वे रह सकते हों, तो एक सुरक्षित आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी. यह सहायता बच्चों के 24 वर्ष की आयु के होने तक जारी रहेगी. इस योजना में 1 मार्च से 30 जून के बीच अनाथ सभी बच्चों को शामिल किया गया है, चाहे उनके माता-पिता की मृत्यु कोविड से हुई हो या अन्य कारण से. राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने एक पुरानी स्पॉन्सरशिप योजना को भी दुरुस्त किया है जिसके तहत निजी व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपए या उससे अधिक का योगदान करके एक कोविड अनाथ को स्पॉन्सर कर सकते हैं. इसके अलावा राज्य की ओर से घोषित एक पालक देखभाल योजना के तहत, नामित माता-पिता एक विशिष्ट अवधि के लिए बच्चों को रख सकेंगे और अगर वे बच्चे को गोद लेने का फैसला करते हैं तो इसके लिए उन्हें गोद लेने की प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त अंक मिलेंगे. मध्य प्रदेश की महिला और बाल विकास निदेशक स्वाति मीणा बताती हैं, ''कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बच्चे को केंद्रीय दत्तक ग्रहण

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुताबिक

3,621

बच्चे अनाथ हुए 1 अप्रैल से 5 जून के बीच;

26,176

बच्चों ने मां-बाप में से किसी एक को खोया;

274

बच्चे त्याग दिए गए

संसाधन प्राधिकरण (सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी) में पंजीकृत किया जाएगा.''

29 मई को केंद्र सरकार ने 'कोविड-19 प्रभावित बच्चों के सशक्तीकरण के लिए पीएम केयर्स फंड' योजना का ऐलान किया, जिसके तहत जिन बच्चों ने कोविड के कारण या तो माता-पिता या अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य को खो दिया है, वे प्रति बच्चा 10 लाख रुपए के कोष से प्राप्त ब्याज के हकदार होंगे. इसकी आय बच्चों को 18 वर्ष की आयु के होने के बाद दी जाएगी, और शेष धनराशि उन्हें 23 वर्ष की आयु के होने पर दी जाएगी. 11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को केंद्रीय विद्यालय या सरकार के आवासीय विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा. पीएम आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज भी दिया जाएगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड के जरिए किया जाएगा.

हालांकि, बच्चों को पालने के लिए सरकारों की प्रतिबद्धताएं केवल उन्हें शिक्षा और रहने की जगह प्रदान करने भर की नहीं होनी चाहिए बल्कि उसके आगे भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है. बच्चों की सुरक्षा चिंता का बड़ा विषय है. यह समझते हुए कि ये बच्चे शोषण के शिकार हो सकते हैं, सरकारें उन्हें उन असामाजिक तत्वों से बचाने के तरीके भी खोज रही है, जो इस मौके का फायदा उठाने को आतुर होंगे.

कुछ पहल जो राज्यों ने की

मध्य प्रदेश: **5,000 रु.** महीना पेंशन, 21 साल की उम्र तक (उच्च शिक्षा लेने का फैसला करने पर 24 साल तक). शिक्षा मुफ्त

दिल्ली: **2,500 रु.** महीना पेंशन, 25 साल की उम्र का होने तक. शिक्षा मुफ्त

चंडीगढ़: **500 रु.** महीना पेंशन, 12 साल की उम्र तक. उसके बाद 18 साल की उम्र तक **1,000 रु.** महीना पेंशन

हिमाचल प्रदेश: **2,500 रु.** महीना पेंशन 18 साल की उम्र तक

पंजाब: **1,500 रु.** महीना पेंशन, 21 साल की उम्र तक

राजस्थान: **500 रु.** महीना पेंशन, 18 साल की उम्र तक

गुजरात: **4,000 रु.** महीना पेंशन, 18 साल की उम्र तक. उसके बाद **6,000 रु.** महीना, 24 साल की उम्र तक

उत्तराखंड: **3,000 रु.** महीना पेंशन, 21 साल की उम्र तक

तेलंगाना: **10 लाख रु.** का फिक्स्ड डिपॉजिट बच्चे के नाम पर, जो कि उसे 18 साल की उम्र का होने पर दिया जाएगा

केरल: **2,000 रु.** महीना पेंशन, 18 साल की उम्र तक. बच्चे के नाम पर **3 लाख रु.** का फिक्स्ड डिपॉजिट भी, जो 18 साल का होने पर उसे दे दिया जाएगा

तमिलनाडु: **3,000 रु.** महीना पेंशन, 18 साल की उम्र तक. मुफ्त शिक्षा. बच्चे के नाम पर **5 लाख रु.** का फिक्स्ड डिपॉजिट भी, जो 18 साल का होने पर उसे दे दिया जाएगा

उत्तर प्रदेश: **4,000 रु.** महीना पेंशन. मुफ्त शिक्षा. विवाह का खर्च राज्य सरकार उठाएगी. बेटी है तो शादी के मौके पर उसे **1.01 लाख रु.** दिए जाएंगे

असम: **3,500 रु.** महीना पेंशन और मुफ्त शिक्षा

वंचित बच्चों के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों ने राज्यों और केंद्र के हस्तक्षेप का स्वागत किया है. वर्ल्ड विजन इंडिया के मानव तस्करी निरोधी कार्यक्रम के प्रमुख जोसफ वेज्ली कहते हैं, ''सबसे अहम पहलू ऐसे सभी बच्चों की पहचान कर उन्हें सरकारी देखरेख में लाना है. सरकारी देखरेख से हमारा मतलब उन्हें राज्य द्वारा चलाए जा रहे संस्थागत केंद्रों में रखने से नहीं बल्कि एक ऐसी प्रणाली से है जहां उनकी निगरानी और परामर्श का कार्य राज्य की ओर से किया जाता है.'' पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में कमजोर बच्चों के साथ काम करने के अपने अनुभव से वेज्ली बताते हैं कि जब तक कि सरकार की निगरानी पक्की नहीं की जाती, बच्चों के अजनबियों की देखरेख में बड़े होने का जोखिम बना रहता है. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ऐसे सभी बच्चों को जिला बाल कल्याण समितियों की निगरानी में लाने पर जोर दिया है. निगरानी यह पक्का करेगी कि अभिभावक बच्चों को मौद्रिक लाभ दे रहे हैं.

एकल माता-पिता के साथ बड़े होने वाले बच्चों, खासकर अगर अभिभावक महिला है, के लिए जोखिम ज्यादा होता है. वेज्ली कहते हैं, ''ऐसे बच्चों की अक्सर जल्दी शादी कर दी जाती है क्योंकि एकल माता-पिता उनकी परवरिश करने में असमर्थ होते हैं,'' उनकी जानकारी के अनुसार, कोविड के बाद बाल तस्कर पहले से ही बहुत सक्रिय हो चुके हैं और कमजोर बच्चों की पहचान कर रहे हैं. इस स्तर पर त्वरित कार्रवाई महत्वपूर्ण है. उनका कहना है कि तस्कर आमतौर पर ऐसे बच्चों को मजदूरी कराने के लिए निशाना बनाते हैं और अंतत: उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेल देते हैं.

एक व्हाट्सऐप संदेश के जरिए बच्चों को गोद लेने का मैसेज प्रसारित किया जा रहा था. इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुलिस ने हाल में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. कुछ राज्य उनकी सुरक्षा पुख्ता करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं.

कोविड अनाथों की पहचान भी एक चुनौती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अक्सर यह पता नहीं चलता है कि माता-पिता की मृत्यु कोविड से हुई है या किसी अन्य बीमारी के कारण क्योंकि वहां कोई जांच नहीं होती. अधिक राज्यों को मध्य प्रदेश के नक्शेकदम पर चलने और इस दौरान अनाथ सभी बच्चों को संबंधित योजनाओं के दायरे में लाने की जरूरत है, चाहे वे कोविड के कारण अनाथ हुए हों या किसी अन्य बीमारी से.■

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

ऑनलाइन निजता की लड़ाई

सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियमों ने केंद्र सरकार और बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी, पर यह बड़ी टकराहट कहीं उपभोक्ताओं के अधिकारों की कुर्बानी तो नहीं ले रही

कौशिक डेका

इलस्ट्रेशनः नीलांजन दास

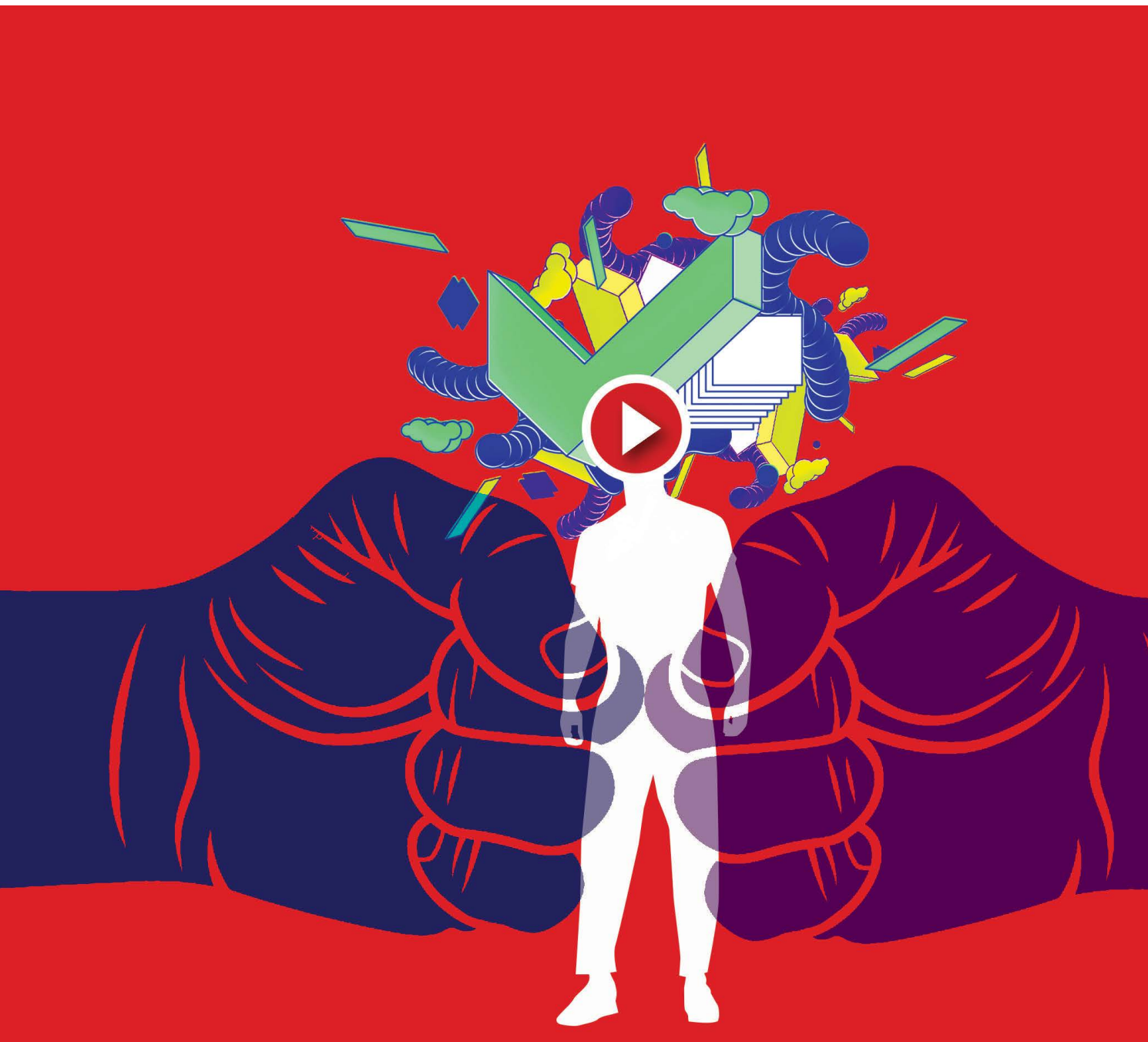

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार उत्पल बोरपुजारी इन दिनों उलझन में हैं. पूर्व पत्रकार होने के नाते वे लोकतंत्र में बोलने की आजादी की अहमियत समझते हैं. साथ ही वे मानते हैं कि लाखों साधारण नागरिकों को अपनी बात कहने का अभूतपूर्व मौका देने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से गलत जानकारियों और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए नियम-कायदों की व्यवस्था जरूरी है. फिल्मकार होने के नाते बोरपुजारी रचनात्मक आजादी के प्रबल समर्थक हैं, हालांकि वे मानते हैं कि ऐसी आजादियों का इस्तेमाल नैतिक आचार-विचार और जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया जाना चाहिए.

लिहाजा, 25 फरवरी को जब सरकार ने डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 जारी किए, उन्होंने इन दिशानिर्देशों के औचित्य पर सवाल नहीं उठाए (जो घोषित तौर पर नागरिकों को शिकायत निवारण तंत्र देने के लिए लाए गए हैं). मगर नए नियमों को सावधानी से पढ़ने के बाद कई दूसरों की तरह बोरपुजारी भी फिक्रमंद हो उठे. वे कहते हैं, ''अनुभव से हम जानते हैं कि अपनी निजता की रखवाली के लिए ट्विटर या फेसबुक पर भरोसा नहीं कर सकते, पर ये दिशानिर्देश भी मुझ इंटरनेट यूजर की कम ही मदद करते हैं.''

नए आइटी नियम केंद्र सरकार और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के बीच सरगर्म लड़ाई के केंद्र में हैं. इनका मकसद विदेशी कंपनियों से भारतीय कानूनों का पालन करवाना है, जो लाखों यूजर यानी उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कतराती हैं. मगर ये नियम कार्यपालिका की मशीनरी को डिजिटल सामग्री सेंसर करने का अधिकार भी देते हैं और वह भी अदालतों की बहुत कम निगरानी के साथ. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और जनरल डायनैमिक्स के पूर्व भारत प्रमुख सुबिमल भट्टाचार्य कहते हैं, ''पारदर्शिता रिपोर्ट के साथ शिकायत निवारण की साफ-साफ प्रक्रिया का प्रकाशन यूजर के लिए इंटरनेट को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा. पर सरकार को निर्णायक मध्यस्थ बनाने से कई लोग परेशान हो उठे हैं.''

सरकार ने नियम क्यों बनाए?

इस विषय से जुड़े सभी लोगों के बीच आम राय है कि गलत जानकारियां फैलाने, लोगों को बदनाम करने, यौन इशारों वाली सामग्री भेजने और कॉपीराइट का उल्लंघन करने के मकसद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अंधाधुंध दुरुपयोग रोकने की खातिर पारदर्शी और जवाबदेह तंत्र की जरूरत है. देश में डेटा प्राइवेसी कानून नहीं है और ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 में पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, खासकर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सरीखे मध्यस्थ सोशल मीडिया माध्यम और व्हाट्सऐप, टेलीग्राम तथा सिग्नल सरीखी इंस्टेंट मेसेंजर सेवाओं की विकसित हो रही कार्यप्रणाली को नियमों के दायरे में ला सकें.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के भीतर पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र न होने से पेचीदगियां और बढ़ जाती हैं. 2000 के आइटी कानून ने भी इन 'मध्यवर्ती' कंपनियों—यानी सामग्री में सक्रिय भूमिका के बगैर जानकारियों के निष्क्रिय वाहकों—को 'सुरक्षित आश्रय' मुहैया किया और उन्हें उनकी प्रकाशित सामग्री पर किसी भी आपराधिक जिम्मेदारी से छूट दी है. केंद्र सरकार अब दावा कर रही है कि आइटी नियमों का लब्बोलुबाब शिकायतों के निवारण के लिए पारदर्शी और तत्काल उपलब्ध फोरम बनाना है. डिजिटल नीति पर नजर रखने वाले भी ऐसी निगरानी की जरूरत स्वीकार करते हैं. सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी पॉलिसी रिसर्च के प्रेसिडेंट जयजीत भट्टाचार्य सवाल करते हैं, ''टीवी, अखबार, वॉइस कॉल और टेक्स्ट मेसेज सरीखे ऐसे ही पारंपरिक माध्यम एक नियामकीय ढांचे में काम कर सकते हैं, तो नए माध्यमों पर भी वैसी ही निगरानी क्यों नहीं होनी चाहिए?''

कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दावा करते हैं कि आपत्तिजनक सामग्री को छांटकर हटाने का तंत्र खुद उनके भीतर है, लेकिन सामग्री के ऐसे संग्रह को अक्सर अनियमितता, विचाराधारात्मक पूर्वाग्रह और व्यावसायिक हितों से प्रेरित होने के आरोपों का सामना करना पड़ा है. पारदर्शिता की कमी तो जाहिर ही है क्योंकि वे अपने यूजर को कभी नहीं बताते कि कोई खास सामग्री क्यों चिह्नित की या हटाई गई. विवादित 'टूलकिट' के हालिया मामले में अपनी अस्पष्ट व्यवस्था के कारण ट्विटर को राजनीतिक पक्षपात के आरोप को लेकर फटकार सुननी पड़ी.

ट्विटर की जन नीति कहती है कि वह 'खासी तादाद में और धोखाधड़ी से बदली या गढ़ी गई' सामग्री पर 'मैनिपुलेटेड मीडिया' (तोड़ी-मरोड़ी गई सामग्री) का लेबल लगाता है. उसका कहना है कि यह तय करने के लिए कि सामग्री तोड़ी-मरोड़ी गई है या नहीं, प्लेटफॉर्म खुद अपनी टेक्नोलॉजी या तीसरे पक्षों का इस्तेमाल करता है.

टूलकिट मामले में यह ट्विटर की नीति की अनियमितता ही थी जिसकी वजह से उसने एक ही सामग्री वाले कुछ ट्वीट चिह्नित किए जबकि कई दूसरे ट्वीट छोड़ दिए. दूसरी गड़बड़ी हुई जब प्लेटफॉर्म ने उप-राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और आरएसएस के कई शीर्ष नेताओं के निजी एकाउंट से सत्यापन का निशान 'ब्लू टिक' हटा दिया. ऐसी प्रक्रियाओं की अनियमितता और अपारदर्शिता के चलते इन मध्यवर्तियों के कामकाज की जांच-पड़ताल के लिए कोहराम मच गया.

आइटी फॉर चेंज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनीता गुरुमूर्ति कहती हैं, ''हमें जानने की जरूरत है कि स्वचालित सार्वजनिक क्षेत्र के इन अदृश्य तंत्रों में क्या हो रहा है. अगर किसी चीज पर तोड़ी-मरोड़ी गई गलत जानकारी का बिल्ला लगाया गया है, तो यह बताना जरूरी है कि क्यों लगाया गया है.'' आइटी विशेषज्ञ और एलायंस फॉर एफोर्डेबल इंटरनेट (ए4एआइ) के सदस्य ओसामा मंजर मानते हैं कि अगर ये प्लेटफॉर्म स्थानीय संदर्भ और भाषा में स्थानीय स्तर पर तथ्यों की जांच-पड़ताल करें तो ऐसी गलत कार्यप्रणाली से बचा जा सकता है. वे कहते हैं, ''गलत सामग्री न केवल हटाई जानी चाहिए बल्कि उसकी वजह भी यूजर तक पहुंचनी चाहिए.''

असल में सरकारी दबाव, विचाराधारा के पूर्वाग्रह और व्यावसायिक हितों के पैरोकारों के प्रभावों में इन प्लेटफॉर्मों के सामग्री को संग्रह और प्रस्तुत करने में विसंगतियां रही हैं और इसका नतीजा नियामकीय व्यवस्था की व्यापक मांग की शक्ल में सामने आया. बीते छह महीनों में ऐसे कई प्रसंग हुए जब केंद्र और ट्विटर के बीच तलवारें खिंच गईं और ज्यादातर मौकों पर ट्विटर को सरकार की मांगें मानने को बाध्य किया गया. इसी महीने केंद्र ने ट्विटर से कार्टूनिस्ट मंजुल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा क्योंकि उनके ट्वीट देश के कानूनों का उल्लंघन करने वाले माने गए. ट्विटर ने सरकार की बात नहीं मानी.

आलोचकों का कहना है कि नए नियम भविष्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे अनुरोध नामंजूर करने की इजाजत नहीं देंगे. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर संसद की स्थायी समिति के चेयरमैन, कांग्रेस सांसद शशि थरूर कहते हैं, ''क्या सोशल मीडिया घराने पोस्टमैन की तरह हैं जो आपकी चिट्ठी पहुंचाते भर हैं, उनका मजमून नहीं पढ़ते? या वे प्रकाशक की तरह हैं, जिनकी जनता के प्रति भरोसे से जुड़ी जिम्मेदारी है कि वे जो प्रकाशित करते हैं उसकी सटीकता, औचित्य और वैधानिकता पक्की करें? फेसबुक और ट्विटर पोस्टमैन होने का दावा करते थे, पर

आइटी दिशानिर्देश ...और आपत्तियां

अगर कोई सरकारी एजेंसी बाखबर करती है, तो प्लेटफॉर्म से हर उस पोस्ट को 36 घंटे के भीतर हटा देना होगा, जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा; मित्रवत संबंधों वाले देशों, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या मर्यादा, अदालती अवज्ञा या मानहानि के मामले में गैर-कानूनी हो	इन श्रेणियों के बहाने सरकार अपने कामकाज को लेकर आलोचना को हटाने का दबाव बना सकती है
किसी यूजर के प्लेटफॉर्म छोड़ देने की हालत में संबंधित प्लेटफॉर्म की कंपनी को 180 दिनों तक उसके पंजीकरण संबंधित सूचना को बरकरार रखना होगा	यह यूजर की निजता का उल्लंघन होगा, जो अपनी जानकारियों के ब्यौरे रखने की सहमति देना न पसंद करे
सभी संबंधित कंपनियों को किसी यूजर की शिकायत पर उसका निवारण 15 दिनों के भीतर करना होगा और भारत में एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी. 50 लाख से अधिक यूजर वाली कंपनियों को एक मुख्य शिकायत अधिकारी या नोडल अफसर की भारत में नियुक्ति करनी होगी, जो कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाए रखे	इससे टेक कंपनियों का खर्च बढ़ेगा, जिससे वे बचना चाहती हैं
भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा तथा मित्रवत देशों से संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था और यौन अपराधों से संबंधित मामलों में अहम सोशल मीडिया कंपनियों को सूचना के पहले स्रोत की पहचान उजागर करनी होगी	व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म का दावा है कि इससे उसे एक से दूसरे व्यक्ति के संवाद में दखल देने का दबाव होगा, जो यूजर की निजता का उल्लंघन है
अहम सोशल मीडिया कंपनियों को बलात्कार और बाल उत्पीड़न से संबंधित कंटेंट की पहचान करने के लिए तकनीकी उपाय का प्रबंध करना होगा. पक्षपात या भेदभाव दूर करने के लिए समय-समय पर उस टूल की समीक्षा होगी	इससे आशंका है कि ऐसे पोस्ट को हटाने का दबाव भी बने, जो आपत्तिजनक न हो
आपात स्थिति में अधिकृत अधिकारी डिजिटल कंटेंट की जांच कर सकता है और सूचना-प्रसारण मंत्रालय कुछ शर्तों के साथ उसे ब्लॉक कर सकता है	आपात स्थिति का हवाला हर उस कंटेंट के लिए दिया जा सकता है, जिसको लेकर सरकार असहज हो

जब वे पोस्ट पर बिल्ले लगाने लगे और यहां तक कि उन्हें हटाने के दबाव के आगे झुक गए, तो वे प्रकाशक की तरह ज्यादा हो गए. वे कभी पोस्टमैन हैं और कभी प्रकाशक, इस जवाब से नियामकीय चुनौती हल नहीं होगी.''

नियमों पर ऐतराज

नए नियम उचित विवेकसम्मत संहिता की पेशकश करते हैं जिनका पालन मध्यवर्ती माध्यमों को करना होगा और तभी वे 'सुरक्षित आश्रय' हासिल कर सकेंगे. डिजिटल मीडिया आचार संहिता सामग्री की 10 श्रेणियां तय करती है जिनके अंतर्गत आने वाली सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने यहां नहीं डालने देना चाहिए. प्लेटफॉर्म को कानूनी अदालत या उचित सरकारी एजेंसी से प्रतिबंधित सामग्री के डाले जाने की सूचना मिलने पर 36 घंटे के भीतर उन्हें हटाना होगा. नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रावधान सरकार को संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता और जन व्यवस्था की धाराओं की दुहाई देकर किसी भी सामग्री को खासकर अपनी आलोचना करने वाली सामग्री को रोकने का बहुत ज्यादा अधिकार देते हैं. गुरुमूर्ति कहती हैं, ''प्रतिकूल मानी गई सामग्री का चरित्र-चित्रण करने के लिए मानहानिकारक और निंदात्मक सरीखे शब्दों की दुहाई दी जा सकती है.''

विवाद की सबसे बड़ी जड़ मूल स्रोत का पता लगाने वाली धारा है. स्थापित यानी कम से पचास लाख रजिस्टर्ड यूजर वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी ऐसी सूचना के सबसे पहले स्रोत की पहचान बतानी होगी, जिसकी मांग भारत की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा, बाहरी देशों के साथ मित्रवत रिश्तों, जन व्यवस्था या यौन अपराधों से जुड़े मामलों में समर्थ न्यायाधिकार/ समर्थ प्राधिकार वाली अदालत ने की हो. हालांकि नियमों में स्पष्ट है कि स्रोत का पता लगाने का आदेश इन श्रेणियों से जुड़े अपराधों में ही दिया जा सकता है, पर विशेषज्ञों को लगता है कि 'जन व्यवस्था' सरीखी श्रेणियों का दायरा बहुत व्यापक है और सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है.

उन्हें डर है कि इस प्रावधान से एन्क्रिप्टेड या कूट तरीके से रखे गए गोपनीय संदेश और अंतत: यूजर की निजता खत्म हो जाएगी. दिल्ली स्थित डिजिटल स्वतंत्रता संगठन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आइएफएफ) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट अपार गुप्त कहते हैं, ''एन्क्रिप्शन न केवल आपके संदेशों को तीसरे पक्षों के हाथों में पड़ने से रोकता है बल्कि साइबर सुरक्षा के तमाम जोखिमों से उनकी रक्षा भी करता है.''

''क्या सोशल मीडिया घराने डाकिए की तरह हैं, जो आपका मेल पहुंचा देते हैं मगर उसे पढ़ते नहीं? या उन प्रकाशकों की तरह हैं, जो अपने हर प्रकाशन में सार्वजनिक जिम्मेदारी का ख्याल रखते हैं? फेसबुक और ट्विटर डाकिया होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन वे पोस्ट को शह देने या हटाने लगेंगे तो प्रकाशक की तरह बन जाएंगे''

शशि थरूर
कांग्रेस सांसद तथा आइटी पर संसदीय प्रवर समिति के अध्यक्ष

''हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि स्वचालित सार्वजनिक मंच की अदृश्य तकनीकी में क्या चल रहा है. अगर कुछ पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा है, तो यह बताना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों?

अनीता गुरुमूर्ति
कार्यकारी निदेशक, आइटी फॉर चेंज

इस प्रावधान का जबरदस्त असर व्हाट्सऐप पर पड़ेगा. उसने दिल्ली हाइ कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कहा है कि इससे उसे अपनी एंड-टु-एंड एन्क्रिप्शन नीति में काट-छांट करनी पड़ेगी. विडंबना है कि इसी अदालत में व्हाट्सऐप अपने यूजर को नए सेवा समझौते पर सहमत होने को मजबूर करने के लिए कानूनी चुनौती का सामना कर रहा है. इस नए समझौते की बदौलत कंपनी यूजर का डेटा अपनी मातृ कंपनी फेसबुक के साथ साझा कर पाएगी. हालांकि यह नीति 15 मई से प्रभावी हो गई, पर व्हाट्सऐप का दावा है कि भारत में निजी डेटा सुरक्षा कानून के आने तक इस अनिवार्य सहमति को रोक दिया गया है.

इस बीच सरकार का कहना है कि उसने बड़ी टेक कंपनियों को बस संदेश के मूल स्रोत का पता लगाने की व्यवस्था कायम करने को कहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह उनसे एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी तोड़ने के लिए कह रही है. अभी तय होना है कि एन्क्रिप्शन के नियमों को तोड़े बगैर मूल स्रोत का पता लगाया जा सकता है या नहीं. भट्टाचार्य कहते हैं, ''निजता या एन्क्रिप्शन से समझौता किए बगैर स्रोत का पता लगाना पूरी तरह मुमकिन है. एन्क्रिप्टेड संदेश काफी कुछ अमेजन पैकेज की तरह होता है. यह जिसके नाम है उसके अलावा कोई नहीं देख सकता कि पैकेज के भीतर क्या है. मगर जिसे मिला है वह पता लगा सकता है कि यह किसने भेजा है क्योंकि इसके साथ भेजने वाले का नाम नत्थी है.'' आइआइटी मद्रास के प्रो. वी. कामकोटि का कहना है कि कुछ आसान से हेरफेर करके स्रोत का पता लगाने की धारा को लागू किया जा सकता है, लेकिन आइआइटी बॉम्बे के प्रो. मनोज प्रभाकरन उनकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि न केवल इन हेरफेर की सीमित उपयोगिता है बल्कि इनसे तमाम यूजर की निजता खतरे में पड़ जाएगी.

दुनिया भर के 29 अध्येता और सुरक्षा विशेषज्ञों के एक समूह ने पिछले साल प्रसाद को पत्र लिखकर कहा कि सभी के लिए सिस्टम की सुरक्षा को कमजोर किए बगैर कुछ लोगों को 'अपवाद स्वरूप पहुंच' मुहैया करने का कोई तरीका नहीं है. न्यूयॉर्क स्थित सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की लीगल डायरेक्टर मिशि चौधरी कहते हैं, ''जानकारी हासिल करने के लिए कानून प्रवर्तक एजेंसियों को आइटी कानून 2000 की धारा 69 सरीखे कानूनों के तहत मौजूदा उपायों की खोजबीन करनी चाहिए और अमेरिका के क्लेरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा ऐक्ट के तहत किए गए समझौतों के प्रावधानों की पड़ताल करनी चाहिए.''

ये नियम नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम सरीखे ओटीटी प्लेटफॉर्म से तीन स्तरीय नियामकीय व्यवस्था की भी मांग करते हैं. इनमें प्रकाशकों के लिए खुद पर लागू होने वाले नियम-कायदे, सरकार की फेहरिस्त में शामिल सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में स्व-नियामकीय संस्था और एक अंतर-विभागीय समिति शामिल है. सूचना-प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायतें सुन सकती है, उसे जन व्यवस्था से जुड़े संज्ञेय अपराध भड़काने से रोकने के लिए सामग्री

“सामग्री को नियंत्रित करने या निजता के हनन की हमारी कोई मंशा नहीं”

*केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री **रविशंकर प्रसाद** डिप्टी एडिटर **कौशिक डेका** के साथ एक विशेष बातचीत में विस्तार से बता रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 आभासी दुनिया में एक भारतीय नागरिक की निजता और उसके लोकतांत्रिक अधिकारों पर किस तरह से असर डालने वाला है. उन्होंने सोशल मीडिया की मध्यस्थ इकाइयों की चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश की और दावा किया कि इन नियमों का एकमात्र मकसद सामान्य उपभोक्ताओं को अधिकार देना और डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर उन्हें लूटखसोट से बचाना है. बातचीत के संपादित अंश:*

प्र इन नए दिशानिर्देशों का नियमित इंटरनेट उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? केंद्र सरकार नागरिकों को साफ आश्वस्त कर सकती है कि इन नियमों से उनकी निजता और बोलने की स्वतंत्रता में कोई कटौती नहीं होगी?

केंद्रीय आइटी मंत्री के रूप में मैं भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय नागरिकों की निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कभी समझौता नहीं किया जाएगा. मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सलाम करता हूं कि उन्होंने मुद्दों को उठाने और प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों या किसी भी अधिकारी से सवाल पूछने की शक्ति आम भारतीयों को दी है. लेकिन जब एक बेबस मां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही बेटी की अंतरंग तस्वीरों के बारे में शिकायत करना चाहती है, तो उसे नहीं पता होता कि किससे संपर्क करे. क्या मैं उसे अमेरिका जाने को कहूं? आज हर कोई—पत्रकार, जज, व्यवसायी—सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाता है. क्या उन्हें शिकायतों के निवारण के लिए एक मंच की जरूरत नहीं? ये नए दिशानिर्देश सामान्य उपभोक्ता को भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर वह अवसर प्रदान करते हैं, दुरुपयोग के खिलाफ उसे सशक्त बनाते हैं और उपभोक्ता तथा प्लेटफॉर्म के बीच जुड़ाव की व्यवस्था प्रदान करते हैं. सामग्री (कंटेट) की निगरानी या निजता के अतिक्रमण की हमारी कोई मंशा नहीं.

● दिशानिर्देशों में एक प्रावधान है जो सरकार को सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को 36 घंटे के भीतर किसी सामग्री को हटाने पर मजबूर करने की अनुमति देता है. सरकार इसका दुरुपयोग ऐसी किसी सामग्री को चिन्हित करने के लिए कर सकती है जिसमें उसके कामकाज की आलोचना की गई हो.

ऐसा करना होता तो मुझे इसके लिए इन दिशानिर्देशों का सहारा लेने की जरूरत ही न थी. यूपीए सरकार से पारित आइटी अधिनियम, 2000 सरकार को इस तरह की कार्रवाई के लिए पर्याप्त शक्ति देता है. बहरहाल, मुझे इन प्रावधानों के किसी भी दुरुपयोग की आशंका नहीं है क्योंकि भारत में एक मजबूत न्यायिक प्रक्रिया है.

● कल अगर कोई नागरिक आपकी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करता है तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके पोस्ट/ट्वीट हटाने को नहीं कहा जाएगा?

हां, मैं हर नागरिक को यह आश्वासन देता हूं. पिछले दो दशकों से प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है. यही हमारा लोकतंत्र है.

● ऐसा ही है तो फिर केंद्र ने हाल ही में ट्विटर को एक कार्टूनिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्यों कहा जिनके पोस्ट में सरकार की आलोचना की गई थी?

मैं उस मामले को देखूंगा. हास्य, कार्टून, व्यंग्य आदि तो लोकतंत्र का हिस्सा हैं. लेकिन हास्य सभ्य होना चाहिए.

● व्हाट्सऐप का दावा है कि किसी भी मेसेज को सबसे पहले किसने पोस्ट किया था, इसकी पड़ताल की व्यवस्था के लिए उसे अपनी एन्क्रिप्शन नीति से समझौता करना होगा, इससे उपभोक्ताओं की गोपनीयता खतरे में पड़ेगी.

ट्रेसेबिलिटी क्लॉज (मेसेज को बनाने वाले को खोजने का प्रावधान) केवल परिभाषित

बंदीप सिंह

मामलों में लागू होता है. मसलन यदि कोई वायरल संदेश दंगे भड़का रहा है या फिर किसी की यौन रूप से संवेदनशील अंतरंग तस्वीरें प्रसारित जा रही हैं, तो इंटरमीडियरीज को यह बताने के लिए कहा जाएगा कि आखिर यह शरारत किसने की है. हम उन्हें कंटेट को डिक्रिप्ट करने के लिए नहीं कह रहे. यह प्रक्रिया तभी शुरू की जाएगी जब ढूंढने के अन्य तरीके विफल हो जाएंगे.

● पर कई सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि एन्क्रिप्शन को तोड़े बिना किसी मेसेज के मूल स्त्रोत का पता लगाने के लिए जो मैकेनिज्म उपलब्ध हैं वे उपभोक्ता को गोपनीयता भंग के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं. एक सामान्य उपभोक्ता यह कैसे पक्का कर सकता है कि इस तरह के एन्क्रिप्शन-बायपासिंग टूल का दुरुपयोग सरकार या गलत नीयत वाले नहीं करेंगे?

टेक्नोलॉजी की समस्या का हल टेक्नोलॉजी से ही निकालना होगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पता लगाने की क्षमता विकसित करनी होगी. ऐसा करने में यदि ये उन आशंकाओं को वास्तविकता में बदलने देते हैं जिन्हें आपने अभी उठाया—उपभोक्ता की गोपनीयता भंग की आशंका—तो ये अपने ग्राहकों को खो देंगे. मंच की शुचिता अहम है और उसकी रक्षा करना उनका काम है. यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वे निजता का उल्लंघन किए बिना ट्रेसेबिलिटी का खाका तैयार करें ताकि इन प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग न हो. हर चीज को कानूनी और तकनीकी नजरिए से न देखें. कई सामाजिक और नैतिक दायित्व भी होते हैं.

● ट्विटर ने उप-राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू के अकाउंट से व्यक्तिगत अकाउंट सत्यापित करने वाला ब्लूटिक हटाया तो आपने दखल दिया...

दखल नहीं दिया, बस इसे उनके सामने उठाया. अगर वे भारत में काम करते हैं, तो उन्हें हमारे संवैधानिक पदों के प्रति संवेदनशील होना होगा. यदि आपके पास किसी अकाउंट को वेरिफाइ/डी-वेरिफाइ करने का कोई मानदंड है, तो इसे सभी अकाउंट पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाना चाहिए. यह बिना सोचे-समझे या आकस्मिक तरीके से नहीं हो सकता. इसके अलावा, वे अपने उपभोक्ताओं की सामग्री के एकतरफा नियामक नहीं हो सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि वे एक मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह काम करें जिसका उसकी सामग्री पर नियंत्रण होता है लेकिन वे उन कानूनों का पालन भी न करें जो मीडिया आउटलेट्स पर लागू होते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारतीय कानूनों और संविधान का पालन करना चाहिए. भारत डिजिटल संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा.

● भारत की लोकतांत्रिक साख पर भी तो प्रश्न उठते हैं ऐसे टकराव से...

इसमें भारत की छवि की कोई बात ही नहीं. भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत है. हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो सरकार से कोविड प्रबंधन और देशद्रोह के आरोपों को लेकर सवाल पूछ सकती है. स्वतंत्र मीडिया है जो सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराता है. पारदर्शी चुनाव तंत्र है. अमेरिका में बैठी, मुनाफा कमाने वाली ये निजी कंपनियां हमें लोकतंत्र पर व्याख्यान नहीं दे सकतीं. ■

हटवाने या रूप बदलवाने का अधिकार होगा.

ज्यादातर आलोचकों का कहना है कि मुट्ठी भर अफसरशाहों की यह 'निगरानी व्यवस्था' और कुछ नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सामग्री को सेंसर करने की सरकार की स्थायी रणनीति है. वे कहते हैं कि अंतर-विभागीय निकाय की जगह स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक निकाय होना चाहिए जिसमें विविध और व्यापक प्रतिनिधित्व हो और जिसके साफ और सुस्थापित मानक हों. गुरुमूर्ति कहती हैं कि आइटी दिशानिर्देशों से ऑनलाइन प्रकाशकों या क्यूरेटेड प्रकाशकों को बाहर रखा गया है.

आगे क्या होगा?

26 मई से नए नियम लागू होने के साथ ही सरकार ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, उनमें से कइयों ने इसके लिए छह महीने से एक साल तक का समय मांगा है. केंद्र से 'अंतिम चेतावनी' के बाद ट्विटर ने भी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सहमति तो दे दी है, हालांकि इसकी समयसीमा नहीं बताई है. दिल्ली हाइ कोर्ट में व्हाट्सऐप की अपील के अलावा आइटी नियमों के खिलाफ कम से कम आधा दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और कई हाइ कोर्ट में लंबित हैं. सरकार ने अभी यह नहीं बताया है कि आगे वह क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन प्रसाद ने साफ कहा है कि भारत में कारोबार वाली विदेश-आधारित टेक कंपनियां 'अनिश्चित काल तक बेलगाम' नहीं रहेंगी.

उधर, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (पीडीपी) विधेयक को संसद में पेश करने को लेकर ऊहापोह बना हुआ है. सरकार ने इसे समीक्षा के लिए भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली एक नवगठित प्रवर समिति के पास भेज दिया है. हालांकि लेखी समिति का विचार-विमर्श दिसंबर 2020 में समाप्त हो गया पर अंतिम रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की गई है. प्रसाद का कहना है कि सरकार संसद के अगले सत्र में डेटा संरक्षण विधेयक लाने की कोशिश करेगी.

तब तक यह नूरा कुश्ती चलती रहेगी. सरकार और डिजिटल इंटरमीडियरीज दोनों ने दावा करने में कसर नहीं छोड़ी है कि वे नागरिकों के निजता के अधिकार के बड़े पैरोकार हैं, जिसे संयोगवश, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार घोषित किया है. पर किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता—यह लड़ाई दरअसल इस बात की है कि आभासी दुनिया के बहस-मुहाबिसों में लगाम किसके हाथ में रहे. ■

“रियाज अलग है, परफॉर्मेंस अलग”

गेट्टी इमेजेज

राजेश गनोदवाले

‘‘बरखा बोलो बरखा, बरका नहीं.’’ अगले महीने 53 साल के होने जा रहे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज उस्ताद राशिद खान फेसबुक लाइव में शिष्यों की गलतियां इसी तरह पकड़ते-सुधारते चल रहे हैं. कभी तानपुरा बढ़वा लेना, और कभी तबले का साउंड मन मुताबिक मांगना. बीच-बीच में वे शिष्यों को सचेत भी करते हैं: ‘‘तुम लोग सुस्त मत हो जाओ. हर तरह के सुनने वाले होते हैं. उनसे कनेक्ट होना है. खुल कर गाना बजाना करो.’’ आगे भी वे इसी तरह से गुर दिए जाते हैं: ‘‘यही मान लो कि सामने बैठे हैं. तय कर लो, महीने में एक बार वर्चुअली हम मिलते रहेंगे. तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो. समय मिला है तो जमकर रियाज मारो. लॉकडाउन का फायदा लो.’’

लंबे लॉकडाउन के चलते कोलकाता के अपने ठिकाने से उनका भी कहीं आना-जाना बंद ही है. ऐसे में वे अपनी राशिद खां अकादमी: द फिफ्थ नोट ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के फेसबुक पेज के जरिए पिछले हफ्ते शिष्यों की तैयारी की खोजखबर भी ले रहे थे. शिष्य घरों में होते हुए भी गुरु के सामने थे. सम्मिलित विद्यार्थियों की क्लास रूम वाली रंजकता शुरू हो चुकी थी. आपस में चुहलबाजी भी चल रही थी. घंटे भर से कुछ अधिक चले संवाद में शिष्य गद्गद थे तो गुरु भी तरोताजा नजर आए.

रामपुर सहसवान घराने के राशिद खान यानी आवाज और अंदाज से खयाल गायिकी में मिजाजदारी का नया रंग भरने वाली देश की बड़ी उस्ताद हस्ती. कोरोना काल में वे संगीत की बड़ी हस्तियों में बिरले ही हैं जो शिष्यों की सुध लेते दिखे. इस माध्यम के लिए उन्होंने खुद को भी ट्यून किया है. इसका अंदाजा उनकी सहज लाइव शैली से भी लगा. कानों में ईयर फोन, काली टी शर्ट! पहचानना कठिन कि स्वाधीनता के बाद पैदा हुई पीढ़ी से निकला यही वह दिग्गज गवैया है जिसकी उस्तादाना गायिकी ने संगीतप्रेमियों को दीवाना बना रखा है. लाइव आने वाले तो अपनी सुदर्शनता को लेकर अकारण चौकस मिलते हैं. लेकिन वे बेतकल्लुफ, शुद्ध गुरु की भूमिका में.

यह लाइव कायदे से था तो अपने ही शिष्यों के लिए. लेकिन सधे हुए उत्तर दूसरों के लिए भी कुंजी हैं. जैसे: ‘‘गाना सीख लेने से ही कुछ नहीं होता. तुम्हें चौमुखा होना पड़ेगा.’’ दुराव-छिपाव से बेखबर वे खयाल में उतरने की चाबी दिए जा रहे थे वे. उन्हीं के शब्दों में, ‘‘अकादमी की यह सोच थी कि वर्चुअल चौपाल के सहारे ही गुरु शिष्य की आपसदारी हो.’’

व्यस्त श्रेणी वाले बड़े गवैये अगर महफिलों में न हों तो अमूमन उनकी बहुरंगी व्यस्तताएं होती है. फिर राशिद खान तो वह शख्सियत हैं जिनके नाम पर टिकट आसानी से बिकते हैं. संगीत का या कोई भी सांस्कृतिक समारोह हो, जिस दिन उनकी पेशकश रहे, उस रोज की गहमागहमी का आलम कह देता है कि आज कुछ खास है! स्टार दर्जा भले 21 वीं शताब्दी में मिला हो लेकिन उनकी आवाज और रागों के साथ गले से किया जाने वाला ट्रीटमेंट देखकर जानकार उनके नाम पर ठिठक जाते रहे हैं. वे घटनाओं और ताजा हालात से अपडेट रहने वाले कलाकारों में हैं.

उन्हें कोलकाता फोन करने पर उस्ताद तुरंत पूछते हैं कि ''कोलकाता तो फिलहाल पूरी तरह बंद है पर रायपुर के हाल कैसे हैं?'' आइटीसी के संयोजन में करीब डेढ़ दशक पहले वे रायपुर आए थे. उन्हें उसकी याद थी. इतने लंबे फासले को लेकर उन्होंने इसरार भी किया और कहा कि ''बताइए! 15 साल हो गए होंगे मुझे आए हुए. इसे (शास्त्रीय संगीत को) बढ़ावा नहीं मिलना अच्छी बात नहीं. आप लोग क्यों नहीं बात उठाते?''

खैर. शिष्यों के साथ उनके लाइव का, उन्हीं के शब्दों में, निचोड़ था: ''रियाज अलग है, परफॉर्मेंस अलग.''

आइए, अब उनसे संगीत के कुछ दूसरे पहलुओं पर हुई बातचीत का रस लें.

● आप उनमें से हैं जिनके नाम के आगे के उस्ताद श्रोताओं ने इतने कम समय में स्वीकार कर लिया. आप अपनी गायिकी से उस्ताद हैं ही, ये अलग बात है.

इस प्यार पर क्या कहूं. लेकिन मैं अपने आप को हमेशा सिखाने की कोशिश करता हूँ! हर महफिल मेरे लिए एक चैलेंज बन कर आती है और वही राग मुझे अगली बार फिर चुनौती देता हुआ दिखता है.

● परिवार में कौन है आपकी विरासत को आगे ले जाने वाला?

बेटा है अरमान (खान), कोशिश कर रहा है. मैं अपने शिष्यों और परिवार में कोई फर्क नहीं देखता. सभी को एक नजर से देखता हूं. सभी हमारे बच्चे जैसे हैं. समान रूप से सीखते हैं. वही सबक बाकियों को भी मिलता है जो बेटा गाता है. इसमें तो जो करेगा वही पाएगा. मिजाज सबका अलग होता है. कोई तैयारी पसंद करता है कोई स्वभावत: सुरीला बना हुआ आता है.

● आज खयाल गायिकी के नाम पर गलेबाजी सुनाई जाती है. गला कंप्यूटर की तरह तो चलता है लेकिन गहराई, सुकून गायब है. ताज्जुब है कि जानकार परिवार के गायक भी ऐसी भूल करते हैं. अजीब नहीं है?

गले को कंप्यूटर? सही है [हंसते हैं वे]. देखो दौड़-भाग से गाना नहीं आता. तैयारी का मुकाम कहां तक हो और सुरों का मजा लेकर गाना, दोनों अलग हैं. उम्र भी एक कारण है. नौजवानी में कभी मैं भी गले की फिरत में खो जाता था! बच्चे हैं, ऊपरवाला चाहेगा तो आस्ते—आस्ते उनमें भी रूहदारी आ जाएगी. लेकिन बिना चैनदारी के गाना असर नहीं करता, इसमें जरा भी शक नहीं. आप जितना चाहे गले का सर्कस दिखाते रहिए.

● इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा आपको पसंद है?

देखिए, 1998 तक मैं जहां भी जाता था, बड़े तानपुरे पैक होकर साथ जाते थे. लोग उसे ताबूत मानकर देखते थे. दिक्कत उसकी सुरक्षा है. सफर में कितना संभालें. इलेक्ट्रॉनिक भी अच्छे हैं. जिन लोगों ने यह तकनीक ईजाद की उनका शुक्रिया. लेकिन मैनुअल का मुकाबला हो नहीं सकता. उसके गूंज की बात ही नायाब है. दो तानपुरों के मध्य बैठा गवैया, (यह) कितना असर करता है इसको पहचानने वाला समय अब पीछे छूटता जा रहा है.

● इसे आप क्या ठीक मानते हैं कि आकाशवाणी में तो कलाकार सुबह, दोपहर और रात के राग एक बैठक में बजा—गा देते हैं. लेकिन महफिल में फरमाइश उठे तो वहां नियमों का हवाला देते हैं कि अभी इस राग का समय कहां?

असल में सुबह, दोपहर और शाम अलग-अलग जाकर गाना व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं. सिद्ध कलाकार आकाशवाणी स्टुडियो में अपना टेंपरामेंट बनाकर उस समय में प्रवेश कर लेते हैं, इसीलिए वो नतीजा मिलता है.

● लेकिन सुबह और दोपहर के समारोह होते भी कहां हैं! तो इन पहर के रागों को नई पीढ़ी याद कैसे रखेगी?

मैं मानता हूं दिन के या दोपहर के राग सुनाई नहीं आते. कामकाजी युग है. इसमें दोनों ओर से हाथ उठना चाहिए. ऐसी महफिलें करवाने वाले भी आएं और सुनने वाले भी. चलिए, मैं आप से पूछता हूं, आप आएंगे अपना काम छोड़कर?

''मैं मानता हूं कि दोपहर के राग सुनाई नहीं आते. यह कामकाजी युग है. ऐसी महफिलें करवाने वाले भी तो आगे आएं और सुनने वाले भी. आपसे पूछता हूं, आप आएंगे अपना काम छोड़कर?''

● 'सुरमंडल' कम लोगों को सूट होता है. बड़े गुलाम अली के बाद पंडित जगदीश ने जिस तरह इसे बरता वो मिसाल बना. अब आपके हाथों में यह खिलता है. किसी शिष्य ने इस बारे में कोई सवाल किया?

किसी ने नहीं पूछा. बड़े गुलाम अली इसे इंडियन क्लासिकल में लाए, यह उनकी बड़ी सोच थी. और जगदीश प्रसाद जी तो यकीनन इसके साथ न्याय करते थे. असल में इसे लेना इतना आसान नहीं. एक-एक सुर की बढ़त सीखनी पड़ती है. इससे एक मजा, मिजाज तो बनता है. जबकि लोग इसे ऐसा छेड़ते हैं कि सुरमंडल खुद दुखी हो जाता है. ■

मौके पर भरी उड़ान

नवीन कुमार

महामारी के बीच सिनेमाघरों के सफेद परदे पर जमती धूल के बीच कुछ ऐक्टर्स जहां अच्छे दिनों का इंतजार करने के पक्ष में हैं तो कुछ मौके पे उड़ान भरने की तलाश में हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म उन्हें पंख भी मुहैया करा रहे हैं. बड़े ऐक्टर्स और बड़े बजट को छोड़ दें तो छोटी फिल्मों और छोटे परदे के ऐक्टर्स को यहां अच्छे मौके मिल रहे हैं. वेबसीरीज बनाने वाले भी सेक्स और हिंसा के भारी तड़के के साथ इसे खूब दुह रहे हैं. इस तरह के कंटेंट में कई अभिनेत्रियों की सहजता ने उनके हौसले बुलंद कर रखे हैं. उन्हें दर्शक जो मिल रहे हैं. *मिर्जापुर* की बीना त्रिपाठी (अमेजन प्राइम) और *आउट ऑफ लव* की डॉक्टर मीरा कपूर (डिज्नी प्लस हॉटस्टार) के रूप में रसिका दुग्गल, *ए सूटेबल बॉय* की मीनाक्षी मेहरा और *बॉम्बे बेगम्स* (दोनों नेटफ्लिक्स पर) की फातिमा वारसी के रूप में शहाना गोस्वामी *आश्रम* की बबीता के रोल में त्रिधा चौधरी और *बिसात: खेल शतरंज का* (दोनों एमएक्स प्लेयर पर) में डॉक्टर कियाना वर्मा के रोल में संदीपा धर सरीखी अभिनेत्रियों ने साहसिक अभिनय से प्रतिबद्ध दर्शक तैयार किए हैं. इसके उलट श्वेता त्रिपाठी शर्मा, अमिका शैल, रूमाना मोला सहित कई और अभिनेत्रियां हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिनय की उड़ान भरने की कवायद में हैं.

मसान गर्ल श्वेता *मिर्जापुर* में रसिका दुग्गल के मुकाबले डटी थीं. अपने अभिनय के बल पर गोलू गुप्ता के किरदार को जीवंत रखते हुए उन्होंने पहचान बना ली. *मिर्जापुर-3* में भी वे नए अंदाज में दिखेंगी. इस समय उनके पास आधा दर्जन प्रोजेक्ट हैं. बकौल श्वेता, ''मिर्जापुर मेरे करियर के लिए टर्निंग पॉइंट है. इसमें पहली बार खुद को होर्डिंग/पोस्टर्स पर देखा.'' *हरामखोर* और *मसान* जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकीं श्वेता बताती हैं, ''मिर्जापुर के दो एपिसोड पढ़ने के बाद ही तय कर लिया था कि मुझे गोलू के रूप में इस दुनिया का हिस्सा होना है. हालांकि उसकी और मेरी जिंदगी में कुछ भी समान नहीं. मेरी कोशिश भी रहती है कि किरदार मुझसे जितने अलग हों, उतना ही मजा आएगा. बतौर ऐक्टर एक ही लाइफ में अलग-अलग लाइफ जीने को मिल रहे हैं. इसका आनंद ही कुछ और है.'' उनका मानना है कि वेबसीरीज में काम करने का अलग मजा है क्योंकि कहानी 8-10 घंटे तक की भी होती है. इसे बिहार के किसी गांव में बैठा दर्शक भी देख पाता है.

वे खुद को खुशकिस्मत मानती हैं कि उन्हें अभिनय के बल पर फिल्में और वेबसीरीज में काम का मौका मिल रहा है. *अपहरण* वेबसीरीज निर्माता-निर्देशक सिद्धार्थ सेनगुप्ता ने नेटफ्लिक्स के शो *ये काली काली आंखें* में श्वेता को साइन करने से पहले उनकी *हरामखोर* देखी थी. श्वेता बताती हैं, ''इमोशनल जर्नी के साथ इसमें प्यार के जुनून वाला मेरा कैरेक्टर है. मसान के बाद ऐसे कैरेक्टर के लिए मैं तरस रही थी.'' लॉकडाउन के दौरान श्वेता ने खुद को सोशल मीडिया से दूर रखा. लॉकडाउन हटने के बाद वे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए शो *एस्केप लाइव*, वूट के लिए शो *द गॉन गेम-2* की शूटिंग करने वाली हैं.

उधर सारेगामापा फेम अमिका शैल की एक के बाद एक तीन वेबसीरीज रिलीज होने जा रही हैं. डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर *छत्तीस और मैना* आ चुकी है और उनका मानना है कि इससे उनका भविष्य संवर जाएगा. वे सात साल पहले कोलकाता से मुंबई आई थीं गायिका बनने. उसमें कामयाबी न मिलने पर पिछले दो साल से ऐक्टिंग में किस्मत आजमा रही हैं. ओटीटी और लॉकडाउन ऐसे में उनके लिए वरदान बन गए. वे *मिर्जापुर-2* में बार सिंगर और अक्षय कुमार की *लक्ष्मी* में विलेन के भाई की गर्लफ्रेंड जैसे छोटे रोल करने को इसलिए राजी हुईं जिससे कि उन्हें आगे भी काम मिले. श्रद्धा पासी के निर्देशन वाले वेब शो *छत्तीस और मैना* में संदीपा धर लीड में तो अमिका सेकंड लीड में हैं. यह गांवों में नाचने वाली नचनिया के जीवन पर आधारित है. अमिका सफाई में कहती हैं कि यह फैमिली ड्रामा है और गंदे सीन नहीं है. नचनिया पर उन्होंने इसी नाम से एक और शो किया है जिसमें वो लीड में हैं. यह तमाशा प्लेटफॉर्म के लिए है. *वीडियो कॉल* नाम की एक और वेब सीरीज वे भूत का भी रोल कर रही हैं. ऑल्ट बालाजी के शो *गंदी बात-5* से अमिका ने डिजिटल पर शुरुआत की थी. वे बताती हैं, ''इसमें मैंने जो अंतरंग दृश्य दिए उतने तो फिल्मों में होते हैं.'' अमिका अच्छे अभिनय से पैसे कमाना चाहती हैं न कि बोल्ड सीन देकर. उन्होंने बोल्ड सीन के लिए अपनी लक्ष्मण रेखा तय कर रखी है: ''जितना सहज है उतना ही करना है.'' वे अपने करियर से खुश हैं. नचनिया सीरीज में उन्होंने *नशीली हूं मै कंटीली हूं मैं..* गाना भी गाया है तो *गंदी बात* का टाइटल ट्रैक भी.

इसी तरह से मौका हथियाने वालों में अमेरिका में जन्मीं और बेल्जियम में पली बढ़ीं भारतीय मूल की बंगाली रूमाना मोला भी हैं.

श्वेता त्रिपाठी शर्मा (दाएं) और अमिका शैल सरीखी अभिनेत्रियों ने पिछले 2-3 साल में अपनी प्रतिभा के बूते ठोस जगह बनाई है

उनकी हिंदी अच्छी है. रुमाना छह महीने के लिए मुंबई आई थीं. ''सोचा था, इस दौरान काम मिला तो ठीक, वर्ना लौट जाऊंगी. इस दौरान उन्हें पोगो के लिए एंकरिंग का एक काम मिल गया.'' बाद में उन्हें कुछ मौके मिले पर कारगर नहीं रहे. उन्होंने धैर्य रखा. लव रंजन ने उन्हें *प्यार का पंचनामा–2* में मौका दिया. अपर्णा सिंह की *इरादा* उनकी दूसरी फिल्म थी, जिसमें नसीरुद्दीन शाह की बेटी का रोल करने के लिए सिर मुड़वाना भी कुबूल किया. फिर उन्हें पहली वेबसीरीज *लाइफ सही है* में काम मिला. वे फिल्म *बावरी छोरी* के अलावा वेबसीरीज *देव डीडी–2* और *वर्जिन भानुप्रिया* में भी प्रतिभा दिखा चुकी हैं. निखिल अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म *जिंदगी तीन दिन* में भी वे दिखेंगी. इसके अलावा *द गेम ऑफ सक्सेस* वेब शो में लीड रोल निभा रही हैं. यह क्रिकेट पर आधारित शो है. इस महमारी के दौरान जिस तरह से वेब सीरीज में ऐक्टर्स को काम करने का मौका मिल रहा है, रुमाना उसे सकारात्मक रूप में देख रही हैं. वे कहती हैं, ''लॉकडाउन के दौरान हमें इसकी अहमियत समझ आई.'' मौके पर काम लपकना हर कलाकार के लिए फायदेमंद है. तभी तो ऊंची उड़ान भर पाएंगे. ■

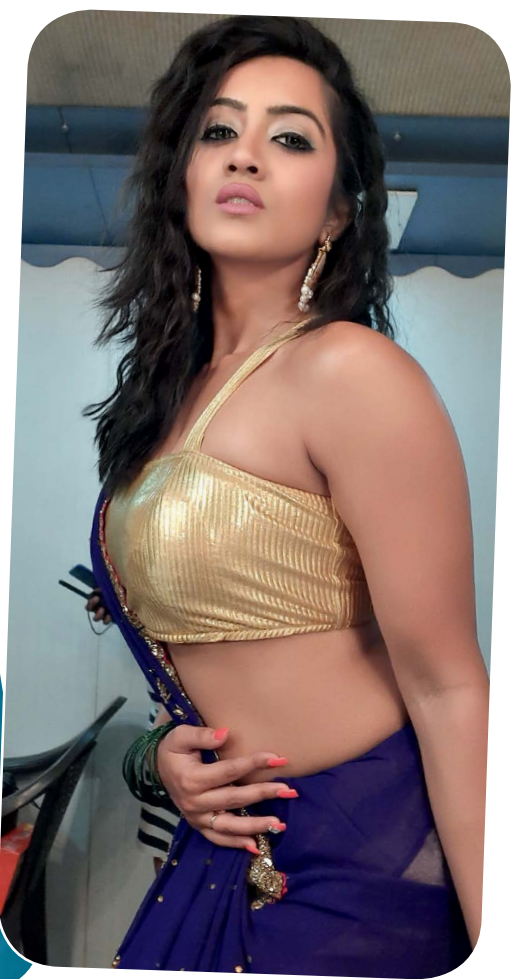

किताबें

नींद के इर्द-गिर्द

देवेंद्र राज अंकुर

दिल्ली में नींद
लेखकः **उमाशंकर चौधरी**
प्रकाशकः **राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली**
कीमतः **160 रुपए**

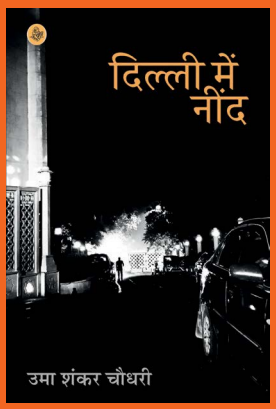

आज से दस-बारह साल पहले उमाशंकर चौधरी का पहला कहानी संग्रह *अयोध्या बाबू सनक गए हैं* प्रकाशित हुआ था और उन्होंने कहानी को कहने के एक नए अंदाज से बहुत उम्मीदें जगाई थीं. संग्रह में आने से पहले ही *अयोध्या बाबू सनक गए हैं* को मैंने एक पुरस्कार योजना के तहत पहला स्थान दिया था. बाद में हम लोगों ने उसका नाट्यमंचन भी किया और उसके बहुत सारे शो किए थे.

कुछ सालों के बाद उनका दूसरा संग्रह *कट टू दिल्ली और अन्य कहानियां* आया और वह उम्मीद बरकरार रही जो पहले संग्रह से बनी थी. अब इधर उनका तीसरा संग्रह छप कर आया है *दिल्ली में नींद*. इस संग्रह में चार कहानियां हैं और हर कहानी बहुत लंबी है. कुल जमा 160 पृष्ठ में चार कहानियां यानि हर कहानी की औसत लंबाई चालीस पृष्ठ. इसके बावजूद जब हम इन कहानियों को पढ़ना शुरू करते हैं तो हर कहानी आपको भीतर तक झकझोर कर रख देती है.

बेशक संग्रह की एक कहानी का शीर्षक है *दिल्ली में नींद* लेकिन गहराई से देखा जाए तो नींद हर कहानी के केंद्र में है. पहली ही कहानी है *कहीं कुछ हुआ है इसकी खबर किसी को न थी*. एक बड़े शहर के एक मुहल्ले में एक परिवार का सारा कीमती सामान लूटे जाने की घटना हो जाती है और आसपास रहने वालों को पता भी नहीं चलता अर्थात् दीन दुनिया से बेखबर सब अपने में मस्त सोते रहे और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई. *दिल्ली में नींद* कहानी में एक महानगर में धीरे-धीरे बढ़ते औद्योगिकीकरण और ध्वनि प्रदूषण से उसके मुख्य पात्र को नींद नहीं आती. एक और कहानी *नरम घास, चिड़िया और नींद में मछलियां* का मुख्य पात्र पर्यावरण को लेकर इतना सजग और सचेत है कि वह नींद में भी उसे लेकर बड़बड़ाता रहता है.

सिर्फ नींद ही नहीं, कुछ और बातें भी सब कहानियों में एक समान दिखाई पड़ती हैं. हर कहानी में गांव से शहर तक की यात्रा है लेकिन उसके अलग अलग रूप सामने आते हैं. एक में मुख्य पात्र वासुकी बाबू को प्रमोशन के तहत गांव से कानपुर जैसे बड़े शहर में जाना पड़ता है, जहां एक रात परिवार की अनुपस्थिति में घर का सारा सामान चोरी हो जाता है. *कंपनी राजेश्वर सिंह का दुख* में बड़ा भाई नर्मदेश्वर अपाहिज होते हुए पढ़ाई के लिए शहर की ओर प्रस्थान करता है और एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचता है. *दिल्ली में नींद* का चारूदत्त सुनानी एक प्राइवेट गैराज में मैकेनिक है और यहां के ध्वनि प्रदूषण का शिकार बनता है. *नरम घास...*के फुच्चू मास्साब गांव से इलाज के लिए अपने बेटे के पास दिल्ली आते हैं और घास, चिड़िया और मछलियों को बचाने के क्रम में पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं. इस रूप में वे अयोध्या बाबू की याद दिलाते हैं.

हर कहानी में कहानीकार ने हर बार एक ही परिवार को केंद्र में रखा है लेकिन उससे जुड़े हर ब्यौरे को इतनी सूक्ष्मता में साकार किया है कि ये सभी पात्र हमारे सामने जीवंत हो उठते हैं. लगता है कि लेखक इन पात्रों से कहीं गहरे में परिचित है. एक तरफ एक बुजुर्ग पीढ़ी है और दूसरी तरफ एक जवान पीढ़ी और इन दोनों के बीच का वैचारिक द्वंद्व भी इन कहानियों में प्रायः मुखर हो उठता है. यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी तरफ रचनाकार बार-बार लौटता रहा है.

मजे की बात यह है कि हर कहानी का परिवेश यथार्थवादी तेवर लिए हुए है लेकिन वे उस परिवेश के भीतर इतने गहरे तक उतर जाते हैं कि वह अतियाथार्थवादी लगने लगता है जिसे अंग्रेजी में 'सरियलिज्म' कहा जाता है. पूरी तरह से प्रयोगशील होने के बावजूद ये कहानियां किस्सागोई के अपने अंदाज से भरपूर हैं–यही वह गुण है जो उमाशंकर चौधरी को अपने समकालीन लेखकों में एक अलग पहचान देता है. ■

सवाल+जवाब

‘सब कुछ करना चाहता हूं मैं’

अभिनेता **अर्जुन कपूर** बंधा-बंधाया ढांचा तोड़ने, ‘न्यू नॉर्मल’ माहौल में शूटिंग करने और अपनी ताजा फिल्म *संदीप और पिंकी फरार* के बारे में

बंदीप सिंह

***संदीप और पिंकी फरार* की सिनेमाघरों में रिलीज का रास्ता बन नहीं पाया, आखिरकार अमेजन प्राइम वीडियो पर उसने दर्शक जुटाए. शुरू में ही ओटीटी पर जाने को नहीं सोचा था?**

निर्माता/निर्देशक बड़े परदे पर इसकी रिलीज चाहते थे पर उसके लिए सही माहौल चाहिए था, जो कि मिल नहीं पाया. मार्च 2020 में हम इसे रिलीज करने जा ही रहे थे कि लॉकडाउन लग गया. फिर हमने इस साल मार्च में इसे रिलीज करने का कार्यक्रम तय किया कि तभी कोविड की दूसरी लहर आ पहुंची.

हाल की आपकी फिल्मों के चुनाव को देखें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि आप सायास बंधे-बंधाए ढांचे को तोड़ते हुए हर तरह की फिल्में करना चाहते हैं?

मैं सब कुछ करना चाहता हूं. मुझे अनीस बज्मी की *मुबारकां* भी करने में मजा आया और दिवाकर बनर्जी की *संदीप और पिंकी*...भी. मैं बस दिल की सुनता हूं, और जब आप अपने मेनस्ट्रीम हीरो होने की बनाई गई हवा में यकीन करने लगें तो कई बार यह मुश्किल हो जाता है. ओटीटी के साथ क्वालिटी पर आत्ममंथन तो हो रहा है. मेनस्ट्रीम फिल्म करते वक्त हम दर्शकों को हल्के में लेकर कच्ची-पक्की फिल्म नहीं परोस सकते.

आपने पिछले साल कोविड से उबरने के बाद ठीकठाक काम निकाला. ‘न्यू नॉर्मल’ में शूटिंग कितनी मुश्किल है?

जब मैं *सरदार का ग्रैंडसन* पूरी करने गया तो देखा कि हालत काफी नाजुक है...आपको खुद अपना कंफर्ट जोन तलाशना है. *भूत पुलिस* के लिए खुशकिस्मती से हम लोग पहाड़ों पर और एक बबल में थे. कम लोगों से संपर्क में रहने के अलावा सफर भी कम करना होता था. लेकिन *एक विलेन* (2021) के दौरान चारों ओर कोविड से दम तोड़ते लोगों को देखकर गहरा सदमा-सा लगा.

आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री जल्दी ऐक्शन में आ पाएगी?

आप काम पर लौटना चाहते हैं, इसमें संवेदनहीनता जैसी कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ताक पर रखकर आप यह मान लें कि काम करना आपका अधिकार है, तब यह जरूर संवेदनहीनता होगी. हमें सबको ध्यान में रखकर समाधान खोजना होगा. ठीक है कि हमें फिल्में बनानी हैं पर हम इन्हें दिखाएंगे कहां? हमें यह पहलू ध्यान में रखना होगा कि दर्शक इन्हें सिनेमाघरों में और नहीं तो कम से कम घर पर ही देखना चाहते हैं.

–सुहानी सिंह

AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM
DEEMED TO BE UNIVERSITY

School of Engineering

AMRITAPURI • BENGALURU • CHENNAI • COIMBATORE

DISHA

THE CAREER CONCLAVE 2021

5 DAYS CAREER ENRICHING SESSIONS

NEXT SESSION BEGINS AT THE END OF JUNE

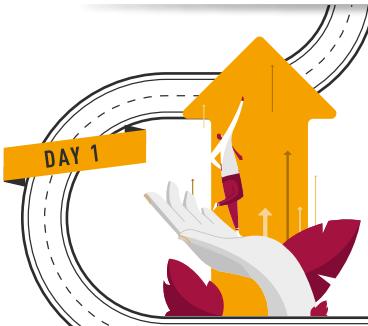

DAY 1

21ST CENTURY SKILLS AND PSYCHOMETRIC TESTS FOR EFFECTIVE CAREER PLANNING

CHANGING FACE OF ENGINEERING CAREERS

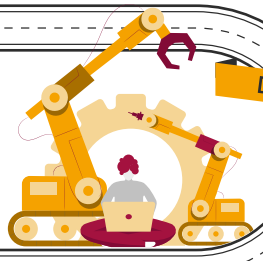

DAY 2

DAY 3

FUTURISTIC ENGINEERING BRANCHES

HIGHER EDUCATION ABROAD AFTER ENGINEERING

DAY 4

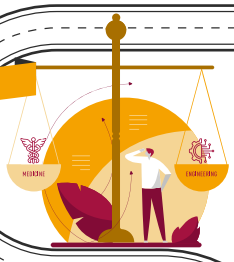

DAY 5

ARE ENGINEERING AND MEDICINE THE ONLY OPTIONS?

DF-Amrita-023

For more information, visit amrita.edu/disha or email: disha@cb.amrita.edu

Flexible Admission Process for Futuristic B.Tech Programmes

Applications Open for B.Tech

AEEE 2021 | JEE MAIN 2021 | SAT | PUEE

+91 94437 97777

amrita.edu/btech

Scan Here

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE